चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

www.chauthiduniya.com

इसमें ग़रीबों के लिए कुछ भी नहीं है

पेज-3

वामपंथ का भविष्य तय हो जाएगा

पेज-5

दाग़ी मंत्री जनादेश का अपमान

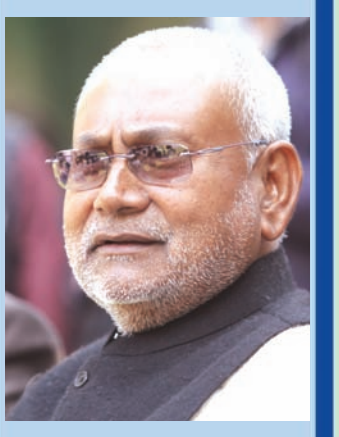

पेज-7

विश्व के प्रमुख तानाशाह

पेज-11

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 14 मार्च–20 मार्च 2011 | मूल्य 5 रुपये

कांग्रेस और रामदेव आमने-सामने

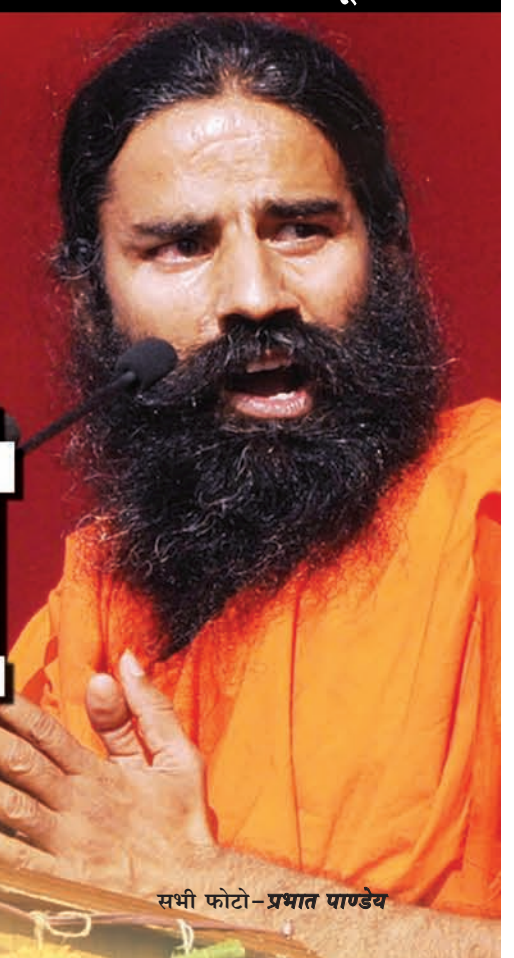

सभी फोटो– *प्रभात पाण्डेय*

कांग्रेस पार्टी और सरकार पर बाबा रामदेव और उनके साथियों के आरोप

- काला धन जमा कराने वालों में केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख और सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल का नाम
- स्विस बैंकों में पैसा जमा करने वाले माफ़िया हसन अली के कांग्रेस पार्टी से रिश्ते
- क्वात्रोकी के बेटे को अंडमान निकोबार में तेल की खुदाई का ठेका दिया गया
- स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में स्वर्गीय राजीव गांधी का काला धन जमा था
- राहुल गांधी को रूस की ख़ुफ़िया एजेंसी पैसे देती है

कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पर उक्त आरोप बाबा रामदेव की स्वाभिमान रैली में लगाए गए. बाबा रामदेव और उनके साथी इन आरोपों के सबूत देश की जनता के सामने पेश करें और सरकार एवं कांग्रेस पार्टी इन आरोपों पर अपनी सफाई दे. देश की जनता को सच्चाई जानने का अधिकार है.

मनीष कुमार

भारत की राजनीति का यह अजीबोग़रीब दौर है. संत राजनीति कर रहे हैं और राजनीतिक दल संतों की तरह बर्ताव कर रहे हैं. संत से मतलब मौन धारण करना है. ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि किसी पार्टी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, देश भर में रैलियां करके राजनेताओं के ख़िलाफ़ आग उगली जा रही है और देश चलाने वाली पार्टी चुप्पी साधकर सब कुछ सुन कर रही है. बीती 27 फ़रवरी को दिल्ली का रामलीला मैदान खचाखच भरा था. पूरे देश भर से लोग भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ एक रैली में शामिल होने आए थे. दर्जनों टीवी चैनलों और अख़बारों के संवाददाताओं की भरमार थी. यह रैली योग गुरु बाबा रामदेव ने बुलाई थी. मंच पर हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे. अन्ना हज़ारे, किरण बेदी एवं केजरीवाल जैसे लोग भी थे, जो हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आंदोलन के चेहरे हैं. कुछ ऐसे चेहरे भी थे, जो अपने बयानों से सनसनी फैलाने में माहिर हैं. इतनी बड़ी रैली, इतने बड़े–बड़े लोग भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ बाबा रामदेव की मुहिम में शामिल हुए. सबको बोलने का मौक़ा दिया गया. हैरानी की बात यह है कि इस विशाल रैली में क्या हुआ, यह मीडिया से पूरी तरह ग़ायब रहा. बाबा रामदेव की वजह से यह रैली एक धार्मिक चैनल आस्था पर दिन भर लाइव दिखाई गई. पहला सवाल तो यही उठता है कि मीडिया ने इस रैली और इसमें लगे आरोपों को महत्व क्यों नहीं दिया.

इस रैली में सबसे सनसनीख़ेज़ भाषण पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर विश्वबंधु गुप्ता ने दिया. उन्होंने वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी को अपशब्द कहे, कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं का नाम लिया और सोनिया गांधी एवं उनके राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल पर तीखी टिप्पणी की. विश्वबंधु गुप्ता ने सबसे पहला प्रहार प्रणव मुखर्जी पर किया. उन्होंने कहा– ***मैं आपको बताता हूं कि पिछले छह सालों में किस तरह देश से धोखा किया गया. यह ऐसी कहानी है, जो आपको चौंका देगी. मैं प्रणव मुखर्जी से मिला, जो कि भारत के वित्त मंत्री हैं. मैंने कहा, मिनिस्टर साहब, स्विट्जरलैंड में हमारे लोगों का 70 लाख करोड़ रुपया पड़ा हुआ है. आप उसको लाने के लिए क़ानून क्यों नहीं लाते. बोले (प्रणव मुखर्जी), विश्वबंधु, तुमको मालूम नहीं है कि स्विट्जरलैंड के भी क़ानून हैं. उस क़ानून के अंदर न वे नाम बताएंगे, न पैसे देंगे. मैं सुनता रहा. एक हिजड़े की बात सुनता रहा. मन में आया कि मेरे मां–बाप अंग्रेज़ों से आज़ादी की लड़ाई में जेल गए थे...यह हिजड़ा यहां बैठा क्या कर रहा है. न सिर्फ़ वह हिजड़ा है, बल्कि वह झूठा भी है. हर बार पार्लियामेंट में झूठ बोलता है.***

प्रणव मुखर्जी पर विश्वबंधु का कोई आरोप नहीं है, कोई ख़ुलासा नहीं किया, फिर भी उन्हें अपशब्द कहे. बाबा रामदेव वहां बैठे मुस्करा रहे थे और लोग तालियां बजा रहे थे. हालांकि उन्होंने केंद्र सरकार पर एक ऐसा आरोप लगाया, जिससे जनता सन्न रह गई. उन्होंने कहा– ***एक बात और करना चाहता हूं. क्वात्रोकी छुपे बैठे हैं. उनका एक बेटा है मलिस्मा या मलुस्मा. सारे काग़ज़ात मेरे पास हैं. मैं कमिश्नर रहा हूं, बिना काग़ज़ात के कुछ भी नहीं बोलता. मलुस्मा ने 2005 में अंडमान निकोबार में तेल की खुदाई का ठेका लिया. इस सरकार के अंदर लिया. जिस क्वात्रोकी को स्वामी जी कहते हैं ढूंढ़ो, इटली की सबसे बड़ी रैकेटियर कंपनी ईएनआई इंडिया लिमिटेड के नाम से खोला गया उसके बेटे का दफ्तर मेरिडियन होटल के अंदर है. चलो वहीं चलकर उसे तोड़ देते हैं. यह मामला अभी तक न मीडिया की नज़र में और न ही संसद की नज़र में आया है.*** यह आरोप सचमुच चौंकाने वाला है. अगर विश्वबंधु गुप्ता के इस आरोप में सच्चाई है तो इसकी जांच हो और अगर यह झूठ है तो केंद्र सरकार और कांग्रेस पार्टी को उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए.

मज़े की बात यह है कि इस भाषण में वह यह दावा भी कर रहे थे कि आज का भाषण प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी सुनेंगे, सारे भ्रष्ट नेता सुनेंगे. उन्हें पता है कि विश्वबंधु गुप्ता क्या है. आज मैं अपनी बात और आपकी बात वहां पहुंचाने के लिए एक–एक चीज़ का ख़ुलासा कर दूंगा. इसके बाद उन्होंने स्विस बैंक के बारे में एक और जानकारी दी. उन्होंने कहा– ***2005 में स्विस बैंकर्स एसोसिएशन ने एक चिट्ठी लिखी सरकार को कि हम आपके देश में आना चाहते हैं. 2007 में वही बैंकर्स, जिनके पास सत्तर लाख करोड़ रखा हुआ है, वे दिल्ली आए. उनकी फोटो हैं हमारे पास. उन्होंने कहा कि हमें हिंदुस्तान में स्विट्जरलैंड के बैंक खोलने दिए जाएं. हमको दुनिया का लूटा हुआ पैसा बंबई की स्टॉक मार्केट में लगाने दिया जाए. शर्म की बात है...चिदंबरम साहब से मैं जवाब मांगता हूं. 2007 में स्विस बैंक को आज़ादी दी गई स्टॉक मार्केट में सट्टा खेलने की. 2005 में भारत में***

(शेष पृष्ठ 2 पर)

> क्वात्रोकी छुपे बैठे हैं. उनका एक बेटा है मलिस्मा या मलुस्मा. मलुस्मा ने 2005 में अंडमान निकोबार में तेल की खुदाई का ठेका लिया. इस सरकार के अंदर लिया. इटली की सबसे बड़ी रैकेटियर कंपनी ईएनआई इंडिया लिमिटेड के नाम से खोला गया उसके बेटे का दफ्तर मेरिडियन होटल के अंदर है. चलो वहीं चलकर उसे तोड़ देते हैं
>
> -विश्वबंधु गुप्ता

> सरकार और पार्टी इस पाप के लिए क्षमा मांगना तो दूर, उल्टा हिसाब मांगती है. अब तो देश की जनता हिसाब मांगेगी कि तुमने कितना देश को लूटा है. आज तो प्रधानमंत्री ने समय नहीं दिया, मैं तो समय मांगता रहूंगा. अगर समय नहीं दिया तो उनका भी समय पूरा हो जाएगा. वह सलामत रहें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बेईमान लोगों से घिरे ईमानदार व्यक्ति हैं. आज तक की सबसे बेईमान सरकार के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री का तमगा उन्हें मिला है.
>
> -बाबा रामदेव

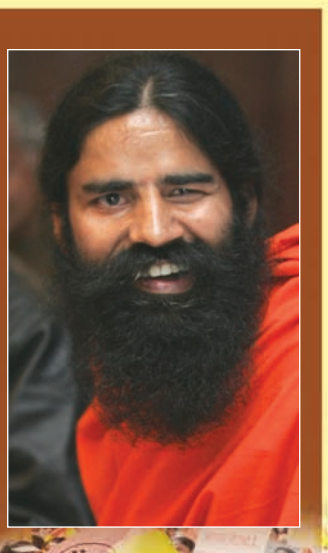

> स्विट्ज़रलैंड के एक अख़बार, जिसका नाम था इलस्ट्रेटेड, ने दुनिया के 14 बड़े गुनहगारों और डाकुओं का ज़िक्र उनकी तस्वीरों के साथ अपने एक पर्चे में किया था. उन 14 गुंडों और बदमाशों के बीच में एक हिंदुस्तानी भी था. वह हिंदुस्तानी हमारे देश का पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी था. उसकी तस्वीर के बाजू में कई मिलियन डॉलर लिखे हुए थे, जो स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में जमा थे.
>
> -राम जेठमलानी

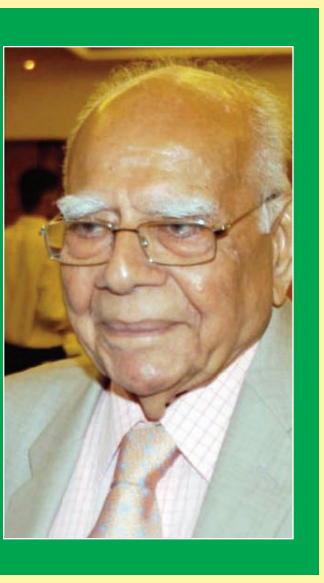

जयराम रमेश ने एक कमेटी गठित की है, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य एन सी सक्सेना को सौंपी गई है.

दिल्ली का बाबू

अवज्ञा की सज़ा

हिमाचल प्रदेश में एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनीषा श्रीधर पर लगे अवज्ञा के आरोप का मुद्दा इन दिनों यहां के बाबुओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. राज्य सरकार ने 1984 बैच की इस अधिकारी के ख़िलाफ़ जांच शुरू कर दी है. मनीषा 2009 में एक साल के लिए डब्ल्यूएचओ में प्रतिनियुक्ति पर तैनात थीं. एक साल की कार्यावधि समाप्त होने पर तैनाती की अवधि बढ़ाने के अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के बाद भी मनीषा अपने मूल कैडर में नहीं लौटीं. सूत्रों के मुताबिक़, सरकार उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुई और उनके ख़िलाफ़ जांच के आदेश दे दिए गए. हालांकि पर्यवेक्षक सरकार के इस कड़े क़दम से आश्चर्यचकित हैं. उनका मानना है कि मनीषा को डब्ल्यूएचओ ने सीधे अपने यहां नियुक्त किया था और वह भारत सरकार की ओर से प्रतिनियुक्ति पर तैनात नहीं हुई थीं. कुछ अन्य लोग कहते हैं कि प्रतिनियुक्ति पर सरकार की असंगत नीति की वजह से कई उलझनें पैदा होती रहती हैं. कुछ अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर रहने दिया जाता है, जबकि कुछ को यह कहकर बुला लिया जाता है कि राज्य में अधिकारियों की कमी है.

दिलीप चेरियन

जंगल की लड़ाई

पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश के अति सक्रिय दृष्टिकोण और विवाद पैदा करने की ओर ज्यादा झुकाव ने अपेक्षाकृत कम चर्चित रहने वाले इस मंत्रालय को चर्चा में ला दिया. साथ ही इस मामले पर विशेषज्ञ बाबुओं की भी मांग बढ़ गई. सूत्र कहते हैं कि समस्या धीरे–धीरे बढ़ने लगी है. जयराम रमेश ने एक कमेटी गठित की है, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य एन सी सक्सेना को सौंपी गई है. इस कमेटी से उन क़ानूनों में बदलाव लाने के लिए सुझाव देने को कहा गया है, जिनसे राष्ट्रीय वन क्षेत्र को शासित और नियंत्रित किया जाता है. पर्यवेक्षकों के मुताबिक़, सक्सेना ने वन अधिकार कानून के बेहतर कार्यान्वयन के लिए कई सुझाव दिए हैं. कमेटी ने यह भी आरोप लगाया है कि वन मामले से जुड़े बाबू वन नियमों को बेहतर ढंग से लागू कराने में असफल रहे हैं. ज़ाहिर है, कमेटी के सुझावों और वन विभाग से जुड़े बाबुओं की अक्षमता के बारे में की गई टिप्पणी ने सक्सेना के लिए मुश्किलें पैदा कर दीं. कमेटी के इस कार्य की वजह से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में सक्सेना के दोस्तों की संख्या घट गई. उदाहरण के लिए वन महानिदेशक ने कमेटी द्वारा दिए गए कई सुझावों को अस्वीकार कर दिया है. इस बीच भारतीय वन सेवा एसोसिएशन ने सक्सेना पर आरोप लगाया है कि तमाम नियमों को दरकिनार करते हुए वन भूमि का वितरण करने के लिए उन्होंने आईएफएस बाबुओं को धमकाया. ज़ाहिर है, ऐसी स्थिति में उन दो समूहों के बीच लड़ाई तो होगी ही, जहां एक समूह बदलाव चाहता है और दूसरा समूह यथास्थिति बनाए रखना चाहता है. ऐसे में जयराम रमेश क्या करेंगे, अपने बाबुओं का समर्थन या फिर बदलाव के समर्थन में उतरेंगे?

dilipcherian@gmail..com

कांग्रेस और रामदेव आमने-सामने

पृष्ठ एक का शेष

स्विट्जरलैंड के चार और इटली के आठ बैंक खोले गए. ये इटली वे बैंक हैं, जिनमें घाटा चल रहा है और जिन्हें वहां का माफ़िया चला रहा है. इससे आगे जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है. बाबा को मैंने ही लिस्ट दी थी आठ बैंकों की.

स्विस और इटली के बैंकों की बात यहीं ख़त्म नहीं हुई. विश्वबंधु ने इन सारी गड़बड़ियों के लिए सोनिया गांधी को ज़िम्मेदार बता दिया. सोनिया गांधी के ख़िलाफ़ सार्वजनिक तौर पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम किसी ने नहीं लगाया. विश्वबंधु ने कहा– ***मेरी बहन सोनिया गांधी, अगर देश को लूटने आई हो, तो लाल क़िले से ऐलान कर दो. अगर हम में देश का ख़ून है तो हम जीतेंगे और अगर तुम में इटली का ख़ून और उसका गर्व है तो तुम जीत जाना. एक बार यह आर–पार की लड़ाई हो ही जाए तो अच्छा है.*** बाबा रामदेव के स्वाभिमान आंदोलन के मंच से सोनिया गांधी पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं. बाबा रामदेव कहते हैं कि भ्रष्टाचार का उनका आंदोलन किसी पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन रैली में जो हुआ, उससे तो यही लगता है कि बाबा रामदेव ने कांग्रेस के ख़िलाफ़ यह अभियान छेड़ा है.

हसन अली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हसन अली के ख़िलाफ़ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई. हैरानी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के पहले ही विश्वबंधु गुप्ता ने कांग्रेस और हसन अली के रिश्तों के बारे में बता दिया था. इस रैली में उन्होंने यह दावा किया– ***अब आपको हसन अली का कुछ ख़ुलासा करता हूं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिसमें मैं कमिश्नर था, उसने पुणे में छापा मारा. छापे में एक लैपटॉप पकड़ा गया, जिसमें सत्रह नाम थे. एक नाम पढ़ा जा सकता था अदनान खशोगी का. बाक़ी सोलह नाम कोडेड थे, समझ नहीं आ रहे थे. हमारे अफ़सर थक गए. उन्होंने कहा कि साहब, ये नाम नहीं पता लग रहे. एक ईमानदार अफ़सर ने स्विट्जरलैंड को चिट्ठी लिखी कि साहब इनके नाम बता दीजिए. उन्होंने कहा कि हम ये नाम आपको देने के लिए तैयार हैं, अगर आपके वित्तमंत्री हमको चिट्ठी लिखें. लेकिन इस चिदंबरम का कैरेक्टर देखिए आप, उस आदमी को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा. हम आपको उसका कैरेक्टर बताते हैं. चिदंबरम ने क्या किया, सत्रह आदमियों की लिस्ट देखी. मुझे कारण मालूम नहीं कि उन्होंने चिट्ठी क्यों लिखी, मगर लगता है उनके मन में घूस खाने का लालच आया. उन्होंने सोचा कि ये पचास हज़ार करोड़ की मोटी–मोटी बिल्लियां आ गई हैं, नाम लाऊंगा, इनको ब्लैकमेल करूंगा और घूस खाऊंगा. इतिहास भी आदमियों से क्या–क्या करा देता है. चिट्ठी लिखी गई, हसन अली का अकाउंट निकला, सत्रह नाम आए, लेकिन चिदंबरम की क़िस्मत फूट गई. उसमें तीन राजनेताओं के भी नाम थे. आपको नाम भी बता देता हूं, विलासराव देशमुख का नाम था, जो कैबिनेट मिनिस्टर है. उसके बाद वह घोड़े बेचने वाला आदमी, जिसने 100 लाख करोड़ रुपया जमा कराया. फिर क्या हुआ. यह तीन साल पहले की बात है. आज भी हसन अली खुलेआम घूम रहा है. आज दूसरे का भी नाम सुन लो, जो विलासराव देशमुख के साथ हसन अली से मिलने गया था पुणे में. दूसरे आदमी का नाम है अहमद पटेल. सोनिया गांधी जी सुन लो...बॉम्बे पुलिस के पास उन तीनों राजनेताओं की वीडियो फुटेज है, जो रात को पुणे में मिलते थे.***

बात हसन अली से सोनिया गांधी तक पहुंच गई. विश्वबंधु ने आगे कहा– ***अहमद पटेल यूपीए की चेयरमैन के राजनैतिक सलाहकार हैं. मैं नहीं जानता कि वह कौन सी राजनीति समझाते हैं, क्योंकि उनकी मीटिंग सोनिया से रोज़ रात को 12 से 2 बजे के बीच होती है. भारत के इतिहास में पहली बार मैंने देश के राजनेताओं को रात–रात भर 12 से 3 बजे तक मिलते देखा है. अरे उल्लू***

जागते हैं उस समय तो! सोनिया गांधी जी यह बताएं या अहमद पटेल बताएं कि हफ्ते में 2–3 बार जब सोनिया का फ़ोन आता था, तो अहमद पटेल गाड़ियां बदल–बदल कर छुपकर उनसे मिलने 10 जनपथ क्यों जाते थे, क्या होता था, क्या हिसाब तय होता था? क्या पैसे की बातें होती थीं? आज यह देश एक डिपार्टमेंटल स्टोर है. इस सरकार ने वाइस चांसलरों की पोस्ट बेचीं. राज्यसभा की सीटें बिक रही हैं पैंतीस करोड़ की. हर चीज़ बिकी. और बिकते–बिकते मामला यहां तक आ गया कि इस मुल्क की ज़मीन तक सरकार ने बेची. हम जानते हैं कि हसन अली दाऊद का आदमी है. 2–जी मामले में आपने शाहिद बलवा का नाम सुना. शाहिद बलवा एक बिल्डर हैं, जो कुछ दिन पहले सड़क पर चलते थे. शाहिद बलवा के यहां जब छापा पड़ा तो उनके पास शरद पवार के काग़ज़ मिले हज़ारों करोड़ के, अनर्थ हुआ. मुझको तो यह भी समझ में नहीं आता कि इस देश के मंत्रिमंडल में कोई ईमानदार मंत्री है भी कि नहीं.

इस रैली में भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं देश के जाने–माने वकील राम जेठमलानी भी थे. उन्होंने भी गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए. उन्होंने कहा– ***स्विट्ज़रलैंड के एक अख़बार, जिसका नाम था इलस्ट्रेटेड, ने दुनिया के 14 बड़े गुनहगारों और डाकुओं का ज़िक्र उनकी तस्वीरों के साथ अपने एक पर्चे में किया था. उन 14 गुंडों और बदमाशों के बीच में एक हिंदुस्तानी भी था. वह हिंदुस्तानी हमारे देश का पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी था. उसकी तस्वीर के बाज़ू में कई मिलियन डॉलर लिखे हुए थे, जो स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में जमा थे. अब मैं 1994 की बात करता हूं. रशिया में एक किताब छपी, जिसका नाम है अ स्टेट विद इन अ स्टेट. उसमें लिखा है कि राहुल गांधी को हमारी केजीबी से, जो उनकी सीक्रेट पुलिस है, हर साल अच्छा पैसा मिल रहा है और राहुल गांधी हमारी शुक्रगुज़ारी करता रहता है और सोचता है कि जो पैसा मैं रशिया से लेता हूं, वह हिंदुस्तान की सेवा में लगाता हूं. हिंदुस्तान के प्रेस ने यहां की जनता को यह बात कभी नहीं बताई. यह बात छिपाई गई, क्यों? क्या भ्रष्टाचार हमारे प्रेस को भी ख़राब कर चुका है?***

बाबा रामदेव सबसे आख़िरी में बोले. संत नहीं, एक राजनेता की तरह बोले. अपने भाषण से उन्होंने सभी वक्ताओं के भाषण को एक दिशा दी. भारत स्वाभिमान आंदोलन के दुश्मन कौन हैं, मित्र कौन, इसे भी सफ़ाई से बताया. उन्होंने कहा– ***महात्मा गांधी का नाम और तो देश में कहीं दिया नहीं, बहुत दबाव देने के बाद नरेगा महात्मा गांधी के नाम किया गया. बाक़ी तो आधी से ज्यादा योजनाओं और संस्थानों के नाम एक ही परिवार के नामों पर हैं. क्या सिर्फ़ एक ही परिवार ने शहादत दी है, आधी से ज्यादा योजनाओं का नाम एक ही परिवार के नाम कैसे कर दिया गया... वर्तमान में जो केंद्र सरकार है, इसका क़रीब 55 साल देश में राज रहा है...इस दौरान 400 लाख करोड़ लूटे गए हैं हिंदुस्तान के. माना कि हम दूसरी पार्टियों को क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, लेकिन यदि दूसरे दोषी हैं एक–दो प्रतिशत, तो 99 प्रतिशत दोषी हैं जो वर्तमान में बैठे हैं.*** वैसे भी विश्वबंधु गुप्ता ने इस मंच से पहले ही ऐलान कर दिया था– ***देश में भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ ऐसा महाभारत होगा, जो हमारी नई पीढ़ी देखेगी और नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक से लेकर दस जनपथ तक की ईंट से ईंट तोड़ दी जाएगी.***

बाबा रामदेव ने काले धन की बात उठाई और सीधा सोनिया गांधी को निशाने पर लिया. उन्होंने विश्वबंधु गुप्ता की बात को आगे बढ़ाया और कहा– ***पहले चोरी करके (काला धन) स्विट्ज़रलैंड भेजते थे, अब इन बैंकों को भारत ही बुला लिया. स्विट्ज़रलैंड के चार बैंक यहीं बुला लिए. उन्होंने कहा कि पहले हज़ार करोड़ लूटते थे, अब लाखों करोड़ लूट रहे हैं. स्विट्ज़रलैंड ले जाने में दिक्क़त होती है. स्विट्ज़रलैंड के बुलाए तो बुलाए, जब मैंने कहा कि आठ बैंक इटली के बुलाए तो मिर्ची लग गई. अरे, इटली के आठ बैंक भारत में क्या कर रहे हैं?*** बाबा रामदेव गांधी परिवार पर हमला करने से नहीं चूकते. कभी सीधे–सीधे तो कभी इशारे में. बीच–बीच में उन्होंने नेहरू पर भी छींटाकशी की, कहा, मैं अभी तेजपुर से आया हूं जिसे एक प्रधानमंत्री ने चीन को सौंप दिया था. इस रैली में उन्होंने उस मुद्दे को फिर उठाया, जिसमें यह आरोप लगाया– ***एक कांग्रेसी सांसद ने मुझे अपशब्द कहे. कोई संन्यासी जिन्हें ब्लडी इंडियन और कुत्ता नज़र आता है, उनके दिमाग़ का इलाज करना चाहिए. दु:ख इस बात का है कि ऐसे लोगों को हम संसद में कैसे बैठा देते हैं. सरकार और वह पार्टी इस पाप के लिए क्षमा मांगना तो दूर, उल्टा हिसाब मांगती है. अब तो देश की जनता हिसाब मांगेगी कि तुमने कितना देश को लूटा है.*** बाबा के निशाने पर केंद्र सरकार तो है ही, साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री को भी कठघरे में खड़ा कर दिया. उन्होंने कहा– ***आज तो प्रधानमंत्री ने समय नहीं दिया, मैं तो समय मांगता रहूंगा. अगर समय नहीं दिया तो उनका भी समय पूरा हो जाएगा. वह सलामत रहें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बेईमान लोगों से घिरे ईमानदार व्यक्ति हैं. आज तक की सबसे बेईमान सरकार के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री का तमग़ा उन्हें मिला है.***

किसी भी रैली का मक़सद देश और समाज में संदेश देना होता है. कुछ रैलियां ऐसी होती हैं, जिनमें मजमा तो लगता है, हज़ारों–लाखों लोग जमा होते हैं, लेकिन वे कोई संदेश नहीं पहुंचा पातीं. वहीं कुछ रैलियां ऐसी होती हैं, जो छोटी होती हैं, जिनमें ज्यादा लोग नहीं जमा होते, लेकिन उनसे देश और समाज में संदेश जाता है. यह रैली संदेश देने में कामयाब नहीं हुई. ख़ानापूर्ति के लिए अख़बारों ने रैली की ख़बर छाप तो दी, लेकिन मुद्दा गुम हो गया. योग गुरु बाबा रामदेव को भी उलझन हुई होगी कि इतने सारे अख़बारों और उनके सभी चहेते टीवी चैनलों से रैली का संदेश क्यों ग़ायब हो गया. क्या कांग्रेस पार्टी और सरकार ने अख़बारों–चैनलों पर दबाव बना लिया या फिर इस रैली में ही कुछ ऐसी बातें कही गईं, आरोप लगाए गए कि मीडिया ने इससे किनारा करना ही मुनासिब समझा.

बाबा रामदेव ने जबसे राजनीतिक दल बनाने की घोषणा की है, तबसे उनकी रैलियों में एक बदलाव दिख रहा है. भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आंदोलन का आह्वान करने वाले बाबा रामदेव की पूरी मुहिम कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पर केंद्रित होती जा रही है. इस रैली में गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के ख़िलाफ़ वक्ताओं ने जमकर आग उगली, आरोप लगाए. बाबा रामदेव के सामने भाषा की सीमा लांघी गई. तालियों की गड़गड़ाहट के बीच राजनीतिक और सामाजिक गरिमा दब सी गई. हालांकि यह सवाल भी उठता है कि संतों के इस आंदोलन में ख़राब भाषा का क्या औचित्य है. अगर बाबा रामदेव की बातों में सत्यता है, अगर उनकी लड़ाई सिर्फ़ भ्रष्टाचार से है तो जनता वैसे ही खिंची चली आएगी.

हमने कई नेताओं से इन आरोपों के बारे में बात की. कांग्रेस के नेताओं को अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए. चुप रहा जाए या फिर बोला जाए. बाबा के ख़िलाफ़ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही है. जो हिम्मत करना भी चाहते हैं, उन्हें चुप रहने के लिए कहा गया है. सवाल यह है कि क्या देश में मंत्रियों, सरकार, राजनीतिक दलों और उनके नेतृत्व पर बिना सबूत, बिना तथ्य, बिना जानकारी के आरोप लगाया जा सकता है. अगर इन आरोपों के सबूत हैं तो बाबा रामदेव और उनके साथियों को उन्हें देश की जनता के सामने पेश करना चाहिए. हम इस मामले को इसलिए उठा रहे हैं कि बाबा रामदेव के मंच से किन्हीं सामान्य लोगों पर आरोप नहीं लगाया गया है. बाबा रामदेव और उनके अभियान में शामिल लोग देश चलाने वाले मंत्रियों और सरकार चलाने वाली पार्टी और उसके नेतृत्व पर आरोप लगा रहे हैं. जनता को सच जानने का अधिकार है. अगर कांग्रेस पार्टी और सरकार इन आरोपों का जवाब नहीं देती है तो देश की जनता मान लेगी कि इन आरोपों में सच्चाई है.

manish@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 3 अंक 1
दिल्ली, 14 मार्च–20 मार्च 2011
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के –2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.

संपादकीय 0120–4783999/11–23418962
विज्ञापन व प्रसार +91 120 4783999
+91 9871194800
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16+4+4+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

इस बजट को देखा जाए तो एक बार फिर से कांग्रेस सरकार ने यह जता दिया है कि वह हर क़ीमत पर बाज़ारवाद और नव उदारवाद का साथ देगी.

बजट 2011

इसमें ग़रीबों के लिए कुछ भी नहीं है

फोटो– *प्रभात पाण्डेय*

सिद्धार्थ राय

प्रणब मुखर्जी के बजट में दबे-कुचलों, ग़रीबों, अल्पसंख्यकों, मज़दूरों, महिलाओं, बच्चों और किसानों के लिए धेले भर की जगह नहीं दिखाई पड़ती. बहुत पहले ही देश में बजट का स्वरूप बदल गया था. आज स्थिति यह है कि बजट सरकार की आमदनी और ख़र्च का ब्योरा नहीं, बल्कि जनता को आंकड़ों में उलझा कर बेवकूफ़ बनाने की एक सोची समझी साज़िश बनकर रह गया है. जहां जनता को खाने को भरपेट भोजन न हो वहां यह काम और भी आसान हो जाता है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को सरकारी फ़ाइलों और वित्त मंत्री के लाल सूटकेस में बंद आंकड़ों और संख्याओं के परे ले जाकर ही किसी भी बजट के पीछे की मंशा समझी जा सकता है. इसे समझने का आधार होता है कि बजट में आम जनता के लिए क्या है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जनता ही देश को पैसा कमा कर देती है और सरकारें केवल उस पैसे की रखवाली करतीं हैं. इस बजट को देखा जाए तो एक बार फिर से कांग्रेस सरकार ने यह जता दिया है कि वह हर क़ीमत पर बाज़ारवाद और नव उदारवाद का साथ देगी.

यह बजट जनता के लिए दुःख लेकर आया है, जबकि जनता महंगाई और भुखमरी की मार झेल रही है, देश के किसान त्राहिमाम कर रहे हैं और बच्चों का भविष्य अंधकार की गर्त में चला गया है. प्रणब मुखर्जी ने बजट पूर्व अपने भाषण में बहुत ही मानवीय बातें कीं. वित्त मंत्री ने माना कि देश महंगाई और अभाव की मार झेल रहा है. उन्होंने यह भी माना कि यह महंगाई और कमी सबसे ज्यादा प्रभाव खाद्य पदार्थों के ही संदर्भ में है. यहां तक उनकी बात बिलकुल सही है. भारत में पिछले एक साल में खाने की चीज़ों आटे, दाल, चावल, दूध, अंडा, प्याज, सब्ज़ियां एवं चीनी के भाव में ही सबसे ज्यादा उछाल आया है. सुनने वालों ने सोचा कि शायद सरकार को और ख़ुद मंत्रीजी को शर्म आई है और वह इसका निवारण करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. महंगाई कोई साधारण बात नहीं है कि इसे तुरंत कम किया जा सके. सरकार ने पिछले दिनों प्याज के दाम आसमान छूने पर जनता को दिखाने के लिए बड़े छापे मारे, लेकिन समझने की बात यह है कि इन छापों से कुछ नहीं होता. महंगाई बाक़ी बहुत से कारकों से बढ़ती या घटती है. अब अगर पेट्रोल और डीज़ल के दाम बढ़ेंगे तो सारे सामानों कि ढुलाई का ख़र्च बढ़ेगा और महंगाई भी बढ़ जाएगी और इसका पूरा इंतज़ाम इस बजट में कर दिया गया है. इस बजट में पेट्रोल और सार्वजनिक वाहनों के ईंधनों पर दी जाने वाली सब्सिडी को बड़े पैमाने पर घटा दिया गया है. 2010-11 में 38386 करोड़ से घटाकर 2011-12 के लिए बस 23640 करोड़. सरकार शायद बहरी ही नहीं अंधी भी हो गई है. शायद प्रणब मुखर्जी ने अख़बार पढ़ना और टी.वी पर समाचार सुनना बंद कर दिया है. ऐसा नहीं होता तो वे समझते कि जब तेल उत्पादन करने वाले देशों यानी पूरे पश्चिम एशिया में क्रांति की लहर चल रही हो तो ज़ाहिर है कि अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में तेल की क़ीमत अपने आप बढ़ेगी और इसलिए भारत में भी. अब सब्सिडी भी कम कर दी तो जनता क्या करेगी? प्रणब जी ने महंगाई को तो माना और यह भी स्वीकार किया कि भारत में कुपोषण का काला साम्राज्य फैलता जा रहा है, लेकिन क्या किया? खाद्यान्नों पर दी जाने वाली सरकारी सब्सिडी को ही कम कर दिया. पिछले साल यह सब्सिडी 60600 करोड़ थी और इस साल इसे 60573 करोड़ कर दिया गया है. अब इस बात का क्या मतलब निकलता है, इसके पीछे मुखर्जी साहब की कौन-सी नई और नायाब आर्थिक सोच है यह तो वही जानें, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में खाद्यान्नों की क़ीमतें बढ़ रही हैं, यह क़दम जनता विरोधी है. यह कटौती कम जान पड़ती है, लेकिन अगर इसे कृषि उत्पादों से जुड़े कोल्ड स्टोरेज और गोदामों के लिए नियत ख़र्च में कमी के साथ जोड़ दिया जाए तो इस कमी का आंकड़ा लगभग छह हज़ार करोड़ का हो जाता है.

इस बजट की सबसे बड़ी ख़ूबी यह रही कि वित्तीय और आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के नाम पर इसमें जनता के कल्याण के लिए पैसे का आवंटन कम कर दिया गया. अगर सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में इस बजट को समझा जाए तो पता चलता है कि सरकार ने इस बार पिछली बार से कम पैसा ख़र्च करने की योजना बनाई है. पिछली बार का बजट ख़र्च सकल घरेलू उत्पाद का 15.4 प्रतिशत था जो इस बार घटकर बस 14 प्रतिशत रह गया है. अब अगर इसे बढ़ी हुई क़ीमतों और महंगाई के संदर्भ में देखा जाए तो यह बहुत ही गंभीर आंकड़ा बनकर उभरता है. इस कम ख़र्ची और बचत की मार सबसे ज्यादा ग़रीब और हाशिये पर खड़े तबक़ों पर पड़ेगी. अब अपने भाषण में मुखर्जी साहब ने कहा कि उन्होंने पिछले दो साल के बजटों में व्यवसायियों और बड़े उद्योगपतियों को वैश्विक मंदी की मार झेलने की वजह से जो छूट दी थी, इस बजट में वे उसे वापस ले रहे हैं. अब पिछले दो सालों की इस रियायत को इस बार बंद किया गया तो ज़ाहिर सी बात है कि सरकार का बहुत पैसा बचा. तो प्रश्न यह उठता है कि इस पैसे को जनता के लिए क्यों नहीं लगा दिया गया? अब बात सामाजिक विषयों और मदों में ख़र्च किए जाने वाले पैसे की. यह बजट का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है जैसा कि किसी भी बजट के पीछे की मंशा इसे देखकर समझी जा सकती है. सकल घरेलू उत्पादन के अनुपात में इस बार इस विषय पर सकल घरेलू उत्पाद का बस 1.96 प्रतिशत ही ख़र्च करने का सरकार का मन है. बड़ी बात यह है कि पिछले साल जब इतनी महंगाई नहीं थी और वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी चल रही थी तब भी यह अनुपात इस बार से अधिक था. मुखर्जी साहब ने अपने भाषण में कहा कि यह बजट उन्होंने ख़ासकर आम आदमी के लिए बनाया है, लेकिन उनकी कैंची जहां-जहां चली है वह इस बात को नकार देती है. सबसे पहले उनकी गाज गिरी महात्मा गांधी रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) पर. याद रखने वाली बात यह है कि इस योजना को कांग्रेस ने अपनी अग्रणी योजनाओं में भी सबसे आगे रखा था. जनता का प्यार और विश्वास जीतने का यह सबसे बड़ा ज़रिया माना जाता था और देश में अप्रशिक्षित मज़दूरों के लिए यह योजना भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं है. इस योजना को खाद्य सुरक्षा का भी एक स्तंभ माना जाता है. इस सबके बावजूद बजट में इसके सौ करोड़ रुपये काट दिए गए. इसी संदर्भ में एक और बात बहुत आवश्यक है. एक तो सरकार ने खाद्य पदार्थों पर दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती की, साथ में पहले रोज़गार पर ख़र्च काटा और ऊपर से खाने के दाम आसमान छूने लगे. इस तरह की व्यवस्था में, जहां पर एक मज़दूर और ग़रीब आदमी पर इतना भार डाला जा रहा हो, एक सफल अर्थव्यवस्था का पनपना संभव नहीं है. यह व्यथा यहीं नहीं रुकती, ग्राम खाद्यान्न बैंक योजना के लिए आवंटित पैसे में भी 30 फ़ीसदी की कमी कर दी गई है.

मुखर्जी साहब ने बजट के पहले के अपने भाषण में संसद के सामने कहा कि उनकी सरकार विस्तृत विकास के लिए कटिबद्ध है और यह बजट उस विचार का आईना होगा, लेकिन उन्होंने ग़रीबों के संबंध में सभी योजनाओं से सरकारी ख़र्च काटने का काम बख़ूबी किया. पहले तो ग़रीब के मुंह से निवाला छीन लिया, फिर उसके सर के ऊपर की छत भी ले ली. इंदिरा आवास योजना जो कि कांग्रेस की अग्रणी योजनाओं में से एक है, का भी आवंटन काफ़ी हद तक पिछली बार की तुलना में कम कर दिया गया है. पिछली बार इसे 9334 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे और इस बार बस 8996 करोड़. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना (नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन) का आवंटन भी लगभग सौ करोड़ कम कर दिया गया है. इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से मुखर्जी साहब क़समें खाते हैं, लेकिन इसके विकास पर भी पानी फेर दिया गया है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बजट 18996 करोड़ से घटाकर बस 16006 करोड़ रुपये कर दिया गया है. आज जब भारत के गांव मंदी की मार झेल रहे हैं, महंगाई और गिरते उत्पादन क्षमता से जूझ रहे हैं, जिससे मुखर्जी साहब भी इत्तेफ़ाक़ रखते हैं और जिसे उन्होंने अपने भाषण में कहा भी, ग्रामीण विकास मंत्रालय का ख़र्च 76378 करोड़ से घटाकर 74143 करोड़ कर दिया गया है. सरकार ने शिक्षा पर ख़र्च बढ़ाकर वाहवाही कमाने का प्रयास तो किया, लेकिन जनता को नहीं बताया कि इसमें सरकार की कोई उदारता नहीं है बल्कि शिक्षा पर लगाए गए टैक्स से आए पैसे को ही वापस लगा दिया गया है. फिर भी इस बढ़ोतरी की सच्चाई कुछ अलग ही है. साथ ही सरकार ने दिखाया कि उसने सर्व शिक्षा अभियान पर पिछली बार के 15000 करोड़ की जगह इस बार 21000 करोड़ रुपये का ख़र्च नियत किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस पैसे से भी सबको शिक्षा के अधिकार की गारंटी नहीं दी जा सकती. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार के अपने आंकलन के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा को आने वाले पांच सालों में सकल बनाने के लिए 1.82 करोड़ ख़राब रुपयों की ज़रूरत है. अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इस बार का आवंटन इस संख्या का पांचवां हिस्सा होना चाहिए था. इसे इस आंकलन के अनुसार 33 हज़ार करोड़ होना चाहिए था.

कामगार मज़दूरों के हितों की भी अनदेखी इस बजट में की गई. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इस बार यह प्रावधान किया गया कि इसके अंतर्गत अब सारे मनरेगा के मज़दूर, बीड़ी उद्योग में लगे मज़दूर और कई ख़तरनाक क़िस्म के उद्योगों में काम कर रहे लोग आएंगे, लेकिन बजट में इस योजना के लिए बहुत ही कम पैसा आवंटित किया गया है. पिछली बार 446 करोड़ रुपये दिए गए थे, जबकी इसे इस बार काट कर 280 करोड़ कर दिया गया है. एक बार फिर ग़रीब आदमी मारा गया, ठगा गया. बच्चों पर भी किए जाने वाले ख़र्च में कोई ख़ास वृद्धि नहीं हुई है. कुपोषित बच्चों की संख्या देखी जाए तो, इस मामले में भारत विश्व में अग्रणी है, लेकिन यहां की सरकार के लिए शायद यह शर्मनाक बात न होकर एक तमग़ा है. आईसीडीएस (इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस) में पिछली बार के 9280 करोड़ के ऊपर इस बार बस दस हज़ार करोड़ ही आवंटित किए गए हैं और यह पैसा भी इसलिए बढ़ाया गया है, क्योंकि इसमें काम करने वाली आंगनवाड़ी कर्मियों की तनख्वाह बढ़ाई गई है. इस कारण इस बढ़े हुए आवंटन से बढ़ा हुआ वेतन दिया जाएगा न कि बच्चों को इसका कोई लाभ मिलेगा. वैश्विक मंदी की मार झेल रही कृषि के लिए भी कुछ ख़ास नहीं किया गया है. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत इस बार का आवंटन बस 7860 करोड़ है, जो पिछली बार के 6755 करोड़ के मुक़ाबले कोई ख़ास वृद्धि नहीं है. उपज बढ़ाने के लिए किसान के पास बेहतर तकनीक नहीं है और देश में कृषि पर आधारित जनता की बहुतायत है. इतने कम पैसों में इन सारी समस्याओं का निवारण संभव नहीं है. हम सभी हरित क्रांति को देश के इतिहास का एक स्वर्णिम पन्ना मानते हैं, लेकिन इसे देश के पूर्वीय क्षेत्रों में फैलाने के लिए बस 400 करोड़ रुपये दिए गए हैं. इन अति ग़रीब पूर्वीय राज्यों में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार एवं झारखंड शामिल है. इसके विपरीत देश के महानगरों में बसें चलवाने के लिए ही लगभग ढाई हज़ार करोड़ रुपये रखे गए हैं.

खाद्य सुरक्षा पर यह सरकार एक क़ानून लाने जा रही है, लेकिन कृषि के लिए दिया गया पैसा नगण्य है. यह सरकार की लापरवाही है, जिस कारण साठ हज़ार ऐसे गांवों में जहां दलहन उगाई जाती है, के विकास के लिए बस 300 करोड़ रुपये दिए गए हैं. प्रणब मुखर्जी के ही अनुसार भारत की 40 प्रतिशत सब्ज़ियां बाज़ार पहुंचने से पहले ही सड़ जाती हैं, लेकिन सब्ज़ियों की खेती के विकास के लिए बस 300 करोड़ रुपये दिए गए. भारत की जनता में प्रोटीन की भारी मात्र में कमी पाई जाती है, लेकिन पूरे भारत के 1.18 बिलियन लोगों की प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय मिशन को बस 300 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है. भारत दूध उत्पादन में विश्व में अग्रणी है, लेकिन यहां प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता शायद सबसे कम है, लेकिन फिर भी चारा विकास योजना को भी बस 300 करोड़ रुपये का ही आवंटन मिल पाया. अब देखते हैं कि इस बजट में इस देश की अल्पसंख्यक जनता के लिए क्या है? रंगनाथ आयोग और सच्चर कमेटी की रिपोर्टों ने यह साफ़ कर दिया कि इस देश का मुसलमान कितना ग़रीब और पिछड़ा हुआ है, लेकिन इस बजट ने मुसलमानों को भी धोखा दिया है. पूरे बजट में मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के लिए बस एक ही परिच्छेद है. सरकार ने तय किया है कि अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता पर बैंकों द्वारा दिए गए लोन का 15 प्रतिशत दिया जाए, लेकिन यह दर पिछले साल 13 प्रशित रही और इस साल 13.6 प्रतिशत की कम दर से बढ़ी. साथ ही सरकार ने इस 15 प्रतिशत के लक्ष्य के लिए कोई नियत समय सीमा का निर्धारण नहीं किया है.

ज़ाहिर है, यह बजट जनता विरोधी है. जनता को ठगा गया. पूरे साल तो कांग्रेस और उसके घटक दलों ने देश को भ्रष्टाचार के मार्फ़त लूटा और जब बारी मरहम लगाने की आई तो जनता के ज़ख्मों को और कुरेद दिया गया.

feedback@chauthiduniya.com

- खाद्यान्नों पर दी जाने वाली सरकारी सब्सिडी को ही कम कर दिया. पिछले साल यह सब्सिडी 60600 करोड़ थी और इस साल इसे 60573 करोड़ कर दिया गया है
- सकल घरेलू उत्पादन के अनुपात में इस बार सामाजिक विषयों पर सकल घरेलू उत्पाद का बस 1.96 प्रतिशत ही ख़र्च करने का सरकार का मन है
- सार्वजनिक वाहनों के ईंधनों पर दी जाने वाली सब्सिडी को बड़े पैमाने पर घटा दिया गया है. इसे 38,386 करोड़ से घटाकर 2011-12 के लिए 23,640 करोड़ कर दिया गया

- मनरेगा के बजट से सौ करोड़ रुपये काट दिए गए
- इंदिरा आवास योजना के बजट से 338 करोड़ रुपये काटे गए
- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना (नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन) का आवंटन सौ करोड़ कम कर दिया गया है
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का बजट 446 करोड़ से 280 करोड़ कर दिया गया है
- पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार एवं झारखंड में हरित क्रांति विस्तार के लिए बस 400 करोड़ का प्रावधान

- पूरे बजट में मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के लिए बस एक ही परिच्छेद है. सरकार ने तय किया है कि अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता पर बैंकों द्वारा दिए गए लोन का 15 प्रतिशत दिया जाए.
- पिछली बार का बजट ख़र्च सकल घरेलू उत्पाद का 15.4 प्रतिशत था जो इस बार घटकर बस 14 प्रतिशत रह गया है
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बजट 18996 करोड़ से घटाकर 16006 करोड़ रुपये कर दिया गया है
- ग्रामीण विकास मंत्रालय का ख़र्च 76378 करोड़ से घटाकर 74143 करोड़ कर दिया गया है

हज़रत मुहम्मद की पत्नी ख़दीजा कपड़े का कारोबार करती थीं. महिला संत राबिया बसरी की ख्याति दूर-दूर तक फैली थी. पुरुष संतों की तरह वह भी धार्मिक सभाओं में शिरकत करती थीं.

मुस्लिम समाज में तालीम की बयार

फ़िरदौस ख़ान

शिक्षा सभ्य समाज की बुनियाद है. इतिहास गवाह है कि शिक्षित क़ौमों ने हमेशा तरक़्क़ी की है. किसी भी व्यक्ति के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शिक्षा बेहद ज़रूरी है. अफ़सोस की बात यह है कि जहां विभिन्न समुदाय शिक्षा को विशेष महत्व दे रहे हैं, वहीं मुस्लिम समाज इस मामले में आज भी बेहद पिछड़ा हुआ है. भारत में ख़ासकर मुस्लिम महिलाओं की हालत बेहद बदतर है. सच्चर समिति की रिपोर्ट के आंकड़े इस बात को साबित करते हैं कि अन्य समुदायों के मुक़ाबले मुस्लिम महिलाएं सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से ख़ासी पिछड़ी हैं, लेकिन ख़ास बात यह है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद वे विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति अर्जित कर रही हैं.

सच्चर समिति की रिपोर्ट के मुताबिक़ देश भर में मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता दर 53.7 फ़ीसदी है. इनमें से अधिकांश महिलाएं केवल अक्षर ज्ञान तक ही सीमित हैं. सात से 16 वर्ष आयु वर्ग की स्कूल जाने वाली लड़कियों की दर केवल 3.11 फ़ीसदी है. शहरी इलाक़ों में 4.3 फ़ीसदी और ग्रामीण इलाक़ों में 2.26 फ़ीसदी लड़कियां ही स्कूल जाती हैं. वर्ष 2001 में शहरी इलाक़ों में 70.9 फ़ीसदी लड़कियां प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा हासिल कर पाईं, जबकि ग्रामीण इलाक़ों में यह दर 47.8 फ़ीसदी रही. वर्ष 1948 में यह दर क्रमश: 13.9 और 4.0 फ़ीसदी थी. वर्ष 2001 में आठवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों का प्रतिशत शहरी इलाक़ों में 51.1 और ग्रामीण इलाक़ों में 29.4 रहा. वर्ष 1948 में शहरी इलाक़ों में 5.2 फ़ीसदी और ग्रामीण इलाक़ों में 0.9 फ़ीसदी लड़कियां ही मिडिल स्तर तक शिक्षा हासिल कर पाईं. वर्ष 2001 में मैट्रिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों की दर शहरी इलाक़ों में 32.2 फ़ीसदी और ग्रामीण इलाक़ों में 11.2 फ़ीसदी रही. वर्ष 1948 में यह दर क्रमश: 3.2 और 0.4 फ़ीसदी थी.

शिक्षा की तरह आत्मनिर्भरता के मामले में भी मुस्लिम महिलाओं की हालत चिंताजनक है. सच्चर समिति की रिपोर्ट के मुताबिक़ 15 से 64 साल तक की हिंदू महिलाओं (46.1 फ़ीसदी) के मुक़ाबले केवल 25.2 फ़ीसदी मुस्लिम महिलाएं ही रोज़गार के क्षेत्र में हैं. अधिकांश मुस्लिम महिलाओं को पैसों के लिए अपने परिवारीजनों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, जिसके चलते वे अपनी मर्ज़ी से अपने ऊपर एक भी पैसा ख़र्च नहीं कर पातीं. यह एक कड़वी सच्चाई है कि मुस्लिम महिलाओं की बदहाली के लिए धार्मिक कारण काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं. इनमें बुर्क़ा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा और तलाक़ के मामले मुख्य रूप से शामिल हैं. लड़कों की शिक्षा के बारे में मुस्लिम अभिभावकों का तर्क होता है कि पढ़-लिख लेने से कौन सी उन्हें सरकारी नौकरी मिल जानी है. फिर पढ़ाई पर क्यों पैसा बर्बाद किया जाए? बच्चों को किसी काम में डाल दो, सीख लेंगे तो ज़िंदगी में कमा-खा लेंगे. वहीं लड़कियों के मामले में वे कहते हैं कि ससुराल में जाकर चूल्हा-चौका ही तो संभालना है. इसलिए बेहतर है कि लड़कियां सिलाई-कढ़ाई और घर का कामकाज सीख लें. ससुराल में यह तो नहीं सुनना पड़ेगा कि मां ने कुछ सिखाया नहीं.

मुरादाबाद निवासिनी 50 वर्षीय कामिनी सिद्दीक़ी बताती हैं कि वह पढ़ना चाहती थीं, लेकिन परिवारीजनों ने उनकी पढ़ाई बीच में ही रोक दी. वह पांचवीं कक्षा में पढ़ती थीं, तभी उनका पर्दा करा दिया गया. उनसे कहा गया कि वह सिर्फ़ घर के कामकाज सीखें, ससुराल में यही सब काम आएगा. पढ़ा-लिखाकर कौन सी नौकरी करानी है. उन्हें इस बात का मलाल है कि वह पढ़ नहीं पाईं, लेकिन वह अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाना चाहती हैं. उनकी चार बेटियां हैं और चारों पढ़ रही हैं. उन्होंने कहा कि वह अपनी बेटियों के साथ वह सब नहीं होने देंगी, जो उनके साथ हुआ. शबाना और निशात ने पिछले साल ही दसवीं की परीक्षा पास की है. वे बताती हैं कि ग़रीबी की वजह से उनके अभिभावक उन्हें तालीम दिलाने में सक्षम नहीं थे. इसलिए उन्होंने अपनी मां के साथ बीड़ियां बनाकर अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाए. उनका कहना है कि सभी लड़कियों को तालीम हासिल करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा ज़िंदगी को बेहतर बनाती है. अब वे ब्यूटीशियन का कोर्स करके ख़ुद का ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हैं. राजमिस्त्री का काम करने वाले अली मुहम्मद ने अपनी चारों बेटियों को अच्छी तालीम दी है. उनकी दो बेटियां दसवीं पास हैं और दो ने बीए तक पढ़ाई की. वह कहते हैं कि अभिभावक अपनी बेटियों के लिए दहेज इकट्ठा करते हैं, लेकिन हमने ऐसा न करके इनकी शिक्षा पर पैसा ख़र्च किया. शिक्षा ही मेरी बेटियों का ज़ेवर है, जो सारी उम्र इनके काम आएगा. चारों बहनें घर पर ज़रदोजी का काम भी करती हैं. वे कहती हैं कि पहले बिचौलिए से काम लिया करती थीं, मगर अब ख़ुद दुकानदारों से सीधा संपर्क करती हैं, जिससे उन्हें पहले से ज़्यादा मुनाफ़ा होता है, क्योंकि बिचौलिया उन्हें बहुत कम पैसे देता था.

हालांकि इस्लाम में शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया है. इसके बावजूद मुस्लिम समाज के रहनुमाओं ने शिक्षा पर कोई विशेष ज़ोर नहीं दिया, जिसके चलते वह पिछड़ता चला गया. मौलाना ख़ालिद रशीद फिरंगी महली ने भी एक फ़तवा जारी करके कहा है कि शिक्षा हासिल करना हर मुसलमान के लिए अनिवार्य है, चाहे वह पुरुष हो या महिला. मुसलमानों को चाहिए कि वे लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि एक पढ़ी-लिखी महिला पूरे परिवार को शिक्षित कर सकती है. औलाद की बेहतर परवरिश के लिए मां का शिक्षित होना बेहद ज़रूरी है. उनका कहना है कि मौजूदा दौर में मुसलमानों के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण उनका शिक्षा में पीछे होना है. एक हदीस में भी कहा गया है कि एक मर्द ने पढ़ा तो समझो एक व्यक्ति ने पढ़ा और अगर एक महिला पढ़ी तो समझो एक परिवार, एक ख़ानदान पढ़ा. फ़तवे में यह भी कहा गया है कि इस्लाम ही एक ऐसा मज़हब है, जिसने औलाद तो औलाद, नौकरानियों को भी शिक्षित करने पर ज़ोर दिया है. इससे ज़ाहिर है कि मुस्लिम लड़कियों को जानबूझ कर शिक्षा से दूर रखने की कोशिश की गई, ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक न हो सकें. हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) के दौर में महिलाएं मस्जिदों में जाकर नमाज़ पढ़ती थीं. अनगिनत युद्धों में महिलाओं ने अपने युद्ध कौशल का लोहा भी मनवाया. प्रसिद्ध औहद की जंग में जब हज़रत मुहम्मद ज़ख्मी हो गए तो उनकी बेटी फ़ातिमा ने उनका इलाज किया. उस दौर में भी रफ़ायदा और मैमूना नाम की प्रसिद्ध महिला चिकित्सक थीं. रफ़ायदा का तो मैदान-ए-नबवी में अस्पताल भी था, जहां गंभीर मरीज़ों को दाख़िल किया जाता था. मुस्लिम महिलाएं शल्य चिकित्सा भी करती थीं. उम्मे-ज़ियाद, शाज़िया, बिन्ते माऊज़, मआज़त-उल-अपगरिया, अतिया असरिया और सलीम अंसारिया आदि उस ज़माने की प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक थीं. मैदान-ए-जंग में महिला चिकित्सक भी पुरुषों जैसी वर्दी पहनती थीं. हज़रत मुहम्मद की पत्नी ख़दीजा कपड़े का कारोबार करती थीं. महिला संत राबिया बसरी की ख्याति दूर-दूर तक फैली थी. पुरुष संतों की तरह वह भी धार्मिक सभाओं में शिरकत करती थीं. सियासत में भी महिलाओं ने सराहनीय काम किए. रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली महिला शासक बनीं. नूरजहां भी अपने वक़्त की ख्यातिप्राप्त राजनीतिज्ञ रहीं, जो शासन का अधिकांश कामकाज देखती थीं. 1857 की जंगे-आज़ादी में कानपुर की हर दिल अज़ीज़ नृत्यांगना अज़ीज़न बाई सारे ऐशो-आराम त्याग कर देश को गुलामी की ज़ंजीरों से छुड़ाने के लिए मैदान में कूद पड़ीं. उन्होंने महिलाओं के समूह बनाए, जो मर्दाना वेश में रहती थीं. वे सभी घोड़ों पर सवार होकर और हाथ में तलवार लेकर नौजवानों को जंगे-आज़ादी में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करती थीं. अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हज़रत महल ने हिंदू-मुस्लिम एकता को मज़बूत करने के लिए उत्कृष्ट कार्य किए.

मौजूदा दौर में भी विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं अपनी योग्यता का परिचय दे रही हैं. तुर्की जैसे आधुनिक देश में ही नहीं, बल्कि कट्टरपंथी समझे जाने वाले पाकिस्तान और बांग्लादेश सरीखे देशों में भी महिलाओं को प्रधानमंत्री तक बनने का मौक़ा मिला. वाक़ई यह एक ख़ुशनुमा अहसास है कि मज़हब के ठेकेदारों की तमाम बंदिशों के बावजूद मुस्लिम महिलाएं आज राजनीति के साथ खेल, व्यापार उद्योग, कला, साहित्य, रक्षा और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में भी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं. जम्मू-कश्मीर के कुलाली-हिलकाक इलाक़े की मुनिरा बेगम ने आतंकवादियों का मुक़ाबला करने के लिए बंदूक़ उठा ली.

उन्हीं के नक्शे-क़दम पर चलते हुए सूरनकोट के गांव की अन्य महिलाओं ने भी हथियार उठाकर आतंकवादियों से अपने परिजनों की रक्षा करने का संकल्प लिया. जम्मू-कश्मीर के राजौरी ज़िले के कालसी गांव की रुख़साना क़ौसर ने आतंकवादियों को मार कर यह संदेश दिया कि देश में वीरांगनाओं की कोई कमी नहीं है. पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम की शबनम आरा ने तमाम अवरोधों को पार करके क़ाज़ी का पद संभाला. केरल के नावैकुलम की शाजीना ने केरल विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए की उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने परिवार का नाम रौशन किया. पश्चिम बंगाल की पपिया सुल्ताना वहां की पहली महिला पुलिस अधिकारी बनीं. एमबीए की डिग्री हासिल कर पपिया ने राज्य पुलिस सेवा की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी. उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा अपनी मां सलमा से मिली, जो मदरसे में शिक्षिका हैं. पपिया का कहना है कि उनके माता-पिता खुले विचारों के हैं और उन्हीं के सहयोग से आज वह इस मुक़ाम तक पहुंच पाई हैं.

यह एक ख़ुशनुमा अहसास है कि पिछले कुछ बरसों में स्कूलों में दाख़िला लेने वाले मुस्लिम बच्चों, ख़ासकर लड़कियों की तादाद बढ़ रही है. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ प्राथमिक स्तर यानी पांचवीं तक की कक्षाओं में 1.483 करोड़ मुस्लिम बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. यह संख्या प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में दाख़िला लेने वाले कुल 13.438 करोड़ बच्चों की 11.03 फ़ीसदी है. वर्ष 2007-08 में यह दर 10.49 फ़ीसदी थी, जबकि 2006-07 में यह कुल दाख़िल बच्चों का 9.39 फ़ीसदी थी. इन कक्षाओं में पढ़ रहे कुल मुस्लिम छात्रों में 48.93 फ़ीसदी लड़कियां शामिल हैं. उच्च प्राथमिक कक्षाओं में भी मुस्लिम बच्चों की तादाद में इज़ाफ़ा हुआ है. यह संख्या कुल दाख़िले की 9.13 फ़ीसदी है. क़ाबिले ग़ौर यह भी है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में लड़कियों की संख्या मुस्लिम छात्रों की तादाद की 50.03 फ़ीसदी है, जबकि सभी वर्ग की लड़कियों के उच्च प्राथमिक कक्षा में कुल दाख़िले महज़ 47.58 फ़ीसदी हैं. यह रिपोर्ट देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के 633 ज़िलों के 12.9 लाख मान्यता प्राप्त स्कूलों से एकत्रित जानकारी पर आधारित है. यह आंकड़े मुस्लिम समाज में बदलाव के प्रतीक हैं. पिछले कुछ अरसे से मुस्लिम समाज में भी तालीम की बयार बहने लगी है. इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि आने वाला वक़्त मुस्लिम महिलाओं के लिए शिक्षा की रौशनी से जगमगाती सुबह लेकर आएगा.

फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

feedback@chauthiduniya.com

Lambda Group at a Glance

LETL

LAMBDA MICROWAVES PVT. LTD.

LAMBDA MICROWAVE TECHNOLOGIES

ARIALCOM

TEK 41 SOLUTIONS

LETL

LAMITEK SYSTEMS PVT. LTD.

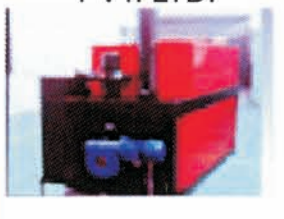

ARB BEARINGS

असम में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती पुनर्वापसी की है. हालांकि विपक्ष के बिखराव का नफा जहां कांग्रेस को मिल सकता है, वहीं असम गण परिषद एकजुट तो भले हो गई.

विधानसभा चुनाव 2011

वामपंथ का भविष्य तय हो जाएगा

शशि शेखर

चौथी दुनिया के लिए लिखे अपने एक आलेख में सीपीआई के महासचिव ए बी बर्धन ने कहा था कि वोट के ज़रिए जनता सरकार को तो सबक सिखाती ही है, जनता सड़क पर उतर कर भी अपना विरोध दर्ज कराती है. यहां इस बात का उल्लेख इसलिए भी ज़रूरी है कि एक बार फिर जनता को अपने वोट की ताक़त आजमाने का मौक़ा मिला है. अब यह ताक़त पांच राज्यों में बैठी सरकारों को सबक सिखाएगी या अपनी भूमिका ठीक से न निभाने के लिए विपक्ष को, यह तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इसके साथ ही अगले दो महीनों में यह भी तय हो जाएगा कि इस देश में वामपंथ की धारा बहती रहेगी या सूख जाएगी. नंदीग्राम और सिंगूर मसले पर तो जनता सड़क पर भी उतरी और अब बारी वोट की है. केरल में भी वामपंथी पार्टी अंदरूनी कलह में ज़्यादा उलझी हुई है. पिछले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य में वामपंथी दलों द्वारा ममता बनर्जी के हाथों शिकस्त खाने के बाद इस बात की संभावना ज़्यादा दिख रही है कि यह चुनाव कहीं वामपंथी दलों के लिए वाटरलू न बन जाए.

बहरहाल, पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव अपने साथ कई चुनौतियां भी लेकर आ रहे हैं. यह चुनौती राजनीतिक दलों के लिए तो है ही, साथ ही मतदाताओं के लिए भी है. मतदाताओं के लिए इसलिए, क्योंकि उन्हें एक ऐसी सरकार चुननी है, जो सचमुच उनकी हो, उनके लिए सोचे और उनके लिए काम करे. इसके अलावा एक बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के लिए भी है. ख़ासकर, नक्सल प्रभावित पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करना ही चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगा. बंगाल के ज़्यादातर इलाक़ों में नक्सलियों का प्रभाव है. नक्सली चुनाव का बहिष्कार करते हैं. आम आदमी को हथियार का भय दिखाकर मतदान केंद्र तक जाने से रोकते हैं. मतदानकर्मियों के अपहरण, बम विस्फोट कर माहौल में भय पैदा करने जैसे प्रयासों से चुनाव आयोग को दो–चार होना पड़ेगा. हालांकि इस मामले में नवंबर 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव से थोड़ी आशा जगती है, जब नक्सलियों की लाख कोशिशों के बाद भी वहां मतदाता घर से बाहर निकले और मतदान केंद्र तक पहुंचे. लिहाज़ा इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को भी भयमुक्त वातावरण में संपन्न करा लेने में सफल रहेगा.

यह चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए भी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा. वजह, एक ओर महंगाई तो दूसरी ओर घोटालों का प्रेत कांग्रेस का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है और इस सबके बीच चुनाव. तमिलनाडु में डीएमके के साथ गठबंधन का कितना फ़ायदा कांग्रेस उठा पाएगी, कहना मुश्किल है. ए राजा से लेकर कनिमोझी के एनजीओ पर पड़े छापे जैसे मुद्दों को अगर जयललिता भुना ले जाती हैं तो न सिर्फ़ डी एम के, बल्कि कांग्रेस को भी नुक़सान उठाना पड़ सकता है. एक अहम मुद्दा दलित ईसाइयों एवं दलित मुसलमानों का है. यानी रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफ़ारिशों, जिनमें दलित ईसाइयों एवं दलित मुसलमानों को आरक्षण देने की बात शामिल है, पर यूपीए की ख़ामोशी का जवाब भी दलित ईसाई और दलित मुसलमान इस चुनाव में मांगेंगे. पश्चिम बंगाल, असम और केरल में भी कुछ ऐसे ही सवालों से कांग्रेस का सामना होगा. बंगाल में तो वैसे भी सीधी लड़ाई वामदलों और तृणमूल कांग्रेस के बीच होने की संभावना है. इस लिहाज़ से देखें तो बिहार के बाद कांग्रेस का जनाधार एक और बड़े राज्य से घटने की संभावना है. पश्चिम बंगाल, केरल और असम में मुसलमानों की अच्छी–खासी संख्या है. यहां इनकी आबादी 24 से 30 फ़ीसदी तक है. असम में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती पुनर्वापसी की है. हालांकि विपक्ष के बिखराव का नफा जहां कांग्रेस को मिल सकता है, वहीं असम गण परिषद एकजुट तो भले हो गई, लेकिन वह समूचे विपक्ष को एकजुट कर पाने में असफल रही. असम में एक और राजनीतिक दल ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है. 2006 के विधानसभा चुनाव में इस पार्टी को दस सीटें मिली थीं. ऐसा माना जाता है कि इस दल को मुसलमानों का अच्छा–खासा समर्थन हासिल है. ज़ाहिर है, इस बार के विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट रंगनाथ मिश्र आयोग और सच्चर कमेटी की सिफ़ारिशों को मुद्दा बनाकर कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है. ख़ैर, इन पांच राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में सबसे दिलचस्प मुक़ाबला पश्चिम बंगाल में होने वाला है. राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ देश की कई राजनीतिक धाराओं को दशा और दिशा देने जा रहा है. यहां किसी एक की जीत दूसरे के राजनीतिक भविष्य को इस कदर बिगाड़ सकती है, जिसकी महज़ कल्पना ही की जा सकती है. सबसे बड़ी चुनौती तीन दशकों से भी ज़्यादा समय से पश्चिम बंगाल में शासन कर रहे वाममोर्चा के लिए है. नंदीग्राम और सिंगूर के मोर्चे पर शिकस्त खाने के बाद वाममोर्चा को अपना जनाधार खिसकता हुआ दिखने लगा था. सो, इसकी भरपाई के लिए सरकारी कवायद भी शुरू कर दी गई थी. बिहार से सीख लेते हुए बंगाल में पंचायतों की 50 फ़ीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का फ़ैसला लिया गया. सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित 7 प्रतिशत आरक्षण को 17 प्रतिशत करके उसमें पिछड़े मुस्लिमों को भी शामिल कर लिया गया.

ममता बनर्जी ने रेल मंत्री के नाते जिस ढंग से इस बार रेल बजट में बंगाल को तोहफ़े दिए, उससे दिख रहा था कि ममता ने यह बजट क्यों और किसे ध्यान में रखते हुए बनाया था, लेकिन ममता बनर्जी को यह भी याद रखना होगा कि वह जिस सरकार में मंत्री हैं, वही सरकार महंगाई, घोटालों और भ्रष्टाचार के लिए भी ज़िम्मेदार है और इस बार जनता की याददाश्त भी कमज़ोर नहीं रहने वाली. नतीजतन, यह मानना ग़लत होगा कि जनता आंख मूंदकर तृणमूल कांग्रेस को समर्थन दे देगी. फिर भी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम का इंतज़ार देश के हर वर्ग को बेसब्री से रहेगा, क्योंकि बंगाल की जनता को ही यह तय करना है कि देश में वामपंथ की धारा बहती रहेगी या फिर उसके लुप्त हो जाने का समय आ गया है.

shashishekhar@chauthiduniya.com

विधानसभा चुनाव–2006

किसे मिली थीं कितनी सीटें

पश्चिम बंगाल	
कुल सीटें	294
सीपीआई (एम)	176
सीपीआई	8
कांग्रेस	21
तृणमूल कांग्रेस	30
एआईएफबी	23
आरएसपी	20
असम	
कुल सीटें	126
भाजपा	10
कांग्रेस	53
अगप	28
एयूडीएफ	10
केरल	
कुल सीटें	140
सीपीआई	17
सीपीआई (एम)	61
कांग्रेस	24
जेडी (एस)	5
केईसी (एम)	7
एमयूएल	7
तमिलनाडु	
कुल सीटें	234
सीपीआई	6
सीपीआई (एम)	9
डीएमके	96
एआईएडीएमके	61
कांग्रेस	34
एमडीएमके	6
पीएमके	18
पुडुचेरी	
कुल सीटें	30
कांग्रेस	10
सीपीआई	1
एआईएडीएमके	3
डीएमके	7

चुनाव कार्यक्रम

पश्चिम बंगाल

पहला चरण	
अधिसूचना जारी होने की तारीख़	24 मार्च
मतदान	18 अप्रैल
दूसरा चरण	
अधिसूचना जारी होने की तारीख़	30 मार्च
मतदान	23 अप्रैल
तीसरा चरण	
अधिसूचना जारी होने की तारीख़	2 अप्रैल
मतदान	27 अप्रैल
चौथा चरण	
अधिसूचना जारी होने की तारीख़	7 अप्रैल
मतदान	3 मई
पांचवां चरण	
अधिसूचना जारी होने की तारीख़	11 अप्रैल
मतदान	7 मई
छठा चरण	
अधिसूचना जारी होने की तारीख़	14 अप्रैल
मतदान	10 मई
तमिलनाडु	
अधिसूचना जारी होने की तारीख़	19 मार्च
मतदान	13 अप्रैल
केरल	
अधिसूचना जारी होने की तारीख़	19 मार्च
मतदान	13 अप्रैल
असम	
पहला चरण	
अधिसूचना जारी होने की तारीख़	10 मार्च
मतदान	4 अप्रैल
दूसरा चरण	
अधिसूचना जारी होने की तारीख़	18 मार्च
मतदान	11 अप्रैल

पुडुचेरी

अधिसूचना जारी होने की तारीख़–19 मार्च
मतदान–13 अप्रैल

देश का पहला इंटरनेट टीवी

हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक

- दो टूक–संतोष भारतीय के साथ
- ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
- पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
- स्पेशल रिपोर्ट
- नायाब हैं हम–उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
- साई की महिमा

एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा–201301 www.chauthiduniya.tv

पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा इस कदर मारपीट किए जाने पर वहां मौजूद ग्रामीणों ने पुलिस पर जमकर पथराव करके पन्नालाल, उसकी पत्नी और दोनों बेटों को आज़ाद करा लिया.

महाराष्ट्र

सोनवणे की हत्या और राजुलवाड़ी का सच

राजेश तिवारी

नमाड़ में अतिरिक्त ज़िलाधिकारी यानी एडीएम सोनवणे को सरेआम जला दिया जाता है, मुंबई से नई दिल्ली तक खलबली मच जाती है. शासन–प्रशासन मानों अचानक नींद से जागता है, पूरे महाराष्ट्र में तेल माफ़ियाओं और मिलावटखोरों के ख़िलाफ़ छापामार कार्रवाई शुरू हो जाती है. मुंबई से मराठवाड़ा तक के क्षेत्र को तेल माफ़ियाओं का गढ़ बताकर उनके खिलाफ अभियान चलाया जाता है और मराठवाड़ा के बाद जहां से विदर्भ की सीमा लगती है, कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति शुरू हो जाती है. महाराष्ट्र की उप राजधानी नागपुर पहुंचते–पहुंचते कार्रवाई का स्वरूप काग़ज़ों और फाइलों में सिमट जाता है यानी सिर्फ़ संदिग्धों को थाने बुलाकर पूछताछ होती है.

इस समूची कवायद के बीच नागपुर ज़िले के उमरेड तहसील मुख्यालय के नज़दीक राजुलवाड़ी में कुछ ऐसा हो जाता है, जो कई प्रश्न अनुत्तरित छोड़ जाता है. यहां रहने वाले पारधी समाज के मुखिया पन्नालाल राजपूत के घर पर छापा मारकर पुलिस 120 लीटर मिट्टी का तेल ज़ब्त करती है. पारधी समाज के लोग पुलिस पर हमला करते हैं और फिर अतिरिक्त सुरक्षाबल बुलाया जाता है, जो कार्रवाई करते हुए कई घरों में तोड़–फोड़ करता है. बाद में शुरू होता है आरोप–प्रत्यारोप का दौर. इस पूरे उच्चस्तरीय ड्रामे में मिलावटखोरी का असल मुद्दा दब जाता है. तेल माफ़िया से साठगांठ रखने वाले भ्रष्ट अधिकारी और नेता चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि अब मुद्दा बदल गया है. अब मामला मिलावटखोरी पर कार्रवाई का नहीं है, बल्कि यह पुलिस बनाम पारधी समाज हो गया है. टोले में पुलिस गिरफ़्तारियां करती है, पन्नालाल को फ़रार बताया जाता है. दोनों पक्ष अपना दामन साफ–सुथरा रखने के लिए अब क़ानून और दुष्प्रचारों का सहारा ले रहे हैं. इस प्रचार युद्ध में कई प्रश्न सामने हैं. क्या पन्नालाल नक्सली है, क्या जब्त किया गया मिट्टी का तेल मिलावटखोरी के लिए रखा गया था, क्या आत्मरक्षा में पुलिस को इतनी बर्बर कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी नो कमेंट्स की स्थिति में क्यों हैं, क्या वहां के थानेदार ने बदले की कार्रवाई की, पुलिस बर्बर थी या पारधी समाज के लोग आक्रामक थे? ये ऐसे प्रश्न हैं, जिनके जवाब स्वस्थ शासन–प्रशासन के लिए ज़रूरी हैं.

बीती एक फरवरी को सुबह साढ़े आठ बजे जब राजुलवाड़ी पारधी टोले के निवासी अपनी नित्य क्रिया में मशगूल थे, तभी पुलिस उपाधीक्षक सुधाकर पालांदुरकर एवं उमरेड थाने के पुलिस निरीक्षक मधुकर गीते पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने पारधी समाज के मुखिया पन्नालाल राजपूत के घर में घुसकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया. पारधी समाज के लोगों का कहना है कि पुलिस ने पन्नालाल को मारना–पीटना शुरू कर दिया. पन्नालाल कुछ समझ पाता, इसके पहले ही उसके घर पर मिले 120 लीटर मिट्टी तेल के साथ उसे हिरासत में ले लिया गया. अचानक हुई कार्रवाई से पन्नालाल बौखला गया. उसने पुलिस को बताया कि उसके घर से ज़ब्त मिट्टी का तेल उसका नहीं, बल्कि ग्रामवासियों का है और प्रमाण के तौर पर उसने अपने पास मौजूद 42 राशनकार्ड भी दिखाए.

पुलिस ने उसकी एक नहीं मानी, जिससे मामला गर्माता गया. आरोप है कि पन्नालाल द्वारा कड़ा विरोध करने पर पुलिस ने ग्रामवासियों के सामने उसे अधनंगा करके मारना शुरू कर दिया. पन्नालाल को पिटता देख थोड़ी ही देर में उसकी पत्नी एवं दो बेटों के सब्र का बांध टूट गया और वे पुलिस अधिकारियों से भिड़ गए. आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस ने पन्नालाल की पत्नी को घसीटते हुए बाल पकड़ कर उसे मारना शुरू किया. पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा इस कदर मारपीट किए जाने पर वहां मौजूद ग्रामीणों ने पुलिस पर जमकर पथराव करके पन्नालाल, उसकी पत्नी और दोनों बेटों को आज़ाद करा लिया. क़रीब आधा घंटे तक चले इस एपिसोड के बाद संख्या में कम होने की वजह से पुलिस बल को वहां से भागना पड़ा. बताते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी पन्नालाल पुलिस पर भारी पड़ गया था. पुलिस के मैदान छोड़ते ही ग्रामीणों ने सभी पुलिस वाहनों को जमकर क्षति पहुंचाई. उपाधीक्षक पलांदुरकर एवं पुलिस निरीक्षक मधुकर गीते की सूमो जीप सहित कई वाहनों में तोड़–फोड़ करके उन्हें जलाने का प्रयास किया गया, लेकिन थोड़ी ही देर में दोबारा पुलिस बल पहुंच जाने से यह भीषण हादसा होते–होते बच गया. अतिरिक्त बल के पहुंचते ही पुलिस दोबारा हरकत में आई. उसने जमकर लाठियां भांजी. ग्रामवासियों को चौराहे पर इकट्ठा करके उन्हें सरेआम पीटने का आरोप भी पुलिस पर लगा है. कई घरों में मौजूद आलमारियों को तोड़कर उनमें से नकदी और गहने निकाले जाने का आरोप भी राजुलवाड़ी निवासी लगा रहे हैं. साथ ही बर्तन, कपड़े एवं टीवी जैसे सामान तोड़ दिए गए. गांव में खड़े दुपहिया–तिपहिया वाहनों को भी पुलिस ने नहीं छोड़ा.

पन्नालाल का भी पुराना रिकार्ड कुछ अच्छा नहीं है. पुलिस का कहना है कि पन्नालाल आपराधिक प्रवृत्ति का है. आज पन्नालाल भले ही लोगों की सहानुभूति का पात्र हो, कई सामाजिक संगठन उसे पारधी समाज का हीरो मानकर उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन हक़ीक़त में ऐसा नहीं हैं. कुछ जानकार तो इस कहानी को अलग रूप में देखते हैं. बताते हैं कि इसके पहले भी उसने कई दफा शराब अड्डे पर छापा मारने पहुंची उमरेड पुलिस पर जानलेवा हमले किए थे. बदनामी के डर से पुलिस ने ही मामला दबा दिया. इसी वजह से पुलिस और पन्नालाल के बीच शीतयुद्ध जारी था. पन्नालाल पर अवैध तरीक़े से शराब का व्यवसाय करने के 14–15 मामले उमरेड पुलिस थाने में दर्ज हैं. पिछले कई बरसों से उसने लगातार इन अवैध धंधों से लाखों की संपत्ति जोड़ ली है. यशवंत सोनवणे को आग के हवाले किए जाने के बाद राज्य भर में मिलावटखोरी के ख़िलाफ़ छापेमारी शुरू की गई है. ऐसा नहीं है कि इसके पहले इन अवैध धंधों को बंद करने जैसे आदेश सरकार ने पुलिस को नहीं दिए थे, लेकिन इस बार कार्रवाई मजबूरी थी. बड़े नाम तो सामने नहीं आए, पर छुटभइये तेल और शराब माफियाओं पर कार्रवाई ज़रूर की गई. इसी चपेट में पन्नालाल भी आ गया. पारधी समाज की कहानी अजीब है. पारधी नाम पारध शब्द से निकला है. पारध यानी शिकार करने वाला. अब पारधी भी कई तरह के होते हैं. पुराने जमाने में यह समाज राजाओं का सुरक्षा सलाहकार हुआ करता था. यह दुनिया की सबसे ख़ुफ़िया और ईमानदार जमातों में से एक है. इसने कई छापामार लड़ाइयां लड़ीं और जीतीं. ख़ुद शिवा जी भी इस समाज की युद्ध शैली से प्रभावित थे. अंग्रेज जब बार–बार और छापामारी अंदाज़ वाले हमलों से परेशान हो गए तो उन्होंने पारधियों को अपराधी घोषित कर दिया. दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि अपराधी का वह लेबल आज भी इस जमात के साथ चिपका हुआ है. महाराष्ट्र के गांवों में बस्ती से दूर किसी टीलेनुमा या समतल ज़मीन पर पारधी समाज के लोग आज भी रहते हैं. ये समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से पूरी तरह कटे हुए हैं और इनमें शिक्षा का अभाव साफ़ दिखता है.

feedback@chauthiduniya.com

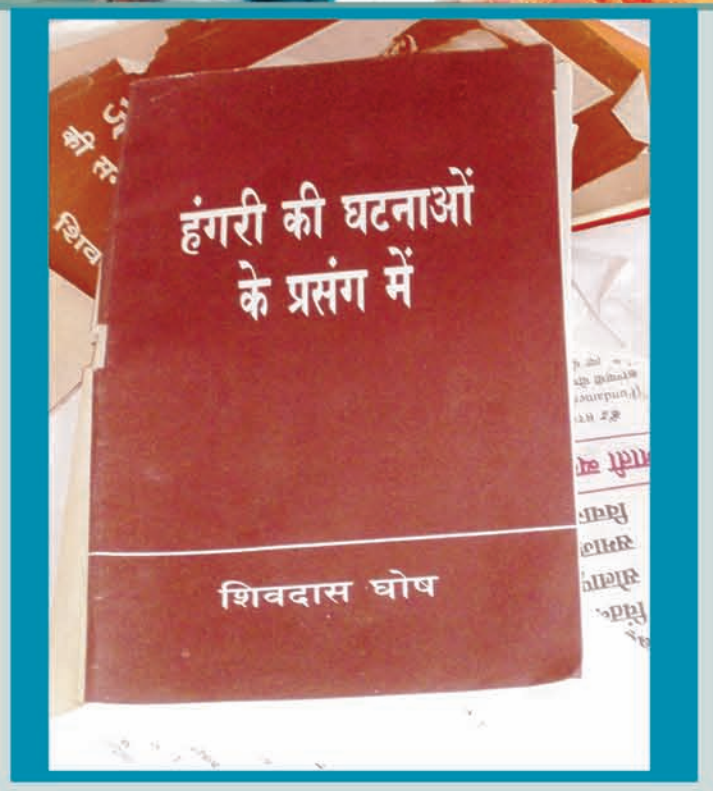

नक्सली होने का आरोप कितना सही

समूचे घटनाक्रम के बाद पुलिस ने पन्नालाल पर नक्सली होने का शक भी ज़ाहिर किया है. पुलिस का दावा है कि उसके घर में खोजबीन के दौरान नक्सली साहित्य बरामद किया गया. इस संबंध में पन्नालाल की बहू का कहना है कि वह पारधी समाज पर शोध कर रही है. हालांकि उसने अपने गाइड का नाम नहीं बताया. कहा जाता है कि आग लगती है, तभी धुआं उठता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि पारधी समाज के गुण–दोष, उनका सामाजिक स्तर, लोकतंत्र में उनकी नगण्य भागीदारी आदि कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जो उन्हें कभी भी नक्सलियों के क़रीब ला सकते हैं. नक्सलियों केसमूचे इतिहास पर नज़र डालें तो इस प्रकार की जनजातियों के लोग हमेशा उनके सॉफ्ट टार्गेट रहे हैं. अगर इस आरोप में थोड़ी भी सच्चाई है तो मामला और भी संगीन हो जाता है तथा इसे पुलिस की बर्बरता एवं पन्नालाल के रिकार्ड जैसी सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता. विदर्भ, मराठवाड़ा, खानदेश एवं सोलापुर तक पारधी समाज की मौजूदगी है. छापामार लड़ाई में यह समाज परंपरागत रूप से माहिर रहा है, इसका अगर माओवादियों के साथ गठजोड़ हो गया तो यह पूरे राज्य के लिए एक बड़ा ख़तरा साबित होगा. नागपुर ज़िले के पुलिस अधीक्षक छत्रपति वाकड़े ने तो घटना के संबंध में कोई भी टिप्पणी करने से इंकार कर दिया, लेकिन क्षेत्रीय विधायक सुधीर पारवे पन्नालाल पर लगे आरोपों को सिरे से ख़ारिज करते हैं. पारवे कहते हैं कि यह सीधे तौर पर पुलिस का मामला है. नक्सली या फिर तेल माफ़िया जैसे आरोपों में कोई दम नहीं है.

मेरी दुनिया.... प्रणब का बजट 2011 ...धीर

मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय एवं असम में विगत कुछ वर्षों से नशीले पदार्थों की तस्करी बढ़ी है. विशेषकर युवा वर्ग तेजी से इसकी गिरफ़्त में आता जा रहा है.

दाग़ी मंत्री जनादेश का अपमान

उपेंद्र चौहान

सरोज सिंह

बिहार की नीतीश सरकार में शामिल दागी मंत्रियों को लेकर विपक्ष का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया है. विपक्षी नेताओं का मानना है कि इस तरह की कैबिनेट जनादेश का अपमान है. इन नेताओं की एकमत से राय है कि स्पीडी ट्रायल चलाकर इन मंत्रियों पर लगे आरोपों की सुनवाई हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और बिहार की छवि बेहतर बने. राजद सांसद राम कृपाल यादव ने तेवर कड़े करते हुए कहा कि बिहार की जनता देखे कि उसने नीतीश कुमार को क्या समझा और वह क्या निकले. विकसित बिहार बनाने का सपना दागी लोगों से कैसे पूरा हो सकता है. दागदार कैबिनेट बनाकर नीतीश कुमार ने बिहार की छवि को धक्का पहुंचाया है. इस सरकार से भाषण के अलावा और किसी चीज की उम्मीद नहीं की जा सकती है. कभी नीतीश के काफी क़रीबी रहे, मगर अब राजद खेमे के मज़बूत स्तंभ राम बिहारी सिंह का कहना है कि नीतीश कुमार ने जो कैबिनेट बनाई है, उससे साफ़ हो जाता है कि उन्हें अपनी छाया में रहने वाले लोग पसंद हैं, चाहे उन पर कितने भी गंभीर मामले क्यों न चल रहे हों.

जदयू सांसद उपेंद्र कुशवाहा की राय में यह राजनीतिक दिवालियापन की निशानी है. चुनाव में एक से एक साफ-सुथरी छवि वाले नेता जीतकर आए हैं, पर उन्हें तवज्जो न देकर दागी नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी गई. नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं गठबंधन को मजबूरी बनने नहीं दूंगा, चाहे मेरी सरकार ही क्यों न चली जाए.

राघवेंद्र

रामकृपाल

नीतीश कुमार को अलोकतांत्रिक बताते हुए वह कहते हैं कि उनमें अहंकार की भावना कूट-कूटकर भरी है. नीतीश कुमार को काम करने वाले मंत्री नहीं, बल्कि दरबारी चाहिए. इसलिए उन्होंने कैबिनेट बनाते समय मंत्रियों पर चल रहे मामलों का ख्याल नहीं रखा. जिन्होंने उनकी दरबारी स्वीकार नहीं, उन्हें उन्होंने पार्टी में हाशिए पर डाल दिया या फिर पार्टी से ही निकाल दिया. राम बिहारी सिंह कहते हैं कि नीतीश के काम करने का जो तरीक़ा है या फिर वह जिस दिशा में जा रहे हैं, उससे लोकतंत्र की नींव कमज़ोर हो रही है. नीतीश इंदिरा गांधी की राह पर नहीं, बल्कि लीबिया के कर्नल गद्दाफी और मिस्र के होस्नी मुबारक की राह पर चल रहे हैं. राम बिहारी सिंह कहते हैं कि तानाशाही का अंत तय है, नीतीश के लोग ही नीतीश का विकल्प बनेंगे.

जदयू सांसद उपेंद्र कुशवाहा की राय में यह राजनीतिक दिवालियापन की निशानी है. चुनाव में एक से एक साफ-सुथरी छवि वाले नेता जीतकर आए हैं, पर उन्हें तवज्जो न देकर दागी नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी गई. नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं गठबंधन को मजबूरी बनने नहीं दूंगा, चाहे मेरी सरकार ही क्यों न चली जाए. भाजपा के दागी चेहरे को भी उन्होंने मंत्री बना दिया तो क्या यह नहीं माना जाए कि वह गठबंधन को लेकर दबाव में हैं. आख़िर कौन सी मजबूरी है, जो ऐसे लोगों की कैबिनेट बन रही है, जिन पर बहुत सारे मामले चल रहे हैं. केवल भाषणों से भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती. भाषण सुनने में तो अच्छा लगता है, पर भ्रष्टाचार की जड़ें बढ़ती ही जा रही हैं. मंत्रियों को केवल संपत्ति की ही घोषणा नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी आय के स्रोत भी बताने चाहिए. बिना इसके सब बकवास है.

पूर्व विधान पार्षद पी के सिन्हा कहते हैं कि जो जैसा होता है, वैसा ही पसंद करता है. नीतीश कुमार की कैबिनेट में शामिल दागी मंत्रियों को बिना समय गंवाए स्पीडी ट्रायल से गुज़ारा जाना चाहिए. लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वह कभी बड़ी मछली पर हाथ नहीं लगाते. निगरानी के छापे एक-दो मामलों को छोड़कर कभी बड़े अफसरों के घरों में नहीं पड़े. स्पीडी ट्रायल से कौन गुज़र रहा है, सभी जानते हैं. लोजपा के प्रधान महासचिव राघवेंद्र सिंह कुशवाहा का कहना है कि नीतीश कुमार ने जो कैबिनेट बनाई है, उससे साफ़ हो जाता है कि उन्हें कमज़ोर लोग पसंद हैं, चाहे उन पर जितने भी गंभीर आरोप क्यों न हों. स्वतंत्र विचार रखने वाले नेता उनकी पसंद हो नहीं सकते. बिहार के केवल 39 फ़ीसदी लोगों ने ही नीतीश कुमार को पसंद किया है, इसलिए उन्हें इस गुमान में नहीं रहना चाहिए कि सारा बिहार उन्हें पसंद कर रहा है. राघवेंद्र ने मांग की कि स्पीडी ट्रायल चलाकर मंत्रियों के मामलों को निपटाया जाए. जदयू नेता उपेंद्र चौहान मानते हैं कि मामले को बेवजह इतना तूल दिया जा रहा है. मंत्रियों ने ख़ुद अपने शपथपत्र में ख़ुद पर चल रहे मामलों की जानकारी दी है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है. ऐसा कोई बड़ा आरोप नहीं है कि बखेड़ा खड़ा किया जाए. दरअसल विपक्ष नीतीश कुमार के विकास कार्यों से घबरा गया है, उसके सामने कोई मुद्दा ही नहीं है.

नेताओं ने तो पार्टी के हिसाब से अपनी-अपनी राय दी, लेकिन आम लोगों ने चर्चा के दौरान इस बात पर अफसोस जताते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार साफ-सुथरी कैबिनेट बनाते तो ज़्यादा बेहतर होता.

feedback@chauthiduniya.com

रामबिहारी सिंह

उपेंद्र कुशवाहा

पीके सिन्हा

पूर्वोत्तर नशे के सौदागरों पर अंकुश ज़रूरी

अरुण कुमार झा

असम एवं पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में नशे के सौदागर अपना जाल बड़ी तेज़ी से फैला रहे हैं. अगर इन्हें शीघ्र ही रोका न गया तो आने वाले वर्षों में यह पूरा इलाक़ा नशीले पदार्थों की तस्करी का मुख्य केंद्र बन जाएगा. अभी हाल में असम पुलिस ने गुवाहाटी से सटे जुरसीमौला गांव में क़रीब सात एकड़ भूमि पर लगी गांजे की फ़सल नष्ट कर दी. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की पहल के चलते ही ऐसा संभव हो सका. युवाओं को नशे की लत लगाकर उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर बनाया जा रहा है. नशीले पदार्थों की खेती से किसानों को शुरू में तो अच्छी क़ीमत मिलती है, लेकिन वे यह नहीं समझ पाते कि ऐसी खेती कुछ ही वर्षों में उनके खेतों की उर्वरा शक्ति क्षीण करके उन्हें बंजर बना देती है और फिर वे भूखे मरने के लिए विवश हो जाते हैं. पूर्वोत्तर में नशे के सौदागरों की इस साजिश को समय रहते नाकाम करना होगा. इनके तार देश के अन्य भागों में भी फैले हुए हैं.

पिछले वर्ष मध्य प्रदेश के मंदसौर से एक युवक-युवती को तीन करोड़ रुपये मूल्य की स्मैक के साथ पकड़ा गया था. बताया गया कि दोनों नशीले पदार्थों की तस्करी करते थे. इस गिरफ़्तारी से एक बार फिर साबित हुआ कि यहां भी नशे के सौदागर सक्रिय हैं और उन्होंने अपना जाल पूरे देश में फैला रखा है. सेना और सुरक्षाबल के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, मादक पदार्थों की तस्करी के माध्यम से पूर्वोत्तर इलाक़े में सक्रिय तमाम विद्रोही संगठन अपने लिए हथियार एवं विस्फोटक ख़रीदते हैं. इस काम में सीमा पार की कुछ ताक़तों की अहम भूमिका होती है. पूर्वोत्तर के अधिकांश उग्रवादी गुट उन्हीं के इशारे पर अपनी गतिविधियां चलाते हैं. ऐसे में नशे के सौदागरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई को लेकर सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. पूर्वोत्तर के राज्यों की भौगोलिक स्थिति भी कुछ ऐसी है कि उनकी सीमाएं चीन, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश से मिली हुई हैं. इन देशों के रास्ते नशे के सौदागर अपना धंधा यहां आसानी से चला रहे हैं.

मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय एवं असम में विगत कुछ वर्षों से नशीले पदार्थों की तस्करी बढ़ी है. विशेषकर युवा वर्ग तेजी से इसकी गिरफ़्त में आता जा रहा है. कुछ माह पूर्व गुवाहाटी एवं डिब्रूगढ़ में मादक पदार्थों का धंधा करने वाला एक गिरोह पकड़ा गया था, जिसके पास से हीरोइन, ब्राउन सुगर और नशे की गोलियां बरामद की गई थीं. पुलिस के अनुसार, मणिपुर और नागालैंड में सक्रिय गिरोह असम में मादक पदार्थों की आपूर्ति काफी गोपनीय तरीक़े से करते हैं. नशीले पदार्थों के तस्कर मुख्य रूप से भारत-म्यांमार सीमा क्षेत्र से अपना कारोबार चलाते हैं. गुवाहाटी में भी उनके एजेंट हैं, जो उनके इशारे पर काम करते हैं. पूर्वोत्तर में म्यांमार और चीन की सीमा से नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल एवं मिजोरम की सीमाएं जुड़ी हैं. असम, मेघालय एवं त्रिपुरा की सीमाएं बांग्लादेश और भूटान से जुड़ी हैं. कुल मिलाकर देखा जाए तो पूर्वोत्तर के अधिकांश राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं.

मणिपुर और नागालैंड में सक्रिय गिरोह असम में मादक पदार्थों की आपूर्ति काफ़ी गोपनीय तरीक़े से करते हैं. नशीले पदार्थों के तस्कर मुख्य रूप से भारत-म्यांमार सीमा क्षेत्र से अपना कारोबार चलाते हैं. गुवाहाटी में भी उनके एजेंट हैं, जो उनके इशारे पर काम करते हैं.

इस पूरे क्षेत्र में चीन, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश के रास्ते मादक पदार्थों की तस्करी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र की मादक पदार्थ एवं अपराध निरोधक शाखा ने असम सरकार को सहायता देने की पेशकश की है. इस पहल से साफ़ हो जाता है कि क्षेत्र में मादक पदार्थों की बढ़ती तस्करी को लेकर विश्व मंच भी चिंतित है. कुछ वर्ष पूर्व गुवाहाटी में तरुण कुमार दत्त नामक एक केंद्रीय आबकारी अधिकारी, जो राजस्व ख़ुफ़िया अधिकारी के पद पर आसीन थे, की नशे के सौदागरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. दत्त की हत्या के बाद हुई अनेक लोगों की गिरफ़्तारी से इस बात का ख़ुलासा हुआ कि हत्याकांड के पीछे नशे के सौदागरों का हाथ था. तरुण कुमार दत्त ने अपने सात साल के कार्यकाल के दौरान क़रीब 40 करोड़ रुपये मूल्य के नशीले पदार्थ ज़ब्त किए थे. तस्कर उनकी कार्रवाइयों से परेशान हो चुके थे और इसी वजह से उन्होंने उन्हें अपने रास्ते से हटा दिया. दत्त की मौत यह साबित करती है कि क्षेत्र में सक्रिय नशे के सौदागर कितने ख़तरनाक हैं और वे अपने धंधे के लिए किस हद तक जा सकते हैं.

हाल के वर्षों में जो आंकड़े सामने आए हैं, उनसे पता चलता है कि पूर्वोत्तर का युवा वर्ग नशे की गिरफ़्त में तेज़ी से फंसता जा रहा है. ऐसे ही युवकों की मदद से इस कारोबार को फैलाया जा रहा है. असम के बाद मणिपुर और मिजोरम तस्करों के बड़े अड्डे बन चुके हैं. इन क्षेत्रों में एड्स जैसी घातक बीमारी भी युवा वर्ग को तेज़ी से अपनी गिरफ़्त में लेती जा रही है. मिजोरम में महिलाओं ने नशे के विरोध में मोर्चा खोल दिया है. जगह-जगह नशीले पदार्थों की होली जलाई जाती है. असम के लोगों को भी नशे के सौदागरों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी होगी, तभी सरकार हरक़त में आएगी. सीमावर्ती क्षेत्रों पर सख्त निगरानी से भी हम इस काले धंधे को रोकने में सफल हो सकते हैं.

feedback@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

आपका उपनाम क्या है

गोधरा पर आया फ़ैसला बहुत कुछ वैसा ही है, जैसा बाबरी मस्जिद पर. इसने किसी एक को ठीक वही नहीं दिया, जो वे चाहते थे और एक मायने में कुछ भी नहीं दिया. इसने सिर्फ़ राजनीति के अमानवीय चेहरों एवं राजनीतिक दलों द्वारा धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता के नाम पर बेवकूफ़ी भरा प्रदर्शन उजागर किया. अगर आप यू सी बनर्जी और नानावटी आयोग की रिपोर्ट को पढ़ें तो आपके लिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि क्या ये दोनों एक ही दुनिया के रहने वाले हैं? आख़िर धर्मनिरपेक्षतावादियों के लिए यह क्यों ज़रूरी है कि वे उन 59 लोगों की मौत को नज़रअंदाज़ कर दें, जो ट्रेन की बोगी में जलकर मर गए. बाद में यह साबित करने की कोशिश की गई कि वे ख़ुद जलकर मरे. क्या कारसेवक इंसान नहीं थे, भारतीय नहीं थे? और क्यों भाजपा, एनडीए एवं विश्व हिंदू परिषद वालों को यह नहीं महसूस हुआ कि 94 संदेहास्पद लोगों में से उन 63 लोगों से माफ़ी मांगी जाए, जिन्हें बिना ट्रायल के नौ साल तक जेल में रहना पड़ा. क्या भारत के अन्य समूहों की तरह मुस्लिमों को न्याय पाने का कोई हक़ नहीं है? गुजरात के मंत्रियों के कार्यालयों में गांधी जी की तस्वीर लगाने का चलन अभी-अभी शुरू हुआ है, लेकिन क्या ये लोग उन्हीं गांधी जी से यह नहीं सीख सकते कि कैसे सहानुभूति दिखाई जाती है?

धर्मनिरपेक्षवाद-सांप्रदायवाद के बंटवारे ने दोनों पक्षों के बीच की स्थिति और बिगाड़ी है और ऐसा करते वक़्त वे यह भूल जाते हैं कि इस वजह से कई जानें ख़तरे में पड़ जाती हैं. आज़ादी के साठ साल बाद भी इस देश में मुस्लिम पिछड़े हुए हैं और इसके पीछे वही लोग हैं, जो ख़ुद को मुसलमानों का दोस्त बताते हैं. दूसरी ओर ऐसे लोग, जो हर भारतीय तक नहीं मानते, कभी-कभी इनकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं. भारत में ऐसी एक भी निष्पक्ष पार्टी नहीं है, जो यह कह सके कि हर इंसान अपने अधिकार का पूर्ण इस्तेमाल करे, सबके साथ न्याय हो. ऐसा हो सकता है, लेकिन तभी, जबकि हम अपनी धार्मिक शिनाख़्त को लेकर ज़ोर न दें या कहें कि इस ओर से अपनी आंखें फेर लें. इसमें कोई शक नहीं है कि 1947 के बाद से इन 64 सालों में भी हम एक ऐसी व्यवस्था स्थापित कर पाने में असफल रहे, जो समानता के आधार पर हो, जहां सबके लिए सम्मान हो, बिना उसकी जाति और धर्म को देखते हुए. असल में मंडल के ज़माने के बाद से हर राजनीतिक दल की एक ख़ास पहचान बन गई. अगर आप राज्य से कोई सहायता चाहते हैं तो आपको अपना लेबल (वर्ग) दिखाना पड़ेगा कि आप बीपीएल, एससी, एसटी अथवा ओबीसी हैं. समस्या यह है कि सत्ता में चाहे जो भी हो, धर्मनिरपेक्ष या सांप्रदायिक, सबके सब सामंती मानसिकता के हैं. वे ऐसा मानते हैं कि यह उनका अधिकार या कहें विशेषाधिकार है कि वे विकास के निचले पायदान पर खड़े लोगों को कुछ दें भी, और जब उन्हें यह उपहार मिले तो इसके लिए वे कृतज्ञता भी प्रकट करें. हो सकता है कि ऐसे लोग 35 किलो गेहूं या चावल न चाहते हों, इसके बदले वे बाज़रा या चिकन चाहते हों. लेकिन उन्हें जो अनाज मिलेगा, वह इसलिए मिलेगा कि उनके मालिकों (नेताओं) को ऐसा लगता है कि इन लोगों को यही मिलना चाहिए. कोई भी यह ज़हमत उठाने के लिए तैयार नहीं दिखता कि ग़रीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों से पूछा जाए कि उन्हें क्या चाहिए? अगर ऐसा होता तो यह सचमुच लोकतांत्रिक क़दम माना जाता, लेकिन भारत में लोकतंत्र की इजाज़त सिर्फ़ चुनाव के समय ही दी जाती है. इसी सामंती मानसिकता की एक त्रासदी उड़ीसा के मलकानगिरी में देखने को मिली. माओवादियों के साथ सरकार की बातचीत के मध्य यहां के ज़िला कलेक्टर आर विनिल कृष्णा को मानो गिरवी रख दिया गया था. अगर ग़रीब आदमी को दिल्ली में बैठे वीवीआईपी को मिलने वाली सुरक्षा का सौवां हिस्सा भी मिले तो यह असंभव है कि कोई उसका अपहरण कर सके. सामंती व्यवस्था की वजह से ही आम लोगों को इस तरह का ख़तरा झेलना पड़ता है, क्योंकि सरकार उन सुविधाओं को टुकड़ों में बांटती है, जिस पर पूर्ण अधिकार आम आदमी का होता है. सत्ता में बैठे लोगों के रिश्तेदारों के पास किसी वीआईपी से कम विशेषाधिकार और सुविधाएं नहीं होतीं. ऐसी स्थिति में जब हम से कोई बिना लाल बत्ती की कार के सड़क पर निकलता है और कोई वीवीआईपी गाड़ी की चपेट में आकर मर जाता है, तब कोई हमारा नाम नहीं पूछता. हर कोई यह जानना चाहता है कि वह हिंदू है या मुस्लिम. मानो हम किसी धर्मनिरपेक्ष या सांप्रदायिक पार्टी-संस्था की संपत्ति हैं. अगर इन दोनों स्थितियों में से कुछ नहीं है तो तय मानिए, कोई भी उस दुर्घटना की परवाह नहीं करेगा. जयहिंद.

feedback@chauthiduniya.com

पर्व नहीं, हम बदले हैं

महेंद्र अवधेश

बात ज्यादा पुरानी नहीं है. यही कोई सात-आठ साल पहले मैं कानपुर (उत्तर प्रदेश) से प्रकाशित एक हिंदी दैनिक में कार्यरत था. होली का मौक़ा था, मैं घर पर अपने कमरे में बैठा पुराने अख़बार पलट रहा था. अचानक मैंने किसी को कुछ अटपटा सा बोलते सुना तो कान उसी तरफ़ केंद्रित हो गए, सगरे तीज-त्योहारन मा आग लागी जाय रही...ई होली है? कहां ते लागत है? ई महंगाई तो खाय जाई सबका...

त्योहारों के बदलते स्वरूप के लिए अपने चिर परिचित ठेठ अंदाज़ में महंगाई को कोसने वाला और कोई दूसरा अथवा सिरफिरा नहीं था, बल्कि पड़ोस में रहने वाली मुहल्ला मौसी रामवती थीं, जिनकी नज़र में दैनिक ज़रूरत की वस्तुओं के दामों में होने वाली बढ़ोतरी ही तीज-त्योहारों की रौनक़ हरने की दोषी थी. किसी हद तक उनकी सोच सही भी थी. किसी बात की वजह तलाशने का उनका अपना एक पैमाना था, क्योंकि एक आम अनपढ़, सीधी-सादी बुज़ुर्ग महिला की समझ का दायरा ही कितना बड़ा होता है.

लेकिन, मौसी को यह कतई नहीं भान था कि सिर्फ़ महंगाई बढ़ने से ही त्योहार फीके नहीं पड़े, बल्कि कहीं कुछ और भी घटता जा रहा है हमारे अंदर और हमारे बीच, जो हमें अपनी संस्कृति, तीज-त्योहारों और परंपराओं से लगातार दूर करता जा रहा है. रही महंगाई की बात, तो आज से सात बरस पहले रसोई और जेब की हालत इतनी बदतर नहीं थी. ज़रूरत की चीजें और बाक़ी ज़िम्मेदारियां किसी न किसी तरह पूरी हो जाती थीं, लेकिन अब सोचना पड़ता है. एक नहीं, कई बार. क्या करें, क्या न करें की स्थिति से निकलना अब आसान नहीं होता. वैसे भी त्योहार सिर्फ़ समर्पण मांगते हैं, धन की उन्हें कोई विशेष दरकार नहीं होती. वे तड़क-भड़क के भूखे नहीं हैं और न ही शाहख़र्ची के हिमायती. वे तो बस इतना चाहते हैं कि आप पूरी ईमानदारी के साथ उठकर उनका स्वागत करें.

सिर्फ़ होली ही नहीं, हर त्योहार अपनी चमक, अपनी उमंग खोता जा रहा है. अब तो सिर्फ़ एक धुंध बची है औपचारिकता की, जिसने सारे उल्लास को अपने दामन में छिपा लिया है. ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है, बीती 8 फ़रवरी को वसंत पंचमी थी. स्कूलों और कुछ संस्थाओं में भले ही सरस्वती पूजन के कार्यक्रम हो गए हों, लेकिन घर और परिवार के स्तर पर कहीं कुछ विशेष होता नहीं दिखा. मुझे अपना बचपन अच्छी तरह याद है. वसंत पंचमी के दिन पूरे मुहल्ले के तन पर वसंती कपड़े दिखते थे. इस दिन विशेष के लिए रसोई के झाड़न, परदे और पोछे तक वसंती रंग में रंग दिए जाते थे, लेकिन अब वह बात और त्योहारों के प्रति वह उत्साह कहीं नहीं दिखता. दिल्ली तो ख़ैर मेट्रो सिटी है, यहां जीवन की भागदौड़ की गति भी सामान्य से कहीं ज्यादा है, सो तीज-त्योहारों में कृत्रिमता का पैठना स्वाभाविक है, लेकिन दीगर शहर, यहां तक कि गांव भी अब इस अनापेक्षित परिवर्तन से अछूते नहीं रहे.

एक समय था कि त्योहारों पर घरों की दीवार रूपी विभाजक रेखा दरकिनार कर पूरा मुहल्ला या गांव कुछ इस कद्र एकाकार हो जाता था, मानों कोई बड़ा परिवार किसी ख़ास आयोजन की तैयारी में जुटा हुआ है. लेकिन अब तो त्योहार घर की चाहरदीवारी में ही सिमट गए हैं, बल्कि वहां भी सकुचते जा रहे हैं. मानों वे ख़ुद ही अति से ज्यादा महत्वाकांक्षी हो चुके मानव से दूर हो जाना चाहते हों. पर्व आता है बाद में, बाज़ार हावी हो जाता है पंद्रह-बीस दिन पहले से ही दिल और दिमाग़ पर. त्योहार बनाइए जानदार-गिफ्ट दीजिए शानदार जैसे स्लोगन अपनी कुटिल मुस्कराहट के साथ जन सामान्य को लूटने के लिए मुस्तैद हो जाते हैं. उधर अति आधुनिक बनने और दिखने की आधारहीन लालसा पाले बैठे लोग त्योहार में शान पैदा करने के चक्कर में बाज़ार के हाथों लुट-पिटकर लौट आते हैं. और, जब होश आता है तो मायूसी उनके सामान्य दिनों की सीमित ख़ुशियां भी छीन लेती है, त्योहार गया भाड़ में. होली में घरों में रात-रात भर जागकर बनने वाली गुझिया और पिचक्के कहीं गुम हो गए हैं और दीवाली में मिट्टी के दीपक. उनका स्थान तोताराम के रसगुल्लों एवं चीन से आई झालरों ने ले लिया है. मानों प्रकृति से नाता बिल्कुल ख़त्म. मनसा-वाचा-कर्मणा सब कुछ कृत्रिम.प्रगति की यह कैसी अंधी दौड़ है? बच्चों से पूछो कि होली का त्योहार हम क्यों मनाते हैं? दीवाली और दशहरा मनाने के पीछे क्या वजह है? रक्षाबंधन किस बात का प्रतीक है? तो वे इन सवालों का कोई सटीक जवाब दे पाने में हिचकिचाते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, भटक से जाते हैं. वे यह तो बता देते हैं कि मदर्स डे, फ़ादर्स डे, फ्रैंडशिप डे और न जाने कौन-कौन से डे कब और क्यों मनाए जाते हैं तथा उन मौक़ों पर क्या-क्या किया जाता है. उन्हें यह सब बताने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आती. कौन ज़िम्मेदार है इस स्थिति का? बच्चे तो क़तई नहीं, क्योंकि जब हम और आप उन्हें बताएंगे ही नहीं, तो वे भला कैसे समझेंगे कि कौन-सा त्योहार कब, क्यों और कैसे मनाया जाता है तथा उनके पीछे मक़सद क्या है? जब वे कोई पाठ ही नहीं पढ़ेंगे, तो उनसे कोई सबक़ सीखने की उम्मीद भला कैसे की जा सकती है? जब आप ख़ुद उन्हें जन्म से ही प्रकृति से दूर कर देंगे तो कृत्रिमता ख़ुद-बख़ुद उनके जीवन की एक ज़रूरत बन जाएगी. उन्हें उनकी ज़मीन से, संस्कृति से कौन दूर कर रहा है? सिर्फ़ आप और हम. पैसों की खनक ने वास्तविक ख़ुशियों से हमारा नाता तोड़ दिया है. कहने का मक़सद मात्र इतना है कि आज की भागमभाग ज़िंदगी में पर्वों के रूप में जो पल-दो पल हमें अपनी ख़ामियां समझने, प्रकृति से जुड़ने और भविष्य का रास्ता तय करने के लिए मिलते हैं, उन्हें हम महज़ मनोरंजन अथवा शान बघारने का मौक़ा भर न समझें, वरन् उन पर्वों की महत्ता और उनके संदेशों पर मनन करें. साथ ही नई पीढ़ी को यह समझाएं कि पर्व हमारे लिए ज़रूरी क्यों हैं, उन्हें कैसे मनाना चाहिए और उनसे सीखना क्या चाहिए?

सिर्फ़ महंगाई बढ़ने से ही त्योहार फीके नहीं पड़े, बल्कि कहीं कुछ और भी घटता जा रहा है हमारे अंदर और हमारे बीच, जो हमें अपनी संस्कृति, तीज-त्योहारों और परंपराओं से लगातार दूर करता जा रहा है.

m_awdhesh@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

उपेक्षा ठीक नहीं

आज़ादी के छह दशकों बाद भी स्वतंत्रता सेनानियों की कोई सार-संभाल सरकार द्वारा नहीं की जा रही है. इस जानकारी से बहुत दुःख हुआ. जिन देशभक्तों ने आज़ादी के सपने को साकार करने के लिए अनगिनत कष्ट सहे, परिवार से दूर रहे, उन्हें स्वतंत्रता सेनानी मानने के लिए सरकार को पर्याप्त सबूत चाहिए. क्या उनकी जुबान की कोई क़ीमत नहीं? राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकार को स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सकारात्मक सोच रखते हुए आवश्यक क़दम उठाना चाहिए.

दिनेश कुमार, *राजस्थान*

निशाने पर कछुए

कुछ दिनों पहले मैंने आपके उत्तर प्रदेश परिशिष्ट में प्रकाशित आलेख-तस्करों के निशाने पर कछुए पढ़ा. यदि कछुओं के संरक्षण के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया तो वे इतिहास के पन्नों में सिमट जाएंगे. उत्तर प्रदेश में तस्करों का पसंदीदा शिकार है कछुआ. उसके पंजों और नाख़ूनों से दवाएं बनाई जाती हैं. हाल में राज्य पुलिस ने 927 कछुए बरामद किए, जिनकी क़ीमत अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में ढाई करोड़ रुपये बताई गई. इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह धंधा कैसे फल-फूल रहा है. सरकार को इस पर ध्यान देकर तुरंत आवश्यक क़दम उठाने चाहिए.

अरुण सरोहा, *दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली*

सर्वश्रेष्ठ पत्र

शर्मनाक

मासूम और नाबालिग़ लड़कियों से देह व्यापार कराना वह भी सड़क किनारे! ऐसे लोग आतंकवादियों से भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं. शर्म आनी चाहिए पुलिस प्रशासन को. एक ओर सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बालिकाओं के कल्याण हेतु नित्य नई योजनाएं बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मासूम बच्चियों को देह व्यापार के दलदल में धकेल कर सरकार के सपनों पर ग्रहण लगाया जा रहा है.

***राजेश जायसवाल,** पूर्णिया, बिहार.*

भ्रष्टाचार एक अहम समस्या

आलेख-संसद के समक्ष चुनौतियां पढ़ा. सरकार ने ग़रीबी दूर करने के लिए चाहे जितनी भी योजनाएं बनाई हों, लेकिन वे कभी कारगर साबित नहीं हुईं. सबसे अहम मुद्दा भ्रष्टाचार है. सवाल यह उठता है कि आख़िर सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश क्यों नहीं लगा पाती. सरकार एक तरफ़ पैसा देती है और दूसरी तरफ़ सरकार के ही लोग भ्रष्टाचार करते हैं यानी एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से लिया. भारत में केवल 20 प्रतिशत लोग अमीर हैं और जो ग़रीब हैं, उनकी ग़रीबी ख़त्म करना आसान नहीं है. अमीर और अमीर हो गए और ग़रीब और ज़्यादा ग़रीब होते चले गए. शिक्षा नीति का क्या हाल है, यह सभी को मालूम है.

ख़दीजा सिद्दीक़ी, *ई-मेल से*

उर्दू में चौथी दुनिया

चौथी दुनिया लंबे अरसे से पढ़ रहा हूं. महमूद मदनी साहब का इंटरव्यू पढ़ा, अच्छा लगा. पहली बार पता लगा कि चौथी दुनिया उर्दू भाषा में भी प्रकाशित होता है. गौ हत्या पर लेख सामायिक है. भारत में छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां न तो गौ हत्या होती है और न किसी बड़े जानवर की. केवल बकरे और मुर्गी के मांस का सेवन किया जाता है.

डॉ. एस डी ख़ान, *जयपुर, राजस्थान*

जन्नत से तुलना अनुचित

पिछले कुछ महीनों से मैं चौथी दुनिया का नियमित पाठक बन चुका हूं. अभी हाल में मैंने संगीतकार इदरीस निज़ामी का इंटरव्यू पढ़ा. ख़ुशी हुई कि हमारे देश में ऐसे भी संगीतकार-कलाकार मौजूद हैं, जो देश के सामने विदेशी पैसे को अहमियत नहीं देते. निज़ामी साहब ने कहा कि भारत दुनिया की जन्नत है, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने आगे कहा कि हम इसे जन्नत से बेहतर समझते हैं, यह मुझे कुछ ग़लत लगा. जन्नत तो सिर्फ़ जन्नत होती है, उसकी तुलना दुनिया की किसी भी चीज़ से करना या उसे जन्नत से बेहतर बताना ग़लत और इस्लाम के ख़िलाफ़ है.

डॉ. शहज़ाद त्यागी, *मुज़फ़्फ़रनगर, उत्तर प्रदेश*

सूचना

राजकमल प्रकाशन
नयी दिल्ली पटना इलाहाबाद

अब चौथी दुनिया में सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को राजकमल प्रकाशन की तरफ़ से 700 रुपये की किताबें पुरस्कार के रूप में दी जाएंगी. पाठक पत्र में अपना पूरा नाम, पता एवं फ़ोन नंबर अवश्य लिखें.

आप अपने स्वतंत्र विचार तथा प्रतिक्रियाएं हमें इस पते पर भेजें. संपादक, चौथी दुनिया, एफ़-2, सेक्टर-11 नोएडा, (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

सरकार को सोच-समझ कर फ़ैसले करने चाहिए

सीवीसी यानी चीफ़ विजिलेंस कमिश्नर पी जे थॉमस के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय बता दी और यह उसकी राय नहीं, फ़ैसला है कि उनकी नियुक्ति अवैध है. सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से जिस समिति ने इन्हें चुना, जिसमें प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और नेता विपक्ष सुषमा स्वराज थीं, उसकी कार्यशैली पर ज़रूर सवाल उठता है. क्यों प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सुषमा स्वराज की राय पर ध्यान नहीं दिया. राजनीति में इस तरह का व्यवहार या कार्यशैली बहुत समझदारी भरी नहीं है, क्योंकि जहां सिर्फ़ तीन लोग हों और तीनों में से एक अगर बहुत स्ट्रांग प्रतिक्रिया दे रहा हो या बहुत सख्त विरोध दर्ज करा रहा हो तो उसके विरोध को वैसे ही देखना चाहिए, जैसे ये अपने विरोध को देखते हैं. अगर इस नज़रिए से काम करते तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार को मूर्खता भरी डांट न खानी पड़ती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में एक लाइन कही है, जिसका नतीजा यह निकलता है कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का किया हुआ फ़ैसला बहुत समझदारी भरा नहीं है. पी जे थॉमस ब्यूरोक्रेटिक सर्किल में एक अच्छे अफ़सर के नाते जाने जाते हैं. उनके ख़िलाफ़ केरल में एक केस था. दिल्ली में जब वह राजा के साथ सचिव थे, उस समय बहुत सारे फ़ैसले हुए. थॉमस का कहना था कि फ़ैसले उनके समय नहीं हुए. लेकिन फ़ैसले उनके समय हुए या नहीं, यह बहस का सवाल नहीं. सवाल यह है कि उनसे पहले फ़ैसले हुए हों या उनके सामने, थॉमस को इन सारे फ़ैसलों के गुण-दोष के बारे में पता था, इसलिए वह इसमें इन्वाल्व तो माने ही जाएंगे. उन्होंने इसमें विरोध दर्ज नहीं कराया, कोई नोट नहीं लिखा, वह इस मसले को अपने मंत्री या प्रधानमंत्री या कैबिनेट सेक्रेटरी के पास नहीं ले गए, पर थॉमस ने एक अड़ियल ब्यूरोक्रेट की तरह व्यवहार किया और उन्होंने कहा कि जब मैं ग़लत नहीं हूं तो क्यों इस्तीफ़ा दूं.

दूसरा ग़लत काम उन्होंने यह कहकर किया कि जब संसद के 250 से ज़्यादा सदस्यों के ख़िलाफ़ आरोप हैं और वे इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं या उनके ख़िलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं हो रही तो मैं क्यों इस्तीफ़ा दूं. पर थॉमस यह भूल गए कि उसी आरोप में उनके मंत्री रहे ए राजा को न केवल त्यागपत्र देना पड़ा, बल्कि वह जेल भी गए. आरोप सिद्ध नहीं हुआ, अपराधी नहीं हैं राजा आज भी, जब तक कोर्ट उन्हें अपराधी साबित नहीं करता, लेकिन इस्तीफ़ा तो उन्हें देना ही पड़ा आरोप को लेकर ही. वैसे ही आरोप को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को इस्तीफ़ा देना पड़ा, वह भी अपराधी नहीं हैं, क्योंकि अभी तक उनके ख़िलाफ़ अपराध सिद्ध नहीं हुआ है. इसलिए यह तर्क लोकतंत्र में नहीं चलता है. इसे थॉमस की होशियारी कहें या बेवकूफ़ी कि उन्होंने केंद्र सरकार को मुसीबत में डाला. जब आरोप-प्रत्यारोप शुरू हुए और सुप्रीम कोर्ट ने कई टिप्पणियां कीं तो थॉमस को अपने अनुभव से यह जान लेना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देने वाला है. अगर थॉमस इस्तीफ़ा दे देते या पहली बार सीवीसी बनने के बाद जब उन पर आरोप लगा था, इस्तीफ़ा दे देते तो शायद उनकी इतनी किरकिरी नहीं होती और यह दरअसल थॉमस की कम हुई है, यह किरकिरी देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, गृहमंत्री श्री चिदंबरम और श्रीमती सोनिया गांधी की हुई है. सोनिया गांधी जी और चिदंबरम को थोड़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए थी, क्योंकि संयोग की बात है कि दोनों एक ही धर्म से आते हैं. थॉमस भी उसी धर्म के हैं. हमारा हिंदुस्तान जातियों एवं धर्मों में बंटा हुआ है और जब कोई ऐसा मामला होता है, जिसमें धर्म और जाति एक हो तो बहुत सारे लोग शक करने लगते हैं.

जैसा थॉमस ने किया, वैसा ही एक अफ़सर और कर चुका है. उस अफ़सर का नाम लाली है. लाली प्रसार भारती के सीईओ थे. यह संवैधानिक पद है और लाली को लगता था कि कोई भी उनके ख़िलाफ़ कुछ कर नहीं पाएगा. जब लाली के ख़िलाफ़ आरोप नहीं लगे थे, यह मैं साल भर पहले की बात कर रहा हूं तो लाली प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम और सरदार-सिक्ख होने का सीधा फ़ायदा उठाते थे. लाली ने बीसियों ऐसे लोगों से कहा कि प्रधानमंत्री ने मुझे बुलाया, प्रधानमंत्री ने मुझसे यह बात की. वह प्रधानमंत्री से अपनी नज़दीकी इस हद तक साबित करते थे कि उनके मंत्री, प्रसार भारती के सदस्य और उनसे मिलने जाने वाले ऐसे लोग जो ईमानदार होते थे, दहल जाते थे, दहशत में आ जाते थे. लाली ने एक माहौल बना दिया था, जिसमें उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से मज़हब का सहारा लिया. मैं सरदार, प्रधानमंत्री भी सरदार यानी मैं सिक्ख, वह भी सिक्ख, हम दोनों एक, हम देर रात मिलते हैं, रणनीति बनाते हैं. इसका नतीजा यह होता था कि बाक़ी लोग हमेशा लाली से सहमे रहते थे. मनमोहन सिंह जी को इस बात की बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने लाली के ख़िलाफ़ न केवल राष्ट्रपति से बर्ख़ास्तगी का ऑर्डर साइन कराया, बल्कि लाली के ख़िलाफ़ सीबीआई जांच और मुक़दमा चलाने की इजाज़त भी दी. मैं पुन: कहता हूं कि मनमोहन सिंह को बधाई देनी चाहिए. हिंदुस्तान और ख़ासकर, जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें उस मानसिकता को याद करके, जहां लोग धर्म और जाति को किसी भी चीज़ के साथ बड़ी आसानी से जोड़ देते हैं. जहां पर स्वधर्मी या स्वजातीय हों, राजनेताओं को बहुत सावधानी से काम लेना चाहिए और अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए, ताकि कहीं ऐसा न हो कि वे किसी मामले में शामिल हों, न हों और लोग उसमें उनका नाम जोड़ दें. लोकतंत्र में जो सामने दिखाई देता है, उसका बहुत असर पड़ता है. यही थॉमस के मामले में हुआ. यहां चिदंबरम, थॉमस और सोनिया गांधी तीनों एक धर्म को मानने वाले, दूसरी तरफ़ लाली और सरदार मनमोहन सिंह एक धर्म को मानने वाले.

अपने धर्म या जाति का कोई आदमी ग़लत ही होगा, मैं यह बात नहीं कहता. सिर्फ़ इतना कहता हूं कि वह आदमी सही हो या ग़लत, और अगर सही हो तब तो और ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए कि उन फ़ैसलों से अपने को अलग कर लेना चाहिए. मैं अभी हाल में उड़ीसा में घटी एक दूसरी घटना का ज़िक्र करना चाहूंगा. उड़ीसा में विनील कृष्णा, जो आईएएस अफ़सर और ज़िलाधिकारी थे, उनका नक्सलियों ने अपहरण कर लिया. सरकार के सामने परेशानी पैदा हो गई कि वह क्या करे. राजनीतिक लोगों ने दबाव बनाया कि सब लोग मिलकर कोई रास्ता निकालें, लेकिन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक बुद्धिमानीपूर्ण फ़ैसला लिया. उन्हें लगा कि अगर हम कांग्रेस या भाजपा के लोगों के साथ मिलकर कोई फ़ैसला लेते हैं और कहीं विनील कृष्णा को नक्सलवादियों ने मार दिया तो सारे देश के आईएएस अफ़सर एक हो जाएंगे और केंद्रीय गृहमंत्री चिदंबरम उनकी सरकार को बर्ख़ास्त कर देंगे. उन्होंने कहा कि आईएएस बिरादरी के लोग मिलकर इसका फ़ैसला लें. मतलब उन्होंने अपने मुख्य सचिव को इसमें शामिल कर लिया. उड़ीसा की पूरी ब्यूरोक्रेसी इसमें शामिल हो गई और उन लोगों ने एक फ़ैसला लिया. नवीन पटनायक ने उससे स्वयं को बिल्कुल अलग रखा. फ़ैसले के तहत नक्सलियों की मांगें मानी गईं और कृष्णा छोड़ दिए गए. यह अलग बात है कि उड़ीसा सरकार को अब यह डर है कि कृष्णा की विचारधारा और नक्सलवादियों की विचारधारा दोनों में कहीं कोई तार जुड़ता है. दूसरे शब्दों में, कृष्णा नक्सलवादियों से सहानुभूति रखते थे और ख़ासकर कृष्णा के ससुर नक्सलवादियों के संपर्क में थे. यह ग़लत नहीं है, क्योंकि नक्सलवादी किसी दूसरे देश से नहीं आए हैं. वे हमारे ही देश के, हमारी ही व्यवस्था के सताए हुए हैं. भूख, बेरोज़गारी, बीमारी एवं ग़रीबी के मारे हुए हैं. उनमें शिक्षा नहीं है, वहां चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं, वहां सड़कें नहीं हैं. ऐसी जगहों पर रहने वाले लोग जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में हैं, वे धीरे-धीरे हथियार उठा रहे हैं व्यवस्था के ख़िलाफ़, उस तंत्र के ख़िलाफ़ जो उन्हें कुछ नहीं देता. उनसे सहानुभूति रखना ग़लत बात नहीं है. हम सब सहानुभूति रखते हैं. देश के बुद्धिजीवियों का बहुत बड़ा तबक़ा उनसे सहानुभूति रखता है. ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा तबक़ा है, जो उनसे सहानुभूति रखता है. सहानुभूति रखना हालांकि काफ़ी नहीं है, लेकिन सहानुभूति न रखना भी एक अपराध है. मुख्यमंत्री ने जहां यह एक अच्छा क़दम उठाया कि उन्होंने फ़ैसला ब्यूरोक्रेसी पर छोड़ दिया, वहीं तत्काल मुख्यमंत्री को दूसरा क़दम उठाना चाहिए. उन्हें उड़ीसा के विकास मॉडल को दोबारा नए सिरे से तय करना चाहिए, क्योंकि अगर इन समस्याओं को बुनियादी तौर पर नहीं पहचाना गया तो यह आग और भड़केगी.

आज एक डीएम पकड़ा गया, सरकार को मांगें माननी पड़ीं. कल डीआईजी पकड़ा जाएगा, डायरेक्टर जनरल पकड़ा जाएगा, मंत्री पकड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री को भी अग़वा किया जा सकता है. उड़ीसा के बहाने मैं देश के सारे मुख्यमंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों से कहता हूं कि आप अगर अपने को नहीं बदलेंगे तो आप या आपके बच्चे उन लोगों के चंगुल में फंस जाएंगे, जो भूख, बीमारी, ग़रीबी और बेरोज़गारी से लड़ रहे हैं. कल कोई केंद्रीय मंत्री भी अग़वा किया जा सकता है. यह एक ख़तरे की घंटी है और इससे लड़ने के लिए पूरी राजनीतिक व्यवस्था, वे लोग जो राजनीतिक व्यवस्था को चला रहे हैं, को चाहिए कि तत्काल अपने दिमाग़ की खिड़की खोलें. आपसी मतभेदों को एक तरफ़ करके देश में खड़ी विश्वास की समस्या, विकास की समस्या, कुछ न मिलने की समस्या और अकेले होने की समस्या से लड़ने के लिए एक नई योजना बनाएं, जिससे अपने ही देश के लोग, जो भूख, बीमारी, ग़रीबी और अपमान से परेशान हैं और 60-70 प्रतिशत के आसपास हैं, वे कम से कम ख़ुद को इस देश का नागरिक मानने की मानसिक स्थिति में आ सकें. यह बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उड़ीसा जैसी घटनाएं दोहराई जाएंगी, बढ़ेंगी. दूसरा भारत सरकार को यह सोचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ कहता है या इशारा करता है तो उसे वह यह मानकर न टाल दे कि यह मैनेज किया जा सकता है. अब सुप्रीम कोर्ट आज़ाद सुप्रीम कोर्ट है. पहले यह आज़ादी दिखाई नहीं देती थी. सुप्रीम कोर्ट उसे बाहर नहीं दिखाता था, अब वह दिखाने लगा है कि हम आज़ाद हैं नहीं, आज़ाद दिखना भी चाहते हैं. सरकार को अपने सारे फ़ैसले बहुत सोच-समझ कर करने चाहिए. अगर वह नहीं करती है तो वह पूरी सरकारी मशीनरी के ऊपर लोगों के विश्वास के सामने सवालिया निशान खड़ा करती है.

मनमोहन सिंह जी को इस बात की बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने लाली के ख़िलाफ़ न केवल राष्ट्रपति से बर्ख़ास्तगी का ऑर्डर साइन कराया, बल्कि लाली के ख़िलाफ़ सीबीआई जांच और मुक़दमा चलाने की इजाज़त भी दी. हिंदुस्तान और ख़ासकर, जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जहां लोग धर्म और जाति को किसी भी चीज़ के साथ बड़ी आसानी से जोड़ देते हैं, राजनेताओं को बहुत सावधानी से काम लेना चाहिए और अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए,

संपादक
editor@chauthiduniya.com

आख़िर कैसे बचेगा पाकिस्तान

नज़म सेठी

हर ज़ुबान पर क्रांति और इंकलाब जैसे शब्द हैं. ग़रीब इससे कुछ हासिल होने की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि अमीर डरे हुए हैं. पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर और अब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री शहबाज भट्टी की हत्या ने अवाम के बीच सिहरन पैदा कर दी है. मेरे लाइव टीवी शो में एक कॉलर (दर्शक) ने पूछा कि एटम बम बनाने का फ़ायदा ही क्या, जब इसका इस्तेमाल किसी के ख़िलाफ़ नहीं किया जा सकता. इस सवाल का जवाब एक क्रोधित दर्शक ने ही यह कहकर दे दिया कि इसे पाकिस्तान की ग़रीब जनता पर गिरा दो, ताकि एक ही झटके में पाकिस्तान से ग़रीबी ख़त्म हो जाए. एमक्यूएम के नेता अल्ताफ हुसैन ने पिछले महीने ही उपदेश देने की मुद्रा में देशभक्त जनरलों को ख़ूनी क्रांति शुरू करने की सलाह दी थी. अब नवाज शरीफ जनभावना को भुनाने में लगे हुए हैं. अपनी हार बचाने के लिए पीर पगारो, जो पीएमएल के दूसरे खेमे के नेता और जीएचक्यू के स्वयंभू प्रवक्ता हैं, ने ऐलान किया कि सेना को अगले 40 साल तक के लिए पाकिस्तान की कमान अपने हाथ में ले लेनी चाहिए, ताकि यहां की सारी व्यवस्था ठीक की जा सके. तो क्या पश्चिमी एशिया की तरह पाकिस्तान में भी क्रांति आने वाली है? नहीं, ऐसा नहीं है.

पश्चिम एशिया में बिखरती राजशाही के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व जनतांत्रिक ताक़तों के पास है, ठीक उसी तरीके से जैसे 18वीं शताब्दी के यूरोप में निरंकुश शासन के विरुद्ध हुआ था या 1980 में पूर्वी यूरोप में मार्क्सवादियों के ख़िलाफ़. विद्रोह की हर लहर धर्मनिरपेक्ष थी, लेकिन पाकिस्तान में आज़ादी के नाम पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है. 1968 में पहला छात्र विद्रोह जनरल अय्यूब खान की सरकार को गिराने में कामयाब रहा. 1977 में बहुदलीय विद्रोह हुआ, जिसने जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार गिरा दी. तीसरा विद्रोह तीस साल बाद हुआ, जिसे मीडिया ने पूरा समर्थन दिया और जिसने जनरल परवेज मुशर्रफ को सत्ता से उखाड़ फेंका. अधिकतर समय सेना के अधीन रहने के बाद भी पाकिस्तान में बहुदलीय व्यवस्था है, जहां चुनाव होते रहते हैं और केंद्र एवं राज्य सरकारें भी अस्तित्व में हैं. इसलिए पश्चिम एशिया जैसा राजनीतिक संकट पाकिस्तान में उभरना मुमकिन नहीं है. तो क्या इसका अर्थ यह है कि पाकिस्तान में बदलाव की लहर नहीं आ सकती? नहीं, ऐसा भी नहीं है. पश्चिम एशिया की तरह यहां कुछ समानताएं भी हैं. पाकिस्तान की 60 फ़ीसदी जनसंख्या 30 साल से कम की है. ज़्यादातर लोग बेरोज़गार हैं और वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था से नाख़ुश भी. पश्चिम एशिया की तरह यहां भी अमेरिका के ख़िलाफ़ असंतोष है.

नतीजतन, पाकिस्तान में भी एक क्रांति की संभावना है, लेकिन दु:ख की बात यह है कि जनभावना प्रजातंत्र के ख़िलाफ़ है, धर्मनिरपेक्षता के विरोध में है और एकांतवादी है. ऐसा इसलिए है, क्योंकि पाकिस्तान में प्रजातंत्र नाकाम हो गया है. तो इसका अर्थ यह है कि पाकिस्तान में ईरान की तरह इस्लामिक क्रांति आएगी? नहीं, ऐसा भी नहीं है. ईरान में इस्लामिक क्रांति इसलिए आई, क्योंकि वहां नस्लीय हिंसा नहीं थी, वहां के लोगों में धार्मिक समानता थी और वहां के सभी उलेमा अयातुल्लाह खुमैनी के साथ थे. इसीलिए ईरान दूसरे मुस्लिम देशों से अलग था, लेकिन पाकिस्तान में जनता धर्म, क्षेत्र एवं जनजातीय रूप में विभाजित है और आपस में लड़ती रहती है. यही वजह थी कि 1971 में पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया. 2002 में यहां की प्रमुख धार्मिक पार्टियों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए मुत्ताहिदा मजलिस-ए-अमल का गठन किया, लेकिन वह अभी तक राजनीतिक व्यवस्था में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सकी है.

ऐसी स्थिति में पाकिस्तान में किस तरह के बदलाव संभव हैं? एक बदलाव अगले साल चुनाव के माध्यम से सत्ता परिवर्तन का हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ़ एक ग़ैर ज़िम्मेदार सरकार को हटाकर दूसरी ग़ैर ज़िम्मेदार सरकार लाने जैसा ही होगा और यह स्थिति फिर से निराशा ही पैदा करेगी. दूसरा उपाय है कि एक ऐसा विद्रोह हो, जिसमें सेना, न्यायपालिका एवं मीडिया एक साथ मिलकर आगे आएं और बेईमान राजनेताओं एवं राजनीतिक दलों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें. इसके बाद जनता-सेना का मिला-जुला शासन स्थापित हो और टेक्नोक्रेट की मदद से बिगड़ी हुई स्थिति को ठीक किया जाए, लेकिन इस सब में पीएमएलएन और पीपीपी के नेताओं को बिल्कुल भी शामिल न किया जाए. समय बीतने के साथ मीडिया फिर अपना पाला बदल लेगा और तब उस व्यवस्था के बदले एक बार फिर एक ज़िम्मेदार लोकतंत्र की मांग करने लगेगा. अराजकता, सलमान तासीर एवं शहबाज भट्टी जैसे लोगों की हत्या, युद्ध, आर्थिक नुक़सान, जन संघर्ष और बिखराव जैसी बातें एक असफल राष्ट्र की निशानी होती हैं. आज यह सब कुछ पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है. उचित विकल्प यही है कि हमारे नेताओं को क़ानून और राजनीति से धार्मिक जुनून को अलग करके रखना होगा. हमें हर हाल में लोकतंत्र को बचाए रखना होगा और उसे कारगर बनाना होगा, ताकि एक राष्ट्र के तौर पर पाकिस्तान का अस्तित्व बचा रहे और वह समृद्ध होता रहे.

पाकिस्तान में किस तरह के बदलाव संभव हैं? एक बदलाव अगले साल चुनाव के माध्यम से सत्ता परिवर्तन का हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ़ एक ग़ैर ज़िम्मेदार सरकार को हटाकर दूसरी ग़ैर ज़िम्मेदार सरकार लाने जैसा ही होगा और यह स्थिति फिर से निराशा ही पैदा करेगी. दूसरा उपाय है कि एक ऐसा विद्रोह हो, जिसमें सेना, न्यायपालिका एवं मीडिया एक साथ मिलकर आगे आएं और बेईमान राजनेताओं एवं राजनीतिक दलों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें.

(लेखक द फ्राइडे टाइम्स के संपादक हैं)

feedback@chauthiduniya.com

सवाल यह है कि सरकार और अदालतों के स्पष्ट आदेशों के बाद भी आख़िरकार रिहायशी क्षेत्रों में व्यवसायिक गतिविधियां चलाने की इजाज़त कौन देता है?

रिहायशी इलाक़े में व्यवसायिक गतिविधियों से परेशान हैं?

यह समस्या लगभग हर छोटे–बड़े शहर की है. आवासीय–रिहायशी इलाक़ों में लालची और स्वार्थी किस्म के लोग ऐसे–ऐसे व्यवसाय शुरू कर देते हैं, जिनकी वजह से उस इलाक़े में रहने वाले लोगों के लिए कई सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है. मसलन, दिल्ली के संजय नगर इलाक़े में कुछ ऐसे ही अवैध गोदाम, पार्किंग, मोटर वर्कशॉप चल रहे हैं, जिनकी वजह से वहां प्रदूषण तो बढ़ ही रहा है, साथ ही कॉलोनी में रहने वाले लोग भी परेशान रहते हैं. सवाल यह है कि सरकार और अदालतों के स्पष्ट आदेशों के बाद भी आख़िकार रिहायशी क्षेत्रों में व्यवसायिक गतिविधियां चलाने की इजाज़त कौन देता है? इस सवाल का एक आम जवाब लोग यह देते हैं कि यह व्यवसाय रिश्वतखोरी की वजह से जिंदा है. बहुत हद तक यह बात सही भी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस तरह के अवैध व्यवसाय के बारे में सरकारी अधिकारियों या संबंधित विभागों को जानकारी नहीं होती है. इस तरह के व्यवसायी पैसे की बदौलत अपने ख़िलाफ़ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होने देते. यह तो बात समस्या की थी, अब समाधान की बात करते हैं कि कैसे इस समस्या का हल एक आम आदमी ख़ुद निकाल सकता है. इस अंक में हम एक ऐसा ही आवेदन प्रकाशित कर रहे हैं, जिसमें हमने इस समस्या से निजात पाने संबंधी उपाय बताए हैं. इस आवेदन का इस्तेमाल करके आप यह सूचना पा सकते हैं कि आपके इलाक़े में ऐसे कितने भवन हैं, जिनका उपयोग क़ानून का उल्लंघन करते हुए व्यवसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है. आप ऐसे भवनों की सूची मांग सकते हैं. इनके ख़िलाफ़ संबंधित विभाग ने क्या कार्रवाई की, इसका पूर्ण विवरण मांगा जा सकता है. आप इस आवेदन के इस्तेमाल से उन नियमों, कानूनों और सरकारी आदेशों की जानकारी भी ले सकते हैं, जिनका उल्लंघन किया जा रहा है. आवासीय संपत्ति का व्यवसायिक उपयोग करने के मामले में निर्धारित सज़ा अथवा नियम के मुताबिक़ की जाने वाली कार्रवाई का विवरण भी मांगा जा सकता है. ऐसे मामले में संबंधित विभाग ने क्या कार्रवाई की, इसकी जानकारी भी जुटाई जा सकती है. अगर आप चाहें तो ऐसी गतिविधियों के ख़िलाफ़ संबंधित विभाग में शिक़यत दर्ज कराकर उसके बाद एक आरटीआई आवेदन दे सकते हैं, जिसमें आप यह पूछ सकते हैं कि आपकी शिक़ायत पर संबंधित विभाग ने अब तक क्या कार्रवाई की है. आप अपने इलाक़े के कई लोगों की ओर से भी आवेदन और शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ताकि संबंधित विभाग पर कार्रवाई करने के लिए दबाव बने.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन –201301
ई–मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप

(व्यवसायीकरण)

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

महोदय,

कृपया.....क्षेत्र में व्यवसायीकरण से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:

1. उपरोक्त क्षेत्र में उन सभी भवनों की सूची प्रदान करें, जिनका उपयोग क़ानून का उल्लंघन करते हुए व्यवसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है.

2. ऐसे प्रत्येक मामले में किस तरह के क़ानूनों का और किस प्रकार उल्लंघन हो रहा है? इसका विवरण दें. आपके विभाग को इन उल्लंघनों के बारे में सबसे पहले कब जानकारी मिली?

3. इन उल्लंघनों की जानकारी मिलने के बाद इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की गई है? इसका पूरा विवरण दें.

4. कृपया उन नियमों, क़ानूनों और सरकारी आदेशों की जानकारी दें, जिनका आवासीय संपत्ति का व्यवसायिक उपयोग करने के कारण उल्लंघन हुआ है.

5. आवासीय संपत्ति का व्यवसायिक उपयोग करने के मामले में निर्धारित सजा अथवा नियम के मुताबिक़ की जाने वाली कार्रवाई का विवरण दें.

6. ऐसे प्रत्येक मामले में आपके विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? प्रत्येक घटना का अलग–अलग पूरा विवरण दें. यदि किसी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो क्यों?

7. मैं ऐसे प्रत्येक मामले में की गई कार्रवाई से संबंधित सभी दस्तावेजों एवं फाइलों का निरीक्षण करना चाहता हूं. कृपया मुझे दिन, समय एवं स्थान के बारे में सूचित करें, जब मैं निरीक्षण के लिए आ सकूं.

8. उन अधिकारियों के नाम, पद और संपर्क का विवरण बताएं, जो इस व्यवसायीकरण के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए ज़िम्मेदार हैं.

9. क्या ये अधिकारी क़ानून के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई न करने के कारण भ्रष्टाचार निवारण क़ानून की धारा 13 (घ) और भारतीय दंड संहिता की धारा 217 के उल्लंघन के दोषी हैं?

10. इन अधिकारियों के ख़िलाफ़ अब आगे कब और क्या कार्रवाई की जाएगी?

11. उपरोक्त व्यवसायीकरण कब तक पूर्ण रूप से रोक अथवा हटा दिए जाएंगे?

12. उपरोक्त क्षेत्र से दिनांक.....से.....के दौरान आपके विभाग को व्यवसायीकरण से संबंधित प्राप्त शिक़ायतों और उन पर की गई कार्रवाई का विवरण दें.

मैं आवेदन शुल्क के रूप में.....रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.
या
मैं बीपीएल कार्डधारक हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नंबर.....है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित न हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम और पता अवश्य बताएं.

भवदीय

नाम.....
पता.....
फोन नंबर.....

संलग्नक.....
(यदि कुछ हो तो)

राशिफल

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
इस सप्ताह स्वाभाविक चंचलता के कारण कुछ अनावश्यक विवाद पैदा हो सकते हैं. रुके हुए काम पूरे करने में किसी की मदद मिलेगी. कारोबार में प्रगति होने से आगे चलकर धन लाभ की आशा रहेगी. आपके कामकाज की सराहना भी वरिष्ठ अधिकारी कर सकते हैं.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
इस सप्ताह कामकाज की स्थिति लाभदायक सिद्ध होगी. व्यवसायिक लाभ में वृद्धि होगी. यह सप्ताह आपके लिए किसी अच्छे परिणाम के संकेत ला रहा है. काफी समय से अटका हुआ धन मिलने या कोई ज़रूरी कार्य बन जाने से आपकी प्रसन्नता बढ़ जाएगी.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
इस सप्ताह लाभ मार्ग अवरुद्ध होगा और घरेलू क्लेश भी परेशान करेंगे. यदि आप अपना कार्यक्रम बदल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. कारोबार में किसी विश्वासपात्र व्यक्ति से धोखा मिल सकता है.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
इस सप्ताह सुख और आराम के साधन–अवसर प्राप्त होंगे. अचानक किसी लाभदायक कार्य के सिद्ध हो जाने से आपका मन प्रसन्न हो सकता है. यदि कहीं यात्रा का कार्यक्रम बना रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी धन जुटाने में आपको अधिक कठिनाई नहीं होगी.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
इस सप्ताह मानसिक विकार, शारीरिक कष्ट और व्याधिक्य के चलते परेशानी हो सकती है. व्यापार या करियर के मामले में आपको कुछ नई रणनीति अपनानी होगी. काफी समय से आप कुछ ऐसी योजनाओं पर विचार कर रहे हैं, जिन्हें अमल में लाना अब ज़रूरी हो गया है.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
परिवार में सुख–शांति बनाए रखें. सौभाग्य आपके द्वार पर खड़ा है. आपके व्यवहार और विचार से प्रभावित होकर कोई प्रभावशाली व्यक्ति आपके लिए मददगार साबित होगा. यदि आप किसी पेचीदा और कठिन काम को करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें सफलता निश्चित है.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
इस सप्ताह स्थायी उद्यम लाभ मार्ग प्रशस्त करेंगे. वरिष्ठजनों की सेवा के प्रति रुचि बढ़ेगी. आपके लिए समय अनुकूल रहेगा. जहां तक हो सके, आप वाद–विवाद या सामाजिक आंदोलन से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
इस सप्ताह सभी काम सरलता से बनते नज़र आएंगे. नौकरी में उन्नति की संभावना है. सोच–विचार कर जो भी काम करेंगे, उसका परिणाम अच्छा रहेगा. किसी शुभ कार्य की योजना बनेगी. सभा, समारोह या सामाजिक कार्यक्षेत्र में आपकी पहुंच होगी.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
सप्ताह की शुरुआत में शत्रु के षड्यंत्रों से तनाव और परेशानी पैदा हो सकती है, परंतु लाभ मार्ग में रुकावट नहीं आएगी. चंद्रमा का अच्छा गोचर चलने से आपको अपना महत्वपूर्ण कार्य करने में सफलता मिलेगी. काफी समय से अटके हुए काम बन जाने से प्रसन्नता होगी.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
इस सप्ताह अचानक कार्यों में गतिरोध आने से व्याकुलता पैदा होगी. आवास या घर की चिंता अधिक रहेगी. घर का कामकाज सुचारू रूप से चलेगा. किसी व्यक्ति विशेष के सहयोग और आश्वासन के बावजूद काम न बनने से खिन्नता रहेगी.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
निकट–दूर की यात्राएं होंगी और मित्रों का समागम व्यय बढ़ाएगा. सप्ताह के आरंभ में ही कुछ अच्छा समय आपके हाथ में रहेगा. बेहतर होगा कि सभी ज़रूरी काम सप्ताह के मध्य तक निपटा लें. उसके बाद जहां आपके प्रयासों में अड़चन आएगी, वहीं शत्रु और विरोधी भी सामने खड़े नज़र आएंगे.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
इस सप्ताह यात्रा का अवसर मिलेगा और दांपत्य जीवन में अनुकूलता बढ़ने की आशा है. यह सप्ताह दौड़–भाग और परिश्रम के अच्छे नतीजे देने वाला साबित होगा. आप किसी के बहकावे या मिथ्या भाषण में न उलझें.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

क्रिकेट की शादी फिक्सिंग

इस बात से सभी वाक़िफ़ हैं कि भारत में क्रिकेट के प्रति लोगों की दीवानगी किस हद तक है, लेकिन इस बार तो हद हो गई. अगर कोई हाथ में बल्ला और गेंद लेकर जीने–मरने की कसमें खाए तो इसे आप क्या कहेंगे, क्रिकेट के प्रति लगाव या समर्पण? राजस्थान के एक शहर में ऐसा ही हुआ है. हाथ में बल्ला और गेंद लेकर किसी खिलाड़ी ने नहीं, बल्कि क्रिकेट के दीवानों ने अपनी शादी की और साथ जीने–मरने की कसमें खाईं. विश्वकप के दौरान इस खेल के प्रति अपने प्यार और लगाव का इज़हार करने के लिए 15 जोड़ियों ने बाकायदा गेंद और बल्ला लेकर सात फेरे लिए और साथ जीने–मरने की कसमें खाईं. तैलिक साहू कम्युनिटी सेंटर में इन जोड़ियों ने फेरे लेने के बाद अपने चहेते खिलाड़ियों को विश्वकप के लिए शुभकामनाएं दीं. सामूहिक विवाह स्थल पर खिलाड़ियों के पोस्टर और उन्हें शुभकामना संदेश देने के लिए बैनर भी लगाए गए थे. एक दूल्हे के रिश्तेदार ने बताया कि हम क्रिकेट के दीवाने हैं. यही कारण है कि हमने विश्वकप थीम के साथ इस विवाह समारोह को आयोजित करने का फ़ैसला किया. विवाह स्थल को खिलाड़ियों के पोस्टरों से पाट दिया गया और साथ ही उन्हें संदेश देने के लिए बैनर भी लगाए गए. हमने सजावटी सामानों की जगह इन्हीं चीजों से विवाह स्थल सजाने का फ़ैसला किया. एक दुल्हन की क़रीबी दोस्त उगांति ने कहा कि हमारे परिजनों ने शुरुआत में इसका विरोध किया था, लेकिन क्रिकेट के प्रति हमारे प्यार की कद्र करते हुए वे अंतत: मान गए. अब अगर इसे इस तरह से कहा जाए कि फिक्स होने वाले क्रिकेट ने इस बार शादियां फिक्स करा दीं तो अन्यथा न लीजिएगा.

कार है या क़ब्रगाह

अभी तक आपने क़ब्रगाह पर मृत लोगों की तस्वीरें लगी देखी होंगी, लेकिन यदि आप सिंगापुर की यात्रा पर जा रहे हैं और वहां आपको तस्वीरों से सजी एक टैक्सी की सवारी का अवसर मिले तो सावधान रहें, क्योंकि वे मृतकों की तस्वीरें हो सकती हैं. यह पढ़कर आपको विक्षिप्त दिमाग़ वाले साइको किलर याद आ गए होंगे, क्योंकि इस तरह के कारनामे इन्हीं लोगों के घरों या कारों में दिखाई देते हैं. यह विचित्र मानसिकता के तहत इस तरह की तस्वीरों के प्रति आकर्षित होते हैं और फिर बाद में कई ग़ैर क़ानूनी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं. एक शख़्स ऐसा भी है, जिसने अपनी कार में मृत व्यक्तियों की तस्वीरें लगाकर उसे क़ब्रगाह में तब्दील कर रखा है. यह कार दरअसल एक टैक्सी है. सिंगापुर की एक महिला लोवेल टैन ने एक वेबसाइट को बताया कि उसने एक ऐसी टैक्सी की सवारी की, जो अंदर से मृतकों के विवरण वाली तस्वीरों एवं खिलौनों से सजी हुई थी. टैन ने चोआ चूआकांग इलाक़े में इस टैक्सी में सवारी की. इस इलाक़े में कई क़ब्रिस्तान हैं. एक समाचारपत्र के मुताबिक़, सिंगापुर में अब केवल चोआ चूआकांग क़ब्रिस्तानों में ही अंतिम संस्कार होता है. टैन कहती हैं कि कार में मृतकों की तस्वीरों और मृत्यु लेखों के साथ कई खिलौने भी सजे हुए थे. यदि कोई व्यक्ति उस टैक्सी में यात्रा करने की हिम्मत कर सकेगा तो उन्हें आश्चर्य होगा. वैसे ऐसे किस्से ज़्यादातर हॉलीवुड की साइको किलर फिल्मों में देखे–सुने जाते रहे हैं. अगर वास्तव में कोई आदमी इस तरह की कार में घूमता है तो उसकी जांच ज़रूर होनी चाहिए.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

1991 में अल बशीर ने नेशनल इस्लामिक फ्रंट के नेता हसन अल तौराबी के साथ मिलकर सरकार बनाई और 1993 में ख़ुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया.

विश्व के प्रमुख तानाशाह

रीतिका सोनाली

अचानक से एक और तानाशाह के बारे में बातें होने लगी हैं. तानाशाही उस तरह की सरकार को कहते हैं जहां संपूर्ण सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है. वहां क़ानून का राज नहीं, शासक के हिसाब से सरकार चलती है. उसी के इशारे पर जज फ़ैसला सुनाते हैं, पुलिस लाठी चलाती है. ऐसे देशों में प्रेस तो होता है, लेकिन छपता वही है जो तानाशाह को पसंद होता है. दुनिया भर में क़रीब 55 ऐसे देश हैं जहां तानाशाही है. इसी के ख़िलाफ़ पश्चिम एशिया में लोग सड़कों पर हैं. उत्तरी अफ्रीका और अरब देशों के लोग आंदोलन कर रहे हैं. पहले ट्यूनीशिया के बेन अली गए, फिर होस्नी मुबारक का नंबर आ गया. अब सवाल है कि अगला नंबर दुनिया के किस देश के तानाशाह का आने वाला है. हम दुनिया के ऐसे दस तानाशाहों के बारे में बता रहे हैं जिनकी गद्दी ख़तरे में है.

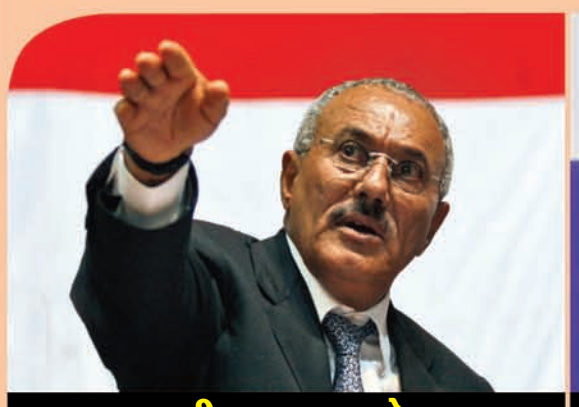

अली अब्दुल्लाह सालेह

दक्षिण यमन में अलगाववादी आंदोलन का आगाज़ पहले ही हो चुका है. दक्षिण और उत्तर यमन के दोनों क्षेत्रों में जाति को लेकर गहरी खाई बना दी गई है. राष्ट्रपति सालेह की ज़िद और ख़राब नीतियों से त्रस्त जनता उनसे इस्तीफ़े की मांग कर रही है. हालांकि उन्होंने आंदोलन को स्थिर बनाने के लिए 2013 में अपना पद छोड़ने की घोषणा करते हुए विपक्ष को राष्ट्रीय सरकार के गठन की पेशकश की, लेकिन विपक्ष ने इसे ठुकरा दिया. यमन के विभाजन से पहले 1977 में उत्तर यमन की सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल रहे सालेह यमन के प्रथम राष्ट्रपति इब्राहिम अल हम्दी की हत्या के बाद 1982 में जनरल पीपुल्स कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचिव बने और फिर 1983 में उत्तर यमन के राष्ट्रपति. सोवियत संघ के पतन के बाद दक्षिण यमन के कमज़ोर पड़ने पर उसे 1990 में उत्तर यमन से जोड़ा गया और इस संधि के बाद भी सालेह राष्ट्र प्रमुख बने रहे. इसके बाद यमन में बहुदलीय व्यवस्था की शुरुआत हुई और प्रत्येक तीन साल में संसदीय चुनाव कराने का फ़ैसला लिया गया. 1993 के चुनाव में जनरल पीपुल्स पार्टी की जीत के साथ सालेह फिर राष्ट्र प्रमुख बने. 1999 में वह पूर्व राष्ट्रपति नजीब कहतन के बेटे एवं अपनी ही पार्टी के नेता अल शाबी को हराकर पुन: राष्ट्रपति बने. सालेह ने अपने शासन के 24 साल पूरे होने के बावजूद 2006 में हुए चुनाव में धांधली करते हुए राष्ट्रपति पद हथिया लिया. इनके शासनकाल में देश को ग़रीबी, बेरोज़गारी, सांप्रदायिक तनाव, भ्रष्टाचार, मानवाधिकारों का हनन और शोषण जैसी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

होस्नी मुबारक

मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सदात की एक सैनिक परेड के दौरान कुछ इस्लामिक कट्टरपंथियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. इसके बाद उप राष्ट्रपति होस्नी मुबारक को राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठा दिया गया. नवंबर 1981 में जनमत के आधार पर उन्हें राष्ट्रपति चुन लिया गया. इसके बाद 1987, 1993, 1999 और 2005 तक हर बार वह राष्ट्रपति पद पर क़ाबिज़ रहे. ग़रीबी और दमन से नाराज़ हज़ारों लोगों ने 25 जनवरी, 2011 से मिस्र सरकार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसे रोकने के लिए होस्नी मुबारक ने पुलिस और टैंक भेजे. पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई मुठभेड़ में काहिरा, सुएज़ और एलेक्सेंड्रिया में 24 लोग मारे गए और 1000 से भी ज़्यादा घायल हुए. फरवरी के पहले हफ्ते में काहिरा के तहरीर स्क्वायर पर लाखों लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने मुबारक से देश छोड़ने के लिए कहा. मुबारक ने पहले कहा कि वह मिस्र नहीं छोड़ेंगे और इसकी वजह उन्होंने यह बताई कि जनता ग़रीबी एवं बेरोज़गारी से मुक्ति और लोकतांत्रिक सुधार संभवत: नहीं चाहती. उन्होंने कहा कि वह प्रगति की राह पर चलते रहेंगे, लेकिन 11 फरवरी, 2011 को मुबारक ने जनता के आगे घुटने टेक दिए और इस्तीफ़ा दे दिया.

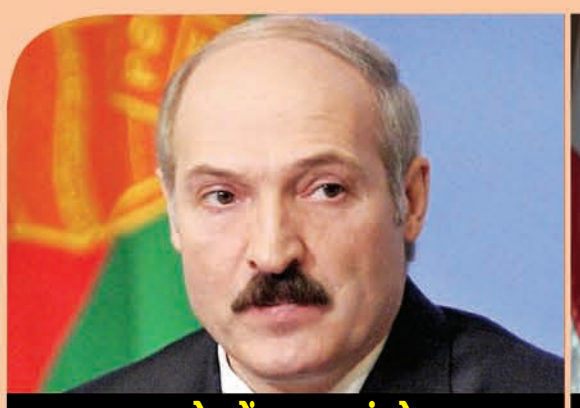

अलेक्जेंडर लुकाशंको

अलेक्जेंडर लुकाशंको ने 1994 में बेलारूस के राष्ट्रपति का पद संभाला था और वह अब तक अपनी गद्दी पर क़ायम हैं. लुकाशंको ने 1975 से 1977 तक फ्रंटियर ट्रूप्स में बॉर्डर गार्ड के तौर पर और फिर सोवियत आर्मी में 1980 से 82 तक काम किया. 1977-1978 में लुकाशंको ने मोगीलेव में कॉमसोमोल यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन की युवा शाखा बनाई, साथ ही कृषि फार्म के निदेशक के रूप में काम किया. 1990 में वह बेलारूस की सुप्रीम काउंसिल में अकेले ऐसे डिप्टी बने, जिन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाया. लुकाशंको ने 1993 में बेलारूसी संसद की एंटी करप्शन कमेटी के चेयरमैन के रूप में स्पीकर स्टैनीस्लाव के साथ 70 सरकारी अधिकारियों को दोषी बताते हुए सबसे इस्तीफ़ा दिलवाया. 1994 में नए बेलारूसी संविधान के निर्माण के साथ हुए राष्ट्रपति चुनाव में लुकाशंको जीत गए. राष्ट्रपति बनने के बाद सुप्रीम सोवियत के नियम-क़ानूनों को छिन्न-भिन्न करते हुए लुकाशंको ने देश का प्रतीक चिन्ह भी बदल दिया. नए संविधान से लुकाशंको के शासन को क़ानूनी तौर पर तानाशाही की इजाज़त मिल गई. लुकाशंको की आर्थिक नीति अनिश्चित और कथित मार्क्सवादी दृष्टिकोण वाली रही है. यहां के 80 प्रतिशत संसाधन राज्य द्वारा नियंत्रित हैं. रूसी समर्थन की वजह से ही समय पर वेतन और पेंशन का भुगतान हो पा रहा है. मानवाधिकार हनन बड़े पैमाने पर है. विपक्षी दलों के नेता नज़रबंद कर दिए जाते हैं. लुकाशंको की कैबिनेट के ही दो सदस्य रहस्यमय तरीक़े से ग़ायब हो गए. 2006 के चुनाव में लुकाशंको ने विपक्ष के खड़े होने पर प्रतिबंध लगा दिया.

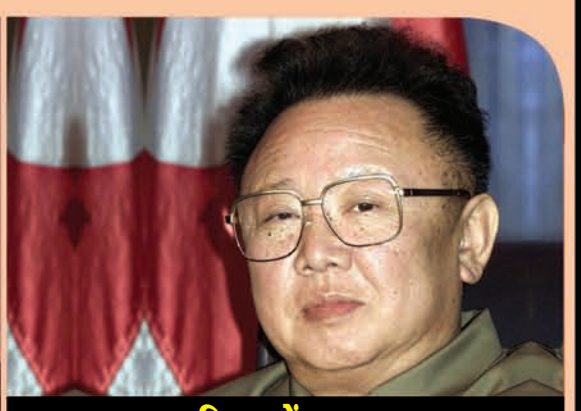

किम जोंग इल

विश्व से अलग-थलग पड़े राष्ट्र उत्तर कोरिया के प्रमुख नेता हैं किम जोंग इल. वह 1993 में नेशनल डिफेंस कमीशन के चेयरमैन बनने के बाद 1994 में सुप्रीम लीडर बने. किम जोंग इल ने राजनीति में अपनी शुरुआत 1964 में सत्तारूढ़ कोरियन वर्कर्स पार्टी से की. इसके बाद उन्हें पार्टी का विभाग सचिव बना दिया गया. उन्होंने 1960 में आर्थिक तर्क लिखे और मीडिया, लेखकों एवं और कलाकारों को पार्टी की आइडियोलॉजी से अवगत कराया. इल ने प्रचार-प्रसार के लिए हर तरह के मीडिया का ख़ूब इस्तेमाल किया, मसलन फिल्में, कला, किताबें और प्रेस. 1980 में उन्हें पोलित ब्यूरो का सदस्य मनोनीत किया गया और 1991 में वह उत्तर कोरियन सेना में सुप्रीम कमांडर बन गए. 1992 में उन्हें डियर लीडर के बजाय डियर फादर के नाम से पुकारा जाने लगा. इल को हर पांच साल में होने वाले सुप्रीम पीपुल्स असेंबली के चुनाव में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह सैन्य निर्वाचन क्षेत्र से सर्वसम्मति से मनोनीत हुए हैं. इल ने विश्व में सबसे बड़ी सेनाओं में से एक सेना का गठन किया है, मगर वह ग़रीबी हटाने में नाकामयाब रहे. आर्थिक अव्यवस्था और खाद्य पदार्थों की कमी के चलते 1990 में क़रीब बीस लाख लोगों की मौत हो गई. इल की सरकार पर अत्याचार, बंधुआ मज़दूरी, जबरन गर्भपात और तक़रीबन 2,00,000 लोगों को बंदी बनाने का आरोप है. उत्तर कोरिया की जनता की मुश्किलें किम जोंग के मरने के बाद ही दूर होंगी, क्योंकि उसके बाद उनका 20 वर्षीय बेटा किम जोंग राजगद्दी पर बैठेगा.

ओमर हसन अहमद अल बशीर

ओमर हसन अहमद अल बशीर सूडान के राष्ट्रपति हैं. वह नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं. सेना में ब्रिगेडियर बनने के बाद इन्होंने 1989 में कुछ अफसरों का समूह बनाया और तत्कालीन प्रधानमंत्री सादिक अल म्हदी को खदेड़ कर ख़ुद सत्ता पर अधिकार जमा लिया. इसके बाद सूडान में सेना का राज हो गया. जब यह रक्षा मंत्री थे, तभी देश में शरिया क़ानून लगा. 1991 में अल बशीर ने नेशनल इस्लामिक फ्रंट के नेता हसन अल तौराबी के साथ मिलकर सरकार बनाई और 1993 में ख़ुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया, लेकिन 1999 के अंतिम दिनों में अल बशीर ने संसद को निष्प्रभावी करके आपातकाल लगा दिया, क्योंकि तौराबी संसद को राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार देते हुए फिर से देश में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कराने की कोशिश कर रहे थे. 2000 में फिर से चुनाव हुए और अल बशीर जीत गए. उनकी नेशनल कांग्रेस पार्टी के लोगों से संसद भर गई. फ़र्ज़ी मतदान की वजह से विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया. अल बशीर के राज में कई हिंसक लड़ाइयां हुईं. दरफुर प्रांत में गुरिल्ला वेलफेयर की तर्ज पर जस्टिस एंड इक्वालिटी मूवमेंट हुआ. 2003 में इस प्रांत में तक़रीबन 3 लाख लोगों की हत्या करा दी गई या उन्हें विस्थापित कर दिया गया. सूडान में निजी मीडिया कंपनियां नहीं हैं और जो सरकारी मीडिया है, वह सरकार की नीतियों का ही प्रचार-प्रसार करता है.

महमूद अहमदीनिज़ाद

पेशे से इंजीनियर और शिक्षक रह चुके महमूद अहमदीनिज़ाद ईरान के छठे राष्ट्रपति हैं. वह एलायंस ऑफ बिल्डर्स ऑफ इस्लामिक ईरान के मुख्य नेता हैं. इस्लामिक रिवोल्यूशन के बाद अहमदीनिज़ाद ऑफिस ऑफ स्ट्रेनथेनिंग यूनिटी से जुड़ गए. मोहम्मद ख़तामी के राष्ट्रपति बनने पर उन्हें पद से हटा दिया गया. 2003 में तेहरान काउंसिल में मेयर का पद मिला. अब तक बने मेयरों की विचारधारा से बिल्कुल विपरीत एवं सख्त धार्मिक हथकंडे अपना कर वह 2005 में एलायंस ऑफ बिल्डर्स ऑफ इस्लामिक ईरान की मदद से जीते और राष्ट्रपति बने. अहमदीनिज़ाद राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पटल पर विवादास्पद रहे. देश में उनकी भर्त्सना आर्थिक संकीर्णता और मानवाधिकार हनन के लिए की जाती है. 2009 में अहमदीनिज़ाद के दोबारा सत्ता में आने की वजह से घरेलू हिंसा छिड़ गई और लोग उनके ख़िलाफ़ सड़कों पर उतर आए. यहां इंटरनेट और फोन कॉल्स की इजाज़त जांच के बाद ही संभव है, जिससे देश के बारे में जनता को सही जानकारी न मिल सके. विरोध करने वाले पत्रकारों को बंदी बनाया जा रहा है. प्रवासी लोगों को इंटेलिजेंस और क्रांतिकारियों की तरफ़ से लगातार धमकियां मिल रही हैं. विपक्षी दलों के नेताओं को आतंकित करने के लिए उन पर हमले कराए जाते हैं. देश में ग़रीबी और बेरोज़गारी की समस्या है. तेल और गैस की प्रचुर मात्रा के बावजूद यहां के संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं किया जा है. देश अव्यवस्था का शिकार है.

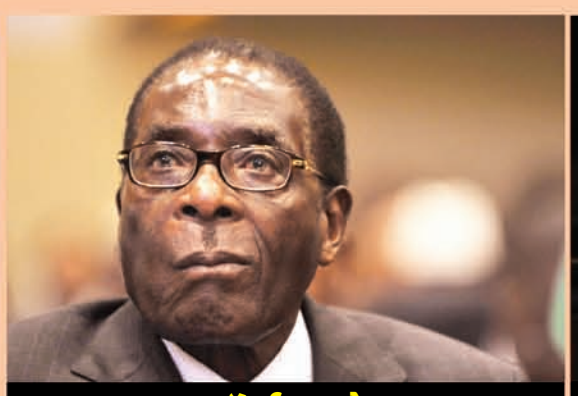

रॉबर्ट मुगाबे

जिंबाब्वे के वर्तमान राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे 1980 से देश का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्होंने 1980 से 1987 तक प्रधानमंत्री पद संभाला और 1987 में प्रधानमंत्री पद ख़त्म करके राष्ट्रपति बन गए. वह पहली बार 1960 में जिंबाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पार्टी के नेता के तौर पर उस समय प्रसिद्ध हुए, जब रोडेशिया में गोरे लोगों का अल्पसंख्यक राज चल रहा था और जिसके ख़िलाफ़ नेशनल यूनियन ने 1964 से 1979 के दौरान छापामार युद्ध छेड़ रखा था. मुगाबे को प्रभावशाली वक्ता, विवादों में घिरा रहने वाला व्यक्ति एवं लोगों को ध्रुवीकृत करने में माहिर राजनीतिज्ञ समझा जाता है. स्वतंत्रता संग्राम के बाद वह अफ्रीकियों के नायक के तौर पर उभर कर सामने आए थे. 1990, 1996 और 2002 में वह फिर से राष्ट्रपति बने. हालांकि उन पर धमकी देकर अपने पक्ष में वोट कराने का आरोप लगा था. 2008 में वह एक बार फिर चुने गए. उपनिवेशवाद का मुखर विरोधी होने के बावजूद मुगाबे की आलोचना हुई. सरकारी अधिकारी ख़निज भंडारों से अपनी जेबें भरते रहे, जबकि जिंबाब्वे की अर्थव्यवस्था नियंत्रण से बाहर चली गई. स्थानीय पत्रकारों ने जब मुगाबे पर लगे आरोपों की असलियत पता करने की कोशिश की तो उन पर अत्याचार किए गए.

हाउस ऑफ सऊद

अल सऊद कहलाने वाला हाउस ऑफ सऊद सऊदी अरब में सत्तारूढ़ तानाशाह परिवार है. इस परिवार के मुखिया राजा अब्दुल्लाह हैं. यह परिवार मोहम्मद बिन सऊद के वंशज और शेख़ मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की बेटी से बना है. यह परिवार सलाफी इस्लाम की सिफ़ारिश करता है और सऊदी अरब की एकता में यक़ीन रखता है. इस परिवार का सबसे प्रभावी व्यक्ति राजा अब्दुल्लाह है, जो सऊदी अरब की राजगद्दी पर बैठा है. इस शाही ख़ानदान में गद्दी का हक़ पिता से पुत्र को नहीं, बल्कि राजा अब्दुल अज़ीज़ के बच्चों में भाई से भाई को मिलता है. इस परिवार में क़रीब 7000 सदस्य हैं. सभी प्रकार की राजनीतिक शक्तियां परिवार के क़रीब 200 लोगों को मिली हैं, जो राजा अब्दुल अज़ीज़ के वंशज हैं. यह परिवार पिछले सौ सालों से राज कर रहा है, बिना किसी चुनावी प्रक्रिया के. तानाशाही के चलते यहां विपक्ष का अस्तित्व नहीं हैं. यहां शिक्षा का स्तर काफी ख़राब है. प्रति 7 में से 1 व्यक्ति अशिक्षित है. पिछले कुछ सालों में बेरोजगारी की समस्या 10 फ़ीसदी बढ़ गई है, वह भी तब, जबकि विश्व के 25 प्रतिशत तेल भंडार यहां हैं. तकरीबन 20 बिलियन डॉलर की संपत्तियों पर सत्तारूढ़ परिवार का क़ब्ज़ा है. यहां महिलाओं की स्थिति बदतर है, उन्हें बहुत कम अधिकार दिए गए हैं और काम करने की इजाज़त नहीं है.

एमोमाली रहमान

मध्य एशिया के छोटे से देश तज़ाक़िस्तान को मिली आज़ादी के अगले साल 1992 से शासन कर रहे एमोमाली रहमान ख़ूनी गृह युद्ध की वजह से सत्ता में आए. पूर्व सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य रहमान रूस के एक सत्तारूढ़ गुट के विरोध में इस्लामी गुट का नेतृत्व कर रहे थे. लाखों की संख्या में लोग मारे गए, लेकिन रहमान बच निकले और मध्य एशिया के दूसरे नेताओं की तरह उन्होंने तानाशाही को कट्टरपंथियों की धमकियों से बचने का एकमात्र उपाय माना और लागू किया.

अब्देलअज़ीज़ बूतफ्लिका

73 वर्षीय अब्देलअज़ीज़ 1999 से अल्जीरिया के राष्ट्रपति हैं. 1962 में फ्रांस से आज़ादी दिलाने वाले समाजवादी क्रांतिकारियों की पार्टी से अलग होकर नेशनल लिबरेशन फ्रंट ख़ुद एक पार्टी बन गया. इससे अब्देलअज़ीज़ लंबे वक़्त से जुड़े थे. 1990 में इस सत्तारूढ़ पार्टी ने इस्लामी कट्टरपंथियों से लड़ाई की, जिन्हें सरकार में उचित भागीदारी नहीं दी गई, क्योंकि सेना ने चुनाव का प्रावधान ही ख़त्म कर दिया था. अपने कार्यकाल में अब्देलअज़ीज़ ने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए दूसरी पार्टियों के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की, लेकिन वह कोशिश व्यर्थ चली गई. देश में बेरोज़गारी की गंभीर समस्या है और युवाओं के लिए अवसर की कमी है.

बाबा ने बड़े प्रेम से उसे समझाया, लक्ष्मी, इस जन्म में जब फकीर का चोला पहन ही लिया तो उसका धर्म भी निभाना पड़ेगा.

दिल्ली, 14 मार्च–20 मार्च 2011
चौथी दुनिया

साई बाबा की भिक्षा

प्रकृति की ही तरह हर जीवात्मा का मूल संस्कार है देना. प्रकृति का नियम भी है, जो जितना देगा, उसे उतना ही मिलेगा. लेकिन जब हम कुछ दे रहे होते हैं, तब हमें पता नहीं चलता कि हम दे रहे हैं, क्योंकि देना तो हमारे मूल में है और यही देयता की धारणा हमें दिव्यता प्रदान करती है.

ऑसिम खेत्रपाल

एक बार शिरडी के साई बाबा से उनकी परमभक्त लक्ष्मी ने पूछा, बाबा अब जबकि द्वारका माई में हर समय धूनी जलती रहती है, सुबह–शाम ग़रीबों की भूख मिटाती यह रसोई क्या आपके लिए दो रोटी नहीं दे सकती? बाबा ने बड़े प्रेम से उसे समझाया, लक्ष्मी, इस जन्म में जब फकीर का चोला पहन ही लिया तो उसका धर्म भी निभाना पड़ेगा. इस दीन दुनिया से निर्लिप्त फकीर का धर्म है हर गृहस्थ के घर जाकर भोग करके अपना निर्वाह करे, ताकि वे गृहस्थ भी दान के अपने धर्म को निबाह पाएं. गृहस्थ जब तक अपनी आय और अपने भोजन का कुछ प्रतिशत पुण्यात्माओं, ग़रीबों और जीव–जंतुओं को दान करता रहेगा, उसका घर धन–धान्य एवं ख़ुशियों से भरा रहेगा. बाबा ने यही किया. अपने जीवन के अंतिम दिन तक यह फकीर अपनी बिगड़ती हालत की परवाह न करते हुए फकीरी के इस धर्म को निभाता रहा. सचमुच साथियों, भारतीय शास्त्रों में दान के महत्व का बहुत गुणगान है. हर धर्म के पैगंबर या आध्यात्मिक गुरु ने मानव जीवन को सार्थक और सफल बनाने के लिए, जीवन का हर सुख पाने के लिए हर तरह के दान की बात की है. ज़रा सोचें कि दान देकर हमें क्या प्राप्त होगा? आप अपने अनुभवों को याद करें. हमें हमेशा किसी को कुछ देकर ख़ुशी ही होती है और नहीं तो किसी भूखे को खाना खिलाकर या अंधे व्यक्ति को सड़क पार कराकर हम इतना अच्छा क्यों महसूस करते हैं? ऐसा इसलिए, क्योंकि प्रकृति की ही तरह हर जीवात्मा का मूल संस्कार है देना. प्रकृति का नियम भी है, जो जितना देगा, उसे उतना ही मिलेगा. लेकिन जब हम कुछ दे रहे होते हैं, तब हमें पता नहीं चलता कि हम दे रहे हैं, क्योंकि देना तो हमारे मूल में है और यही देयता की धारणा हमें दिव्यता प्रदान करती है. लेकिन दुःख की बात यह है कि भय और संशय के इस माहौल में दान एवं धर्म के इस प्रकृति प्रदत्त गुण को भी हमने कारोबार का एक हिस्सा बना लिया है. कभी अपने ग्रहों के दोष ठीक करने के लिए कभी किसी और फल की प्राप्ति के लिए. कई बार तो अपने सिर पर आए संकट दूसरों पर डालने के लिए हमने दान देना शुरू कर दिया. आज अध्यात्म का काम करना भी फैशन की सूची में आने लगा है और दान देना स्टेटस सिंबल बन गया है. लेकिन जो प्रकृति का गुण आप में स्वतः ही है, उससे मिलने वाले पुण्यों से ख़ुद को परंपराओं या नियमों के चक्रव्यूह में फंसाकर वंचित न करें. आज स्थूल में कुछ देने की स्थिति नहीं भी है तो सूक्ष्म में शुभ भावना, शुभकामना, सच्ची ईमानदारी की भावना, प्रेम एवं वात्सल्य का भाव तो दान कर ही सकते हैं. किसी ग़रीब की आवाज़ सुनकर उसके आंसुओं को पोछ तो सकते हैं. रोते को सांत्वना तो दे सकते हैं, किसी डूबते को आशा और विश्वास का तिनका तो दे ही सकते हैं. आप और हम इतना भी कर लेंगे तो यक़ीन रखिए कि सामने वाला आपके हौसले या विश्वास से अपने आप ही उठ जाएगा और अपने जीवन को सफल कर पाएगा. दान पैसे का, दवा का, अनाज का या शुभकामना का, जिस भाव से दिया जाए, वह महत्वपूर्ण होता है.

ओम साई राम.

feedback@chauthiduniya.com

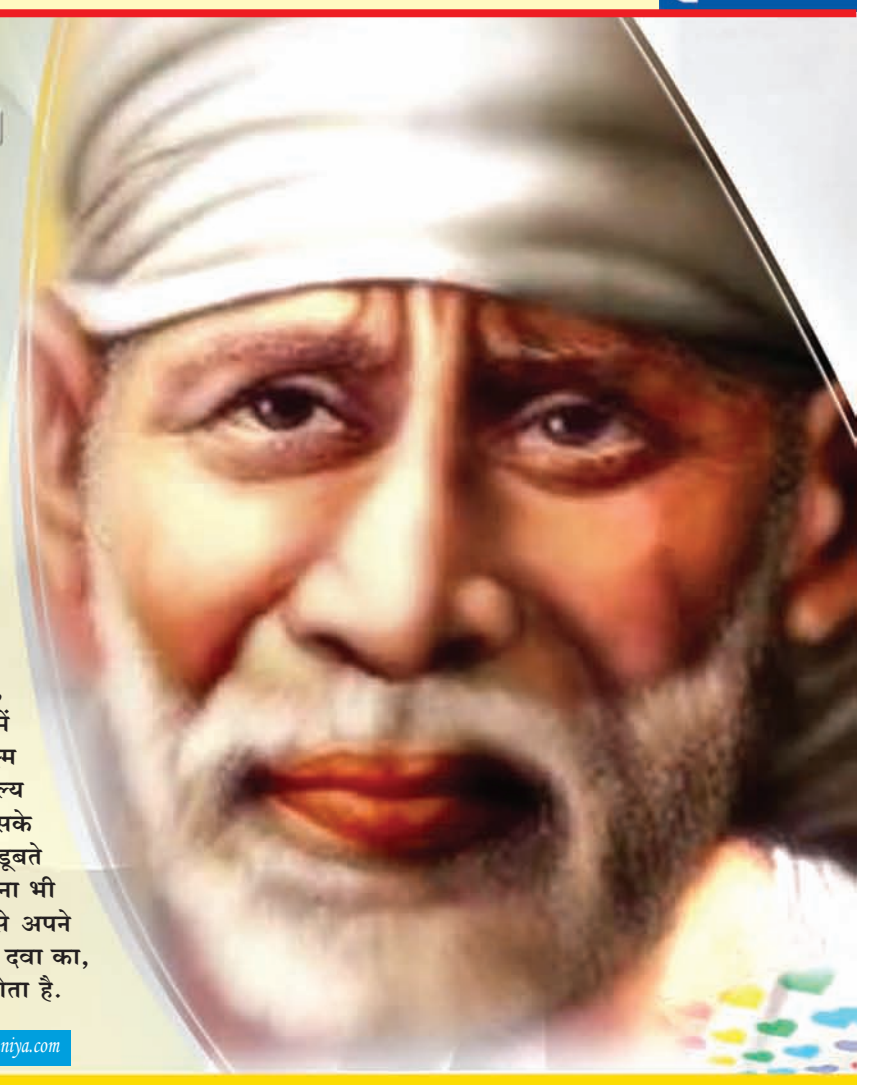

पहेली का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग साई सच्चरित्र का पाठ करें. सात दिन के अंदर इसका संपूर्ण पाठ करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी.

इस बार का प्रश्न है–बाबा ने भिक्षा में मिली चाट भाकरी से बहुत लोगों का पेट भर दिया. उन्हें भिक्षा देने वाली भक्त कौन थीं? साई बाबा को साई कहकर पुकारने वाला पहला व्यक्ति कौन था?

सही जवाब भेजने वाले तीन विजेता पाठकों को फाउंडेशन की ओर से आकर्षक ईनाम मिलेंगे. आप अपने जवाब हमें भेज सकते हैं इस पते पर

शिरडी साई बाबा फाउंडेशन,
एच 252, कैलाश प्लाजा, संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश
नई दिल्ली– 110065
आप अपने जवाब **info@ssbf.in** भी पर भी भेज सकते हैं.
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें. 011–46567351, 46567352

ज्ञानोदय

असफलता केवल यही सिद्ध करती है कि सफलता के लिए पूरे प्रयास नहीं किए गए. *स्व. मालती कपूर*

मां होने के कारण नारी का स्थान भगवान से भी ऊंचा है. *प्रेमचंद*

विचारों को दबाया नहीं जा सकता. एक दिन विचार कंदरा फोड़ कर संसार पर छा जाते हैं. *स्व. तारा चंद्र मेहरोत्रा*

श्री साई महिमा

श्री साई राम परम सत्य, प्रकाश रूप, परम पावन शिरडी निवासी, परम ज्ञान आनंद स्वरूप, प्रज्ञा प्रदाता, सच्चिदानंद स्वरूप, परम पुरूष योगीराज, दयालु देवाधिदेव हैं, उनको बार बार नमस्कार.

ग्यारह वचन

१. जो शिरडी आएगा। आपद दूर भगाएगा।
२. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर। पैर तले दुःख की पीढ़ी पर।
३. त्याग शरीर चला जाऊँगा। भक्त हेतु दौडा आऊँगा।
४. मन में रखना दृढ़ विश्वास। करे समाधी पूरी आस।
५. मुझे सदा जीवित ही जानो। अनुभव करो सत्य पहचानो।
६. मेरी शरण आ खाली जाए। हो कोई तो मुझे बताए।
७. जैसा भाव रहा जिस मन का। वैसा रुप हुआ मेरे मन का।
८. भार तुम्हारा मुझ पर होगा। वचन न मेरा झूठा होगा।
९. आ सहायता लो भरपूर। जो माँगा वह नही है दूर।
१०. मुझ में लीन वचन मन काया। उसका ऋण न कभी चुकाया।
११. धन्य धन्य व भक्त अनन्य। मेरी शरण तज जिसे न अन्य।

संपर्क करें:
शिरडी साईं बाबा फाउन्डेशन
252-H, LGF कैलाश प्लाजा, सन्तनगर, ईस्ट अफ् कैलाश, मेन रोड, नई दिल्ली–110065.
Tel./Fax: 91-11-46567351/52
web: www.ssbf.in

कृष्ण की नगरी में आपका अपना घर!

Giriraj Sai Hills

Sai Vihar Township
Spiritual home... away from home

- Fully Furnished and Spacious studio Apartments.
- One Bedroom Apartments.
- Two bedroom Apartments.
- Fully Furnished Villas.

STARTING FROM RS. 9.65 LAKHS*

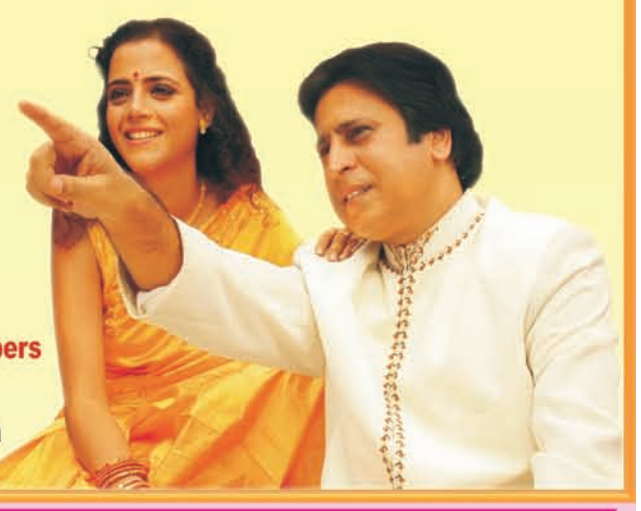

AUM Infrastructure & Developers
Aum Infrastructure & Developers
Email: info@ssbf.in
Website: www.girirajsaihills.in

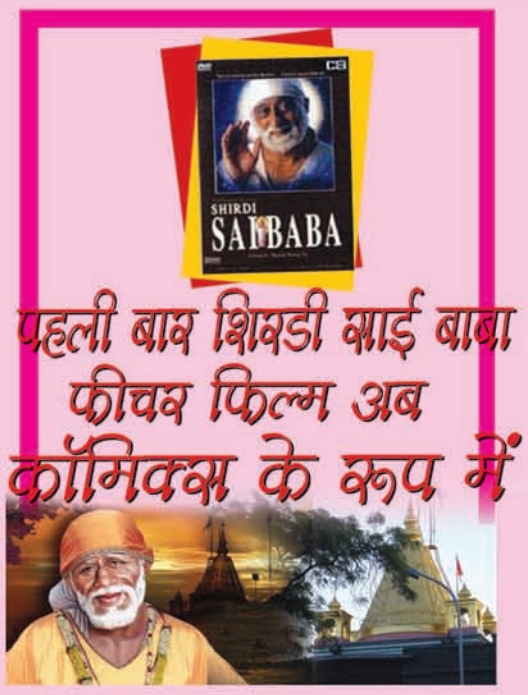

सभी साई भक्तों को विनम्रता से सूचित किया जाता है कि आप अपने साई अनुभव, साई उत्सवों आदि की विस्तृत सूचना, फाउंडेशन में सदस्यता के लिए info@ssbf.in पर मेल या 011–46567351/52 पर संपर्क कर सकते हैं.

लेखक का दावा है कि उसे यह उपन्यास लिखने में नौ वर्ष लगे. दरअसल अगर हम इस उपन्यास के कथानक को देखें तो यह पूरा उपन्यास एक फैमिली ड्रामा है, जिसमें वाल्टेयर और पैटी का प्यार परवान चढ़ता है.

अनंत विजय

उपन्यासकार की आज़ादी

अमेरिकी लेखक जोनाथन फ्रेन्ज का उपन्यास फ्रीडम पिछले कई हफ्तों से बेस्ट सेलर की सूची में बना हुआ है. यह उपन्यास न केवल बेस्ट सेलर की सूची में शीर्ष पर है, बल्कि पाठकों के साथ–साथ आलोचकों ने भी इसे खुले दिल से सराहा है. इस उपन्यास को लेकर अमेरिका और यूरोप में काफी शोरगुल मचा, हर अख़बार और पत्रिका में इसकी चर्चा हुई. उपन्यास की लोकप्रियता और उसकी शैली को लेकर आलोचक इतने अभिभूत हो गए कि कई लोगों ने इसके लेखक जोनाथन फ्रेन्ज को टॉलस्टॉय और टॉमस मान के सामांतर खड़ा कर दिया. विश्व प्रसिद्ध टाइम पत्रिका ने अपने कवर पर जोनाथन की तस्वीर छापी और उन्हें पिछले दस सालों में प्रकाशन जगत का सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाला लेखक क़रार दे दिया. आम तौर पर उपन्यासों को बेदर्दी से कसौटी से पर कसने वाले अख़बार न्यूयॉर्क टाइम्स में जब इसकी समीक्षा छपी तो इसे अमेरिकन फिक्शन का मास्टर पीस क़रार दिया गया. लब्बोलुआब यह कि फ्रीडम को उसके पाठकों ने काफी पसंद किया.

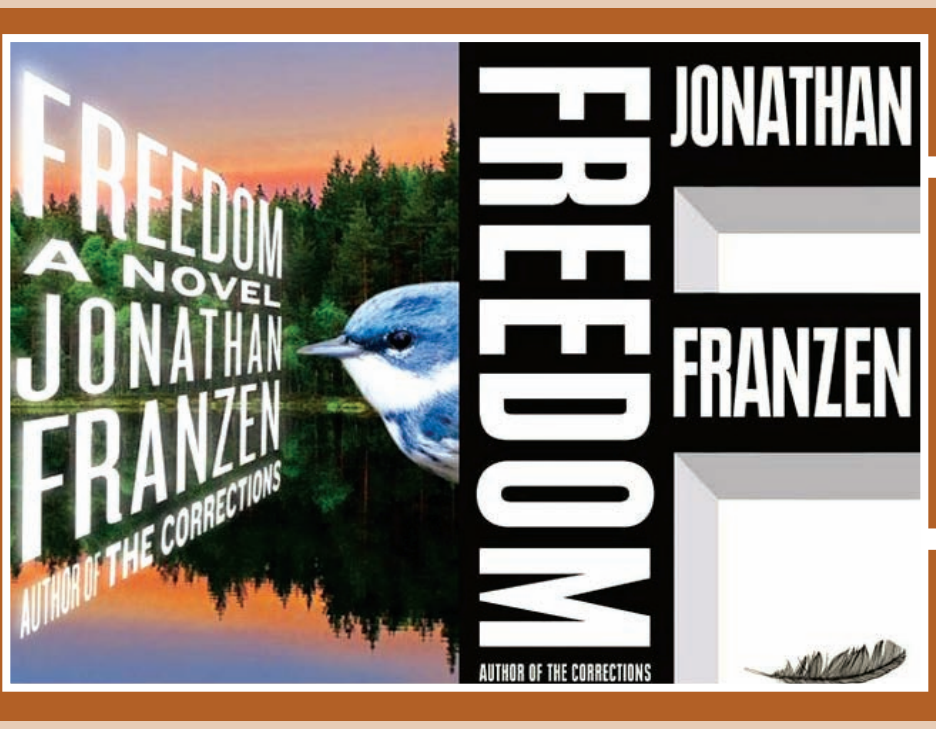

समीक्ष्य पुस्तक : फ्रीडम
लेखक : जोनाथन फ्रेन्ज
प्रकाशक : फोर्थ एस्टेट, लंदन
मूल्य : 882 रुपये

लेखक का दावा है कि उसे यह उपन्यास लिखने में नौ वर्ष लगे. दरअसल अगर हम इस उपन्यास के कथानक को देखें तो यह पूरा उपन्यास एक फैमिली ड्रामा है, जिसमें वाल्टेयर और पैटी का प्यार परवान चढ़ता है. वे दोनों शादी के बंधन में भी बंधते हैं और फिर सेंट पॉल शहर के प्रतिष्ठित इलाक़े में घर ख़रीद कर अपना वैवाहिक जीवन शुरू करते हैं. पैटी एक आदर्श पड़ोसी की तरह व्यवहार करती है, जो बहुधा अपने अगल–बगल में रहने वालों को बैटरी रिसाइकल करने की युक्ति बताती है तो कभी लोगों को यह समझाती है कि कैसे स्थानीय पुलिसकर्मियों का उपयोग किया जा सकता है. पैटी और वाल्टर का जीवन बेहद रोमांटिक तरीक़े से गुजरता है और वाल्टेयर की नज़र में पैटी एक बेहतरीन माशूका है, जो पत्नी बनने के बाद भी उतनी ही शिद्दत से उसे प्यार करती है. प्यार–मोहब्बत से चल रही ज़िंदगी के बीच एक अहम मोड़ तब आता है, जब कुछ दिनों बाद उन्हें एक पुत्र पैदा होता है. पुत्र पैदा होने के बाद समय का पहिया घूमता है और कहानी थोड़ी तेजी से चलती है और समय के साथ पैटी एवं वाल्टेयर जवान जोड़े से बुढ़ाते जोड़े में तब्दील होने लगते हैं.

इस उपन्यास की कहानी में रोचक मोड़ तब आता है, जब पैटी का बेटा किशोरावस्था में पहुंचता है. टकराहट होती है मां के सपनों और बेटे की आकांक्षाओं में. यहां इस मनोविज्ञान को लेखक ने बेहद सूक्ष्मता से पकड़ा है. किशोरवय बेटे जॉय और मां पैटी के बीच जो मनमुटाव और विचारों का संघर्ष चलता है, उसकी परिणति होती है कि एक दिन उनका इकलौता बेटा घर छोड़कर आक्रामक रिपब्लिकन पड़ोसी के घर में रहने चला जाता है. यह उपन्यास एक फैमिली ड्रामा के अलावा अभिभावकत्व के संघर्षों की दास्तां भी है. बाद में जॉय शादी कर लेता है और अपनी पत्नी कोनी के साथ रहने लगता है. बुढ़ाती मां पैटी अपने बेटे के पास तो जाना चाहती है, लेकिन उसकी पत्नी कोनी को वह पसंद नहीं करती है. यहां आपको टिपिकल इंडियन मानसिकता भी नज़र आ सकती है. जोनाथन के हर उपन्यास में एक भारतीय पात्र तो होता ही है, इसलिए मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि जोनाथन ने भारतीय परिवार की मन:स्थिति को अमेरिकी परिवेश में ढाला है. ग़ौरतलब है कि जोनाथन ने अपने इस उपन्यास में भी एक भारतीय पात्र को रखा है. इस उपन्यास में वाल्टेयर की सेक्रेटरी ललिता एक भारतीय लड़की है. इसके पहले भी जोनाथन ने अपने उपन्यास–द ट्वेंटीसेवन्थ सिटी में मुंबई की एक लड़की एस जामू को एक शहर के पुलिस प्रमुख के रूप में चित्रित किया है.

कहानी आगे बढ़ती है तो जॉय अपनी पत्नी के अलावा बेहद ख़ूबसूरत लड़की जेना में सुकून तलाशता है. उधर पैटी को अपने पति वाल्टेयर की सेक्रेटरी ललिता फूटी आंखों नहीं सुहाती. इस तरह के परिवेश में जहां बेटा अपनी पत्नी के रहते प्रेमिका की जुल्फों में उलझा हो और पति अपनी सेक्रेटरी के साथ इश्क की पींगें बढ़ा रहा हो तो एक महिला के दिमाग़ में क्या चल रहा होगा. पैटी की मानसिकता और खंडित व्यक्तित्व का जो सूक्ष्म चित्रण जोनाथन ने किया है, वह इस उपन्यास को रोचकता की नई ऊंचाई पर ले जाता है. कहानी में ही यह तथ्य भी सामने आता है कि दरअसल पैटी का जो असुरक्षा बोध है, उसके पीछे का मनोविज्ञान यह है कि पैटी जब किशोरी थी तो देश के प्रथम परिवार के बेटे ने उसके साथ डेट रेप किया था. चूंकि अपराधी देश के बड़े परिवार से था, इसलिए पैटी के मां–बाप इस अपराध को भुनाने में लग गए और बेटी का सौदा कर अपने फ़ायदे की सोचने लगे. पैटी को जब अपने मोलभाव का पता चला तो वह बेहद खिन्न हो गई. उसे लगने लगा कि घर–परिवार सब बेकार है, सब अपने फ़ायदे की सोचते हैं. उस वक़्त से ही पैटी के अंदर बेहद असुरक्षा का बोध घर कर गया था, जो उसके मां बनने के बाद बढ़ता चला गया.

जोनाथन के इस उपन्यास के सारे पात्रों ने कहीं न कहीं ज़बरदस्त पाबंदी के बाद स्वतंत्रता के स्वाद को चखा है, लेकिन ज्यों ही वे स्वतंत्रता के जोश में उन्मादी होने लगते हैं, उन्हें ज़बरदस्त ठोकर लगती है और वे ज़मीन पर आ जाते हैं. अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो बॉस्केट बॉल खिलाड़ी पैटी जब आज़ाद होकर दौड़ते हुए सड़क पर आती है तो अचानक फिसल कर गिरती है और अस्पताल पहुंच जाती है. पैटी के जोश और फिर उसके ठोकर खाकर गिर जाने की घटना से इस उपन्यास का एक पैटर्न दिखाई देता है, जिसका ज़िक्र मैं ऊपर कर चुका हूं. लेकिन जिस तरह से सांप–सीढ़ी के खेल की तरह इस उपन्यास की कथा चलती है, उससे रोचकता बरक़रार रहती है और वह पाठकों को लगातार बांधे रखती है. इसके अलावा घटनाओं और परिस्थितियों का जो सूक्ष्म चित्रण लेखक ने किया है, उससे उनकी मेहनत साफ़ तौर पर झलकती है. लेखक ने इस बहाने अमेरिकी समाज का चित्रण किया है. यह उपन्यास बराक ओबामा के अमेरिका के राजनीतिक पटल पर उदय के साथ ख़त्म होता है, जहां जीत की उम्मीद है और बदलाव की आहट भी.

(लेखक आईबीएन–7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

ग़ज़लों से दुनिया को संवारने की जुस्तजू

चांद शेरी हिंदी पत्र–पत्रिकाओं में लगातार छपते रहे हैं. उनकी कुछ ग़ज़लें तो विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं में इतनी बार छप चुकी हैं कि एक पंक्ति पढ़ते ही पाठक अगला काफ़िया ख़ुद पूरा कर देते हैं. ज़र्द पत्ते हरे हो गए, चांद शेरी की लोकप्रिय ग़ज़लों का संकलन है. इसका पहला संस्करण दिसंबर 1999 में प्रकाशित हुआ था. इस पुस्तक पर राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर ने प्रथम प्रकाशित कृति पर दिया जाने वाला सुमनेश जोशी पुरस्कार भी दिया था. पिछले दिनों बोधि प्रकाशन जयपुर ने जर्द पत्ते हरे हो गए का दूसरा संस्करण प्रकाशित किया है. इसकी अधिकांश ग़ज़लें एकाधिक अवसरों पर प्रकाशित हो चुकी हैं और शायर के मिजाज़ से पाठकों को रूबरू कराती हैं.

समीक्ष्य पुस्तक : जर्द पत्ते हरे हो गए
रचनाकार : चांद शेरी
प्रकाशक : बोधि प्रकाशन, जयपुर
मूल्य : 50 रुपये

चांद शेरी एक भावुक किस्म के इंसान हैं, जो अपने से बाहर दुनिया के सुखों में अपने सुख की तलाश करते हैं. इन सुखों की तलाश करते हुए जहां कहीं उनका विसंगतियों से सामना होता है, वह अपनी पीड़ा को शायरी के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं. एक ग़ज़ल में वह कहते भी हैं, वक़्त भी कैसी पहेली दे गया/उलझनें सौ, जां अकेली दे गया/ ग़म ग़लत करने को वह शेरी मुझे/ शाइरी जैसी सहेली दे गया. चांद शेरी के लिए ग़ज़ल गोई फकत ग़म ग़लत करने की कोशिश प्रतीत नहीं होती. उनकी ग़ज़लों को पढ़ते हुए प्रतीत होता है कि उनके लिए ग़ज़ल कहना सराबों में किसी खुलूस की तलाश करते हुए आंखों में सुकून का समंदर उतरने की तरह है, मैं ढूंढता रहा हूं सराबों में मुद्दतों/आंखों में मेरी एक समुंदर उतर गया.

चूंकि सराबों में किसी तलाश में भटकते हुए आदमी की आंखों में समुंदर उतरना एक अपूर्व घटना होती है, इसलिए चांद शेरी इसका मूल्य भी समझते हैं और इसलिए वह माहौल में मौजूद हर रूहानी ख़ूबसूरती को पूरी शिद्दत के साथ सहेजे रखने का आह्वान अपनी ग़ज़लों में तरह–तरह से करते हैं. एक जगह वह कहते हैं, कच्ची मिट्टी के इन घरौंदों से/पत्थरों जैसी बात मत करना. दूसरी जगह वह विश्वास बंधाते हैं, जुबां पर किसी की दुआ रख/ख़याल अमन का, ख़ैर का रख/ मिलेगी तुझे तेरी मंज़िल/ क़दम–दर–क़दम हौसला रख. कई ग़ज़लों में वह आने वाली चुनौतियों के प्रति आगाह भी करते हैं, जब परिंदा उड़ान पर होगा/तीर कोई कमान पर होगा अथवा शेरी बुझेगी आग हवस की भी किस तरह/अपने गुनाह में भी अदा ढूंढते हैं लोग.

इस संकलन की अधिकांश ग़ज़लों का प्रस्थान बिंदु वह क्षण है, जब शायर कहता है, आज का रांझा हीर बेच गया/ हीरे जैसा ज़मीर बेच गया/ इक कबाड़ी को वो निरा ज़ाहिल/ मीर, तुलसी, कबीर बेच गया/ इक कबीले की शान रखने को/अपनी बेटी वजीर बेच गया/ बाप–दादा की उस हवेली को/एक अय्याश अमीर बेच गया. धार्मिक उन्माद फैलाकर सामाजिक सौहार्द को चुनौतियां देने की कोशिशों ने शायर को बहुत उद्वेलित किया है. यह पीड़ा उसकी ग़ज़लों में बार–बार सामने आई है, मंदिरों का, मस्ज़िदों का आदमी/बस्तियों की शादमानी ले गया. हैरां हैं मंदिर– मस्जिद भी/उनकी खातिर खंजर कितने? राम तेरी सरजमीं पर लोग अब/नफरतों की आग फैलाने चले/मंदिरों के, मस्जिदों के आदमी/बस्तियां यूं ही उजड़वाने चले.

कुल मिलाकर ज़र्द पत्ते हरे हो गए की ग़ज़लें पढ़ना एक ऐसे रचनाकार से साक्षात की तरह है, जो अपने समय की विसंगतियों से व्यथित होने के बावजूद दुनिया में जहां भी और कुछ भी अच्छा है, उसे अपनी ग़ज़लों में पिरोकर समय और समाज के सामने रखना चाहता है. यही चेतना इस संकलन को महत्वपूर्ण बनाती है.

अतुल कनक
feedback@chauthiduniya.com

32 जीबी की एक्सपेंडेबल मेमोरी से इस फोन ने रचा है एक शानदार इतिहास. इन बिल्ट म्यूज़िक प्लेयर एवं रिकॉर्डिंग सहित एफएम रेडियो से लीजिए संगीत का भरपूर आनंद.

मोबाइल पर वर्ल्ड कप का मज़ा

इस फोन का स्क्रीन साइज 2.4 इंच है. इस फोन की ख़ासियत है कि आप चाहे इसे वर्टिकल रखें या हॉरिजंटल, यह फोन स्क्रीन को अपने आप एडजस्ट कर लेता है.

जेन मोबाइल कंपनी ने एक ऐसा मोबाइल लांच किया है, जिस पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड कप, वह भी बिल्कुल मुफ्त! आप सोच रहे होंगे क्रिकेट बिना कोई पैसा ख़र्च किए भला कैसे देखा जा सकता है. जेन मोबाइल ने जेन–82 एनालॉग मोबाइल फोन लांच किया है, जो टीवी और मोबाइल दोनों का काम करेगा. जैसा कि आप जानते हैं, वर्ल्ड कप में टीम इंडिया द्वारा खेले जा रहे अधिकतर मैच दूरदर्शन पर आ रहे हैं. इस मोबाइल की ख़ासियत यह है कि आप इसके ज़रिए दूरदर्शन चैनल अपने मोबाइल पर ही देख सकते हैं. इसमें लगा एंटीना दूरदर्शन जैसे फ्री टू एयर चैनलों को कैच करता है, जिन्हें आप बिना कोई शुल्क दिए देख सकते हैं. है न कमाल की बात! इस मोबाइल में कोई ऑपरेटर न होने से आप मुफ्त में क्रिकेट मैच का मज़ा ले सकते हैं, जबकि कई कंपनियां पहले से ऑपरेटर आधारित चैनल देखने की सुविधा मुहैया कराती हैं, लेकिन उसके लिए ग्राहकों को अलग से चार्ज देना पड़ता है. इस फोन का स्क्रीन साइज़ 2.4 इंच है. इस फोन की ख़ासियत है कि आप चाहे इसे वर्टिकल रखें या हॉरिजंटल, यह फोन स्क्रीन को अपने आप एडजस्ट कर लेता है. दूसरी बड़ी ख़ासियत इसकी बैट्री है, जिससे आप छह घंटे तक लगातार मैच का लुत्फ़ उठा सकते हैं. साथ ही 3.5 एमएम जैक के ज़रिए आप कमेंट्री भी सुन सकते हैं. डेटा या डाउनलोड चार्ज न होने के कारण यह फोन आपको बेहद पसंद आएगा.

मज़ेदार कैमरा

ख़ूबसूरत पलों को संजोने के लिए फ्यूजी फिल्म ने कैमरे का एक नया मॉडल लांच किया है. कंपनी ने फाइनपिक्स–ए सीरीज कैमरों की ज़बरदस्त सफलता के बाद भारतीय बाज़ार में उतारा है फाइनपिक्स–एवी–200 कैमरा. इस कैमरे में कई विशेषताएं हैं. यह यूनिक मेगापिक्सल कैमरा है, जिसमें हाई रेज़ोल्यूशन सेंसर्स के साथ हाई सेंसिटिविटी सेटिंग्स मौजूद हैं. कैमरे की ख़ासियत है इसकी डिजिटल इमेज स्टैबलाइजेशन टेक्नोलॉजी. इस ख़ास कैमरे में हैं कई और भी शानदार फीचर्स, जैसे–स्क्रीन रिक्गनिशन ऑटो मोड, जो सीन टाइप और शूटिंग कंडीशंस की पहचान करके कैमरे के फोकस, एक्सपोज़र और वाइट बैलेंस को पाने में सक्षम है. इसमें महज़ एक बटन पुश करके ही आप पा सकते हैं फ्लोलैस फोटो. इसके अलावा प्री–प्रोग्राम्ड सीन मोड्स, सिंगल एवं ट्रैकिंग ऑटो फोकस, फेस डिटेक्शन, ऑटोमैटिक रेड आई रिमूवल, मल्टीपल जूम, मोशन पैनारोमा मोड एवं लाइटवेट डिज़ाइन आदि. शार्प, क्लीयर और कलर लोडेड तस्वीरों के लिए इसमें सबसे ख़ास है मल्टीपल जूम. फ्यूजी के इस हॉट न्यू हाई–रेस फाइनपिक्स–एवी–200 कैमरे की क़ीमत है तक़रीबन छह हज़ार रुपये.

नया एयर वायरलेस माउस

पावरफुल 1600 डॉट्स प्रति इंच (डीटीआई) ऑप्टिकल इंजन वाला एयर वायरलेस माउस. 17 इंच और इससे अधिक बड़ी बिग स्क्रीन के लिए यह है बेहद यूज़फुल. इसमें कई ऐसी ख़ूबियां हैं, जो इसे बनाती हैं आम माउस से ख़ास.

अब लार्ज स्क्रीन कंप्यूटर यूजर्स के लिए होगा रिस्ट मूवमेंट और भी आसान, क्योंकि कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों के लिए माउस से होने वाली समस्याएं हो जाएंगी कम और कंप्यूटर इस्तेमाल करना होगा और भी आसान.

डिजिटल लाइफ स्टाइल उत्पादों के अग्रणी निर्माता एमकेट लाए हैं पावरफुल 1600 डॉट्स प्रति इंच (डीटीआई) ऑप्टिकल इंजन वाला एयर वायरलेस माउस. 17 इंच और इससे अधिक बड़ी बिग स्क्रीन केलिए यह है बेहद यूज़फुल. इसमें कई ऐसी ख़ूबियां हैं, जो इसे बनाती हैं आम माउस से ख़ास. जैसे 2.5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, पीसी एवं लैपटॉप के लिए हाई क्वालिटी वायर फ्री कंट्रोल, उत्कृष्ट ग्रिप के लिए वेलवेट टच और स्लिम डिज़ाइन आदि. यह माउस पावर ऑन–ऑफ बटन के साथ मल्टी लेवल पावर सेविंग तकनीक से लैस है. स्पीड और सेंसिटिविटी के मामले में एयर माउस बाज़ार में मौजूद किसी भी माउस की तुलना में देता है डबल स्पीड. सुविधाओं और क्षमताओं से लबालब इस माउस की क़ीमत है केवल 850 रुपये.

नोकिया के नए हैंडसेट

नोकिया सी सीरीज़ के इन ख़ूबसूरत हैंडसेट्स के साथ आपको एक महीने तक ओवी लाइफ टूल्स सर्विस भी फ्री एक्सेस करने की सुविधा मिलती है.

नोकिया ने बेहद किफ़ायती दाम में दो नए स्टाइलिश फोन पेश किए हैं नोकिया सी–1–01 और सी–1–02. उक्त फोन आपको देते हैं इंटरनेट और मल्टी मीडिया कार्य प्रणालियों को आसानी से एक्सेस करने की सुविधाएं. इन हैंडसेट्स में आप ब्लूटुथ, एमएमएस एवं यूएसबी की मदद से आसानी से डाटा शेयर कर सकते हैं. नोकिया सी सीरीज़ के इन ख़ूबसूरत हैंडसेट्स के साथ आपको एक महीने तक ओवी लाइफ टूल्स सर्विस भी फ्री एक्सेस करने की सुविधा मिलती है. 32 जीबी की एक्सपेंडेबल मेमोरी से इस फोन ने रचा है एक शानदार इतिहास. इन बिल्ट म्यूज़िक प्लेयर एवं रिकॉर्डिंग सहित एफएम रेडियो से लीजिए संगीत का भरपूर आनंद. नोकिया सी–1–01 में आप इन बिल्ट वीजीए कैमरे की मदद से वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी भी कर सकते हैं. इन हैंडसेट्स की क़ीमतें हैं क्रमशः 2789 एवं 2394 रुपये.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

पिछले विश्वकप में भी पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी टीमों को उलटफेर का शिकार बनाकर सनसनी फैलाने वाले आयरलैंड का नाम बीच में किसी प्रतिस्पर्धा में नहीं सुना गया.

क्रिकेट वर्ल्डकप

जाने कहां गुम हो जाती हैं ये टीमें

राजेश एस कुमार

वर्ल्डकप 2011 अब तक अपने रोमांचक दौर पर है. जैसा कि हर बार होता है, इस बार भी कई उलटफेर हुए और आगे भी होंगे. जिन टीमों को फिसड्डी माना जाता है या यूं कहें कि जिन्हें सिर्फ़ ग्रुप की लिस्ट लंबी करने के लिए शामिल किया जाता है, वही टीमें शुरुआती दौर में बड़ी-बड़ी टीमों को हराकर या उन्हें कांटे की टक्कर देते हुए रोमांचक मोड़ पर लाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं. इन टीमों में आयरलैंड, नीदरलैंड, ज़िम्बाब्वे, कनाडा और बांग्लादेश का नाम लिया जा सकता है. इन सभी टीमों में एक चीज कॉमन है, वह यह कि इन सभी टीमों के नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सिर्फ़ तब सुनाई देते हैं, जब वर्ल्डकप का आयोजन होता है. उसके बाद पता नहीं, ये सारी टीमें कहां ग़ायब हो जाती हैं. हालांकि इस मामले में कुछ हद तक बांग्लादेश को अपवाद माना जा सकता है. यह टीम कभी-कभी एशियाई देशों में होने वाली क्रिकेट प्रतिस्पर्धाओं में खेलती हुई नज़र आ जाती है, लेकिन प्रदर्शन वही ढाक के तीन पात वाला ही रहता है.

कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि विश्वकप में अपने उलटफेर प्रदर्शन से बड़ी-बड़ी टीमों के छक्के छुड़ाने वाली इन नई नवेली टीमों का आख़िर बाद में क्या होता है. इस प्रतिस्पर्धा के ख़त्म होने के बाद ये कहां गायब हो जाती हैं. बाद में जब भी कोई बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता होती है तो इन्हें उसमें शामिल क्यों नहीं किया जाता है. अगर इनका प्रदर्शन इतना ही ख़राब होता तो फिर ये उलटफेर क्यों करतीं, जैसा कि इस बार इंग्लैंड और काफ़ी हद तक पाकिस्तान के साथ हो चुका है. अगर इस पर यह तर्क दिया जाए कि ये उलटफेर सिर्फ़ तुक्के के बल पर हुए हैं तो इसका मतलब ये टीमें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भाग लेने लायक हैं ही नहीं. आख़िर कब तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वहीं गिने-चुने देशों के नाम सुनाई देते रहेंगे? क्या कभी ऐसा भी होगा, जब टॉप रैंकिंग में इन नई नवेली टीमों को भी जगह मिलेगी? इसके पीछे की असल वजह क्या है, इस पर जानकारों की अलग-अलग राय हो सकती है, लेकिन इतना तो तय है कि पिछले कई सालों से हम इस तरह की टीमों को सिर्फ़ लिस्ट भरने के तौर पर ही देखते आ रहे हैं और शायद आगे भी यही देखते रहेंगे. इसका मतलब तो यही हुआ कि दूसरे देशों की टीमों को कभी नया मुकाम हासिल ही नहीं होगा. अगर ऐसा है तो यह बहुत सारे देशों की प्रतिभाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा. हर बार कोई कमज़ोर सी टीम दिग्गज को पटक देती है और फिर पूरे वर्ल्डकप का समीकरण ही बदल जाता है. आयरलैंड ने इंग्लैंड को हराकर ऐसा ही किया है. हालांकि आयरलैंड की जीत के पीछे इंग्लैंड की दिशाहीन गेंदबाजी और घटिया क्षेत्ररक्षण की भी अहम भूमिका रही. इंग्लिश टीम को अपनी इन ग़लतियों का ख़ामियाजा उलटफेर का शिकार होकर भुगतना पड़ा. इसके बावजूद आयरलैंड की मेहनत कम नहीं हो जाती.

पिछले विश्वकप में भी पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी टीमों को उलटफेर का शिकार बनाकर सनसनी फैलाने वाले आयरलैंड का नाम बीच में किसी प्रतिस्पर्धा में नहीं सुना गया. आयरलैंड के अलावा और भी कई टीमें हैं, मसलन हॉलैंड, कनाडा और नीदरलैंड, जो किसी भी मैच में खेल का रुख़ बदलने का माद्दा रखती हैं. बांग्लादेश का पूरा करियर ही उलटफेर की कहानी पर टिका हुआ है. इतने सालों के दौरान बांग्लादेश का नाम कभी भी टॉप रैंकिंग में नहीं आया. इस बार बांग्लादेश पहली बार वर्ल्डकप की मेजबानी कर रहा है. बांग्लादेश ने यह तो दिखा दिया कि अब वह भी ऐसे आयोजनों की मेजबानी करने में सक्षम है, लेकिन क्या वह आगे होने वाले मैचों में यह दिखा पाएगा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उसका प्रदर्शन विश्वसनीय है. बांग्लादेश के लिए सबसे अच्छा वर्ल्डकप 2007 का था, जहां उसने पहले चरण में भारत को हराकर सुपर आठ में प्रवेश किया. सुपर आठ में भी उसने दक्षिण अफ्रीका को हराया. हालांकि इसके बाद वह सभी मैच हार गया, लेकिन इन दो ज़बरदस्त उलटफेरों ने उसे अचानक लाइम लाइट में ला दिया. उसके बाद से यह टीम आज तक छोटे-मोटे उलटफेरों के दम पर ही टिकी हुई है. इसने कभी भी यह साबित नहीं किया कि यह ए लिस्ट की रैंकिंग में शामिल होने लायक है.

पिछले दो सालों में बांग्लादेश की टीम में बहुत परिवर्तन आया है. जहां उसने विदेशी धरती पर जाकर अच्छा प्रदर्शन किया है, वहीं घरेलू पिच पर भी बांग्लादेश ने पहले न्यूज़ीलैंड और फिर ज़िम्बाब्वे को एक दिवसीय सीरीज़ में हराया. अतः हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश कुछ भी करने में सक्षम है. भारत के अलावा पाकिस्तान भी इस तरह के उलटफेरों का शिकार हो चुका है. याद कीजिए 1999 का वर्ल्डकप, बांग्लादेश ने क्रिकेट वर्ल्डकप में पहली बार भाग लिया था. उस बार उसने लीग मैच में उलटफेर करते हुए पाकिस्तान को हराया था, लेकिन दूसरे मैचों में उसका प्रदर्शन ख़राब रहा. अतः उसे पहले दौर में ही बाहर होना पड़ा. ऐसा कोई नियम नहीं है कि इस तरह के उलटफेर करने वाली टीमें ए ग्रेड में नहीं आ सकती हैं. याद कीजिए 1983 का वर्ल्डकप, भारतीय टीम बेहद कमज़ोर मानी जाती थी. फिर भी किसी तरह वह वर्ल्डकप के फाइनल तक पहुंच गई. कुछ ने इसे तुक्का तो कुछ ने तक़दीर का खेल बताया. फाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम मात्र 183 रनों पर आउट हो गई. ज़्यादातर लोगों ने यह पक्का कर दिया कि यहां से भारत सिर्फ़ उपविजेता ही बन सकता है, लेकिन बाद में मोहिंदर अमरनाथ की जादुई गेंदबाजी और कपिलदेव के करिश्माई कैच ने भारत को विश्व चैंपियन बना दिया. निश्चित तौर पर यह वर्ल्डकप का अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर है. इसके दम पर चैंपियन बनने वाली उस वक़्त की कमज़ोर भारतीय टीम आज नंबर वन की पोजीशन में है. इससे यह तो साबित होता है कि पहली बार खेलना इस बात का ठप्पा नहीं हैं कि आप आगे भी न खेल पाओ. इसके अलावा कुछ और बड़े उलटफेरों पर ग़ौर फरमाइए. 2007 में आयरलैंड बनाम पाकिस्तान का मैच. भला उस मैच को कोई कैसे भूल सकता है. पिछले वर्ल्डकप में पाकिस्तान की टीम आयरलैंड की कमज़ोर टीम के सामने 132 रनों पर ऑल आउट हो गई थी. इसके बाद ख़ुद आयरलैंड के सात विकेट 113 रनों पर गिर गए. उसी दौरान ट्रेंट जॉनटन ने छक्का मारकर अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दी. उस रात पाकिस्तान के कोच बॉब वूल्मर को दिल का ऐसा दौरा पड़ा कि वह कभी उठ नहीं पाए. पाकिस्तान वर्ल्डकप से बाहर हो गया. पिछले वर्ल्डकप में अगर आयरलैंड ने पाकिस्तान को बाहर किया तो पिद्दी समझे जाने वाले बांग्लादेश ने भारत को. टीम इंडिया ने 191 रनों का कमज़ोर स्कोर बनाया, जिसे बांग्लादेश की टीम ने आसानी से पार कर लिया. इसी हार के बाद भारत को बाहर जाना पड़ा. इसी तरह 1983 में एक तरफ बॉर्डर, मार्श लिली और थॉमसन जैसे क्रिकेटरों से सजी ऑस्ट्रेलिया की टीम थी तो दूसरी तरफ़ क्रिकेट की दुनिया में पहला क़दम रख रही जिम्बाब्वे. पर डंकन फ्लेचर की जादुई पारी के साथ जिम्बाब्वे ने 239 रन बना डाले, नतीजतन आस्ट्रेलिया हार गया. 2003 के वर्ल्डकप में केन्या ने भारतीय क्रिकेटर संदीप पाटिल की कोचिंग में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और विश्व विजेता रह चुकी श्रीलंका की टीम को परास्त करते हुए सेमी फाइनल तक जगह बना ली.

हालांकि विशेषज्ञ कुछ और कारणों का ज़िक्र करते हैं. उनका मानना है कि इस तरह की टीमें उलटफेर कुछ ख़ास कारणों से कर पाती हैं. मसलन वर्ल्डकप में बांग्लादेश के पास सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह मैच अपने घर में खेल रहा है. अपनी पिचों और 35,000 लोगों के बीच किसी भी टीम का हौसला बढ़ सकता है. ऐसे में वह कोई बड़ा चमत्कार करे तो कोई आश्चर्य नहीं. इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि इस तरह की टीमों के पास खोने के लिए कुछ ख़ास नहीं होता. ऐसे में उन पर जीतने का कोई ख़ास दबाव नहीं होता है और उस दबाव मुक्त माहौल में वे बेहतरीन प्रदर्शन कर जाती हैं. फिर भी यह यक्ष प्रश्न तो अभी भी क़ायम है कि आख़िर इन टीमों का अस्तित्व वर्ल्डकप से कभी बाहर निकलेगा या फिर ये सिर्फ ग्रुप लिस्ट बढ़ाती ही नज़र आएंगी.

rajeshsy@chauthiduniya.com

Now, mixing business with pleasure makes perfect business sense.

FORTUNE Inn Grazia BY WELCOMGROUP Noida

Welcome to Fortune Inn Grazia, Noida - an elegant, upscale, full-service business hotel. It is strategically located in the heart of the city and in close proximity to Sector 18, the commercial and shopping hub of Noida. The hotel offers everything from contemporary accommodation and exciting dining options to, of course, comprehensive facilities for business and leisure. All to meet the growing needs of the new-age business traveller.

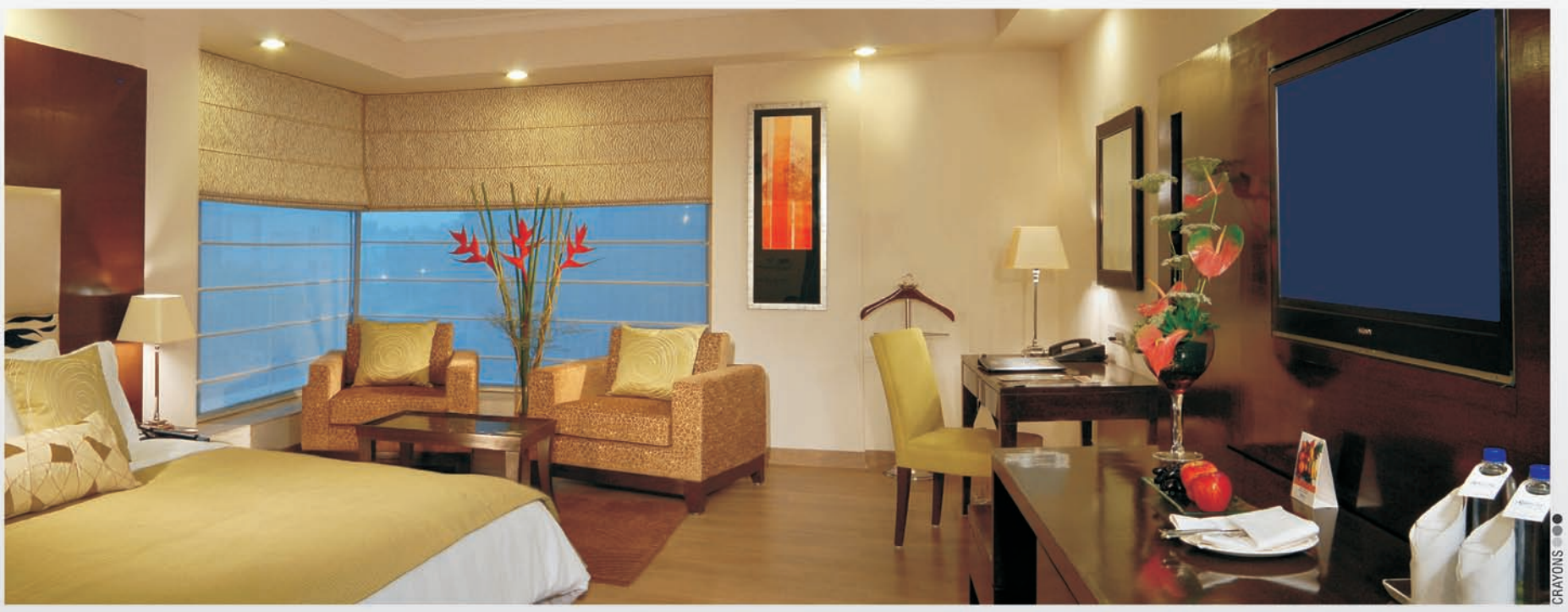

Block-I, Plot No. 1A, Sector-27, Noida - 201301, Uttar Pradesh, India. Tel: 0120-3988444, Fax: 0120-3380144, E-mail: grazia@fortunehotels.in, Website: www.fortunehotels.in

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 14 मार्च–20 मार्च 2011

निर्माता समझ चुके हैं कि अगर उनकी फिल्म लगातार दो हफ्तों तक सिनेमाघरों में हाउसफुल जैसी स्थिति में बनी रही तो निर्माण की लागत तो निकल ही आएगी.

बॉलीवुड

सब कुछ बदल गया है

एक वक़्त था, जब हिंदी फिल्मों के निर्माता-निर्देशक ही मीडिया से बातचीत करते थे और फिल्में बढ़िया कारोबार कर जाती थीं. फिल्म के प्रोमोशन का ख़र्च निर्माण का एक-दो फ़ीसदी हुआ करता था और उसकी मार्केटिंग केवल इतनी होती थी, जितनी चर्चाएं हुआ करती थीं, लेकिन मल्टीप्लेक्स का जमाना आया और सब कुछ बदल गया. निर्देशकों को यह समझने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगा कि निर्माण की लागत फिल्म रिलीज होने के दो हफ्ते के अंदर वसूली जा सकती है. इसके बाद ही फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्सेप्ट आया और खेल की रणनीति ही बदल गई. आज बॉलीवुड का बिजनेस चलता है झूठे वादों, ग़लत आंकड़ों और हाई-फाई प्रोमोशन पर.

निर्माता समझ चुके हैं कि अगर उनकी फिल्म लगातार दो हफ्तों तक सिनेमाघरों में हाउसफुल जैसी स्थिति में बनी रही तो निर्माण की लागत तो निकल ही आएगी. इसके लिए निर्माता-निर्देशक जो कर सकते हैं, वह कर लेते हैं, चाहे इसके लिए किसी भी तरह के हथकंडे अपनाने पड़ें. यहां तक कि ख़राब प्रतिक्रिया मिलने के बावजूद फिल्मकार अपनी फिल्म को अच्छा बताते रहते हैं और मीडिया के ज़रिए लोगों में फिल्म का क्रेज़ बनाए रखते हैं. वे फिल्म की कमाई बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं. आजकल फिल्में अपने जनरल रीव्यू से नहीं, बल्कि वे बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर पाईं, इससे जानी जाती हैं. सिर्फ़ इतना ही नहीं, फिल्मकार अपनी फिल्म के फ्लॉप होने की ख़बर का खंडन भी करते हैं. आजकल फिल्म से पैसा बनाना बहुत आसान हो चुका है. मल्टीप्लेक्स पर रिलीज होने और ओवरसीज रिलीज होने की वजह से दो हफ्तों में ही फिल्म की निर्माण लागत वसूल कर ली जाती है. हालांकि इससे डिस्ट्रीब्यूटरों को नुक़सान पहुंचता है.

प्रोड्यूसर अपनी फिल्म को लाने से पहले इतना ज़्यादा बवंडर फैला देते हैं कि रिलीज तक उसकी प्रिंट कॉस्ट 50 से 70 फ़ीसदी बढ़ जाती है और फिर वे उसे डिस्ट्रीब्यूटरों को बेचते हैं. जब फिल्म थिएटर में लगती है, तभी उसके सफल और असफल होने का पता चल पाता है और डिस्ट्रीब्यूटर भी यह समझ पाते हैं कि वे इस फिल्म से पैसे कमा पाएंगे या नहीं, लेकिन तब तक वे इस फिल्म के प्रिंट मोटी क़ीमत पर ख़रीद चुके होते हैं. ऐसी स्थिति में या तो दर्शक या फिर डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ धोखा होता है. एक बार धोखे के बाद एकाध साल में दोबारा इसी समीकरण पर फिल्म रिलीज की तैयारी हो जाती है. एक नए टाइटल के साथ नए पैकेट में उसी पुरानी चॉकलेट की मार्केटिंग के लिए ग्राउंड तैयार हो जाता है. डिस्ट्रीब्यूटर, जो फिल्म को सिनेमाघरों तक पहुंचाते हैं, लगातार नुक़सान के थपेड़े झेलते रहते हैं, लेकिन बॉलीवुड के बड़े निर्माता-निर्देशकों को इस बात की ज़रा भी फ़िक्र नहीं है और न इंडस्ट्री से सरोकार रखने वाले बुद्धिजीवियों को.

डिस्ट्रीब्यूटरों को इन फिल्मों के ऑफिसियल प्रोमो के अलावा कुछ नहीं बताया जाता कि वे जो फ़िल्म ख़रीद रहे हैं, वह कैसी है, उसमें किस तरह का कंटेंट है, स्टोरी लाइन क्या है और सबसे ज़रूरी यह कि प्रेजेंटेशन आइडिया किस तरह का है. जबकि डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए प्री-स्क्रीनिंग का इंतज़ाम होना चाहिए, तभी फिल्मों के कारोबार में व्याप्त राजनीति और धोखाधड़ी का खेल ख़त्म हो पाएगा.

रीतिका सोनाली
ritika@chauthiduniya.com

प्रीव्यू

गेम

एक्सेल इंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी गेम एक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन किया है अभिनव देव ने और निर्माता हैं फरहान अख्तर एवं रितेश सिधवानी. मुख्य कलाकार हैं अभिषेक बच्चन, सराह जेन डियास, कंगना रानावत, शहाना गोस्वामी, बोमन ईरानी, गौहर खान एवं जिम्मी शेरगिल. इस फिल्म में महिला लीड किरदार के लिए पहले ऐश्वर्या राय का नाम तय किया गया था, लेकिन फिर बाद में उन्हें शूटिंग के लिए डेट्स और शेड्यूलिंग की वजह से आने वाली समस्याओं को देखते हुए एक नए चेहरे को फिल्म में लीड रोल के लिए लिया गया. मुख्य किरदार के अलावा दो और हीरोइनों को फिल्म में लिया गया. फिल्म का नाम पहले क्रुक्ड रखा गया था, लेकिन निर्माता-निर्देशकों को ज़्यादा पसंद न आने की वजह से इसे बाद में बदल कर गेम कर दिया गया. इसके प्रोडक्शन में काफी विलंब हुआ. वजह, निर्देशक अभिनव देव अपनी कुछ निजी परेशानियों के चलते फिल्म पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे. अभिनव फिल्म निर्माण के क्षेत्र में आने से पहले एड फिल्म मेकर थे. फिल्म गेम एक स्टाइलिश एक्शन थ्रिलर है, जिसकी शूटिंग मुंबई, ग्रीस, इस्तानबुल, लंदन, टर्की एवं थाईलैंड में की गई है.

माना जाता है कि फिल्म बोर्न आइडेंटिटी ट्राइलॉजी पर बनी है. संगीत दिया है शंकर-एहसान-लॉय ने और डायलॉग ख़ुद फरहान अख्तर ने लिखे हैं. इंडस्ट्री के बेहतरीन संगीतकारों में से एक इस तिगड़ी ने जब मेहनत की है, तो ज़ाहिर है कि फिल्म का संगीत काफी ज़ोरदार होगा. सात गानों वाली इस फिल्म में म्यूज़िक के सभी फ्लेवर दिए गए हैं. यह फिल्म 18 मार्च को रिलीज हो रही है. कंगना रानावत फिल्म गेम में अपनी हालिया रिलीज फिल्म तनु वेड्स मनु के किरदार से बिल्कुल अलग अंदाज़ में नज़र आएंगी. फिल्म थ्रिलर एक्शन जॉनर की है तो ज़ाहिर है कि इसमें कैरेक्टर्स का स्लाइटली डार्क और स्लाइटली लाइट शेड ज़रूर होगा. बहरहाल, फिल्म किरदारों को लेकर एक्सपेरीमेंटल मोड में बनी नज़र आती है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

असिन का बिकनी अवतार

साउथ सेनसेशन असिन ने इंडस्ट्री में धमाकेदार एंट्री की मिस्ट परफेक्शनिस्ट आमिर ख़ान की फिल्म गजनी से. अब उन्हें ज़रूरत है एक बड़े हिट की. वैसे गजनी के बाद उनका क्या हश्र हुआ बॉलीवुड में, यह तो सभी जानते हैं, लेकिन अब असिन फ़ैसला कर रही हैं सोच-समझ कर. वह सिर्फ़ स्टार ही नहीं, फिल्म की पूरी टीम देखकर ले रही हैं फ़ैसला. गजनी के बाद उन्होंने सलमान ख़ान के साथ लंदन ड्रीम्स में काम किया. इसके बाद वह सलमान के साथ अनीस बज़्मी की फिल्म रेडी में भी नज़र आएंगी. ख़बरें आ रही थीं कि इस फिल्म में असिन और सलमान के कुछ गर्मागर्म सीन डाले गए हैं, लेकिन बाद में फिल्म के निर्देशक अनीस और ख़ुद सलमान एवं असिन ने इन ख़बरों का खंडन कर दिया. बहरहाल हॉट न्यूज़ यह है कि असिन ने बड़े बैनरों और बड़े स्टारों के साथ काम करने के बाद अब अपना काम करने का अंदाज़ ही बदल लिया है. जल्द ही आने वाली अपनी फिल्म में वह एक नए अवतार में नज़र आएंगी.

दरअसल हाउसफुल का सिक्वल बना रहे साजिद नाडियाडवाला की आने वाली फिल्म हाउसफुल-2 में वह स्किन शो करती नज़र आएंगी. पहले वाली हाउसफुल में जहां जिया ख़ान ने बिकनी अवतार को फॉलो किया था, वहीं इस बार हाउसफुल के सिक्वल में असिन बिकनी बेब बनी नज़र आएंगी. फिल्म की टीम इस बात से काफी संतुष्ट है कि असिन का यह रूप दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब रहेगा. इस फिल्म में हॉट लुक के साथ असिन ही नहीं, जॉन भी नज़र आएंगे.

दीया का नया प्रोजेक्ट

दीया मिर्ज़ा का एक्टिंग करियर भले ही बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन अपने सबसे अच्छे दोस्त ज़ायद ख़ान के साथ प्रोडक्शन हाउस खोलकर उन्होंने एक नई पारी का आगाज़ किया है. वैसे ख़बरें तो प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म के डायरेक्टर साहिल के साथ उनके लिंकअप की भी आ रही हैं. प्रोडक्शन हाउस खोलने का ख्याल आया कैसे? इस सवाल के जवाब में दीया कहती हैं, जब मैं इंडस्ट्री में नई-नई आई थी, तब मुझे भी किसी ने चांस दिया था और अब लगता है कि मुझे भी नए लोगों को मौक़ा देना चाहिए.

दीया जो फिल्म बना रही हैं, उसकी स्क्रिप्ट उनके दिल के बेहद क़रीब है और उन्हें ज़ायद एवं साहिल जैसे लोगों का साथ भी मिल गया. इन्हीं तमाम बातों से उन्हें अपना प्रोडक्शन हाउस खोलने की प्रेरणा मिली. ज़ायद ख़ान से दोस्ती वाले रिश्ते को बहुत दिल से अपनाती हैं दीया. वह कहती हैं, ज़ायद मेरा बहुत प्यारा दोस्त है. हमारी दोस्ती शुरू से ही बहुत अच्छी रही. मैं उसकी शादी में परिवार के सदस्य की तरह शामिल रही. फंक्शन में सभी दोस्तों को कॉर्डिनेट करना और मैनेजमेंट से जुड़े रहना जैसे काम मैंने दिल से किए. तबसे हमारे रिश्ते बहुत ख़ूबसूरत और मज़बूत हो गए, जो आज तक क़ायम हैं. मलाइका एवं ज़ायद, दोनों के ही मैं बहुत क़रीब हूं. उनकी शादी के बाद की जर्नी में भी मैं शामिल रही. मलाइका जब मां बनने वाली थी, तब भी मैंने दोनों की ख़ुशियां शेयर कीं. मलाइका मेरी बहन की तरह है और ज़ायद मेरा सबसे अच्छा दोस्त. दीया की अरशद वारसी के साथ भी कुछ ऐसी ही दोस्ती है, उन्होंने उनके साथ पार्टनरशिप क्यों नहीं की? इस सवाल पर वह कहती हैं, यह सच है कि अरशद भी मेरे उतने ही अच्छे दोस्त हैं. भले ही उनके साथ पार्टनरशिप नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन हाउस खोलने के लिए उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित किया, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है. एक्टिंग करियर सफल न रहने के बाद अपनी नई पारी से क्या उम्मीद करती हैं दीया? इस सवाल के जवाब में वह कहती हैं, मैंने जब भी, जो भी करना चाहा, किया. मैं एक फाइटर हूं और यह बात अच्छी तरह जानती हूं कि अपने लिए फ़ैसले हम ख़ुद ही बेहतर तरीक़े से ले सकते हैं. मैं जो भी काम कर रही हूं, उस पर मुझे पूरा यक़ीन है. मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं डायरेक्टर बनूं. जब कोई सही स्क्रिप्ट हाथ में आएगी तो मैं यह सपना भी पूरा करूंगी.

मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं डायरेक्टर बनूं. जब कोई सही स्क्रिप्ट हाथ में आएगी तो मैं यह सपना भी पूरा करूंगी.

चौथी दुनिया

उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड

दिल्ली, 14 मार्च –20 मार्च 2011

www.chauthiduniya.com

फोटो– *प्रभात पाण्डेय*

प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त बनाने की कवायद

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र मुख्यमंत्री मायावती ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है. इसी के तहत उन्होंने प्रदेश में स्थिति का जायज़ा लेने के लिए दौरे करने का अभियान शुरू किया. हालांकि औपचारिक तौर पर इन दौरों का मक़सद विकास कार्यों की समीक्षा और क़ानून व्यवस्था की स्थिति देखना बताया गया.

डॉ. सुनील कौशिक

आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र मुख्यमंत्री मायावती प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त बनाने में जुट गई हैं. उन्होंने अपने दौरे के दौरान लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के ख़िलाफ़ सख्त रवैया अपनाते हुए पिछले माह जहां 79 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए, वहीं कई को निलंबित भी किया. इसके अलावा कार्य में कोताही बरतने वाले आईपीएस अफ़सरों व अन्य अधिकारियों पर भी सीएम की गाज गिरी. मुख्यमंत्री का यह अभियान 2 फ़रवरी से 2 मार्च तक चला. इसमें उन्होंने 72 ज़िलों 81 अंबेडकर ग्रामों, 80 मलिन बस्तियों, 88 अस्पतालों, 148 तहसीलों, 148 थानों तथा प्रत्येक जनपद में निर्मित कांशीराम शहरी ग़रीब आवास योजना के आवासों का निरीक्षण किया. उनके दौरे अप्रत्यक्ष रूप से 2012 में होने वाले प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र सोची-समझी रणनीति के तहत ही आयोजित किए गए थे. प्रत्यक्ष में इन दौरों का उद्देश्य विकास कार्यों की समीक्षा करना और क़ानून व्यवस्था की स्थिति को देखना था. अपने दौरे में मुख्यमंत्री को प्रदेश के हर ज़िले में विकास कार्यों में शिथिलता, लापरवाही और लचर क़ानून व्यवस्था देखने को मिली. इससे उन्हें मालूम हो गया कि अधिकारी उनके आदेशों को इस कान से सुनकर उस कान से निकाल रहे हैं. इस दौरान जो तस्वीर उभर कर सामने आई उसने मायावती को भयभीत कर दिया है. अपने दौरों के संबंध में मायावती ने जनवरी माह में ही प्रचारित करा दिया था कि वे फ़रवरी में प्रदेश के सभी ज़िलों में आकस्मिक दौरे करेंगी, लेकिन उनके विश्वसनीय लोगों ने उन्हें सलाह दी कि वे आकस्मिक दौरे न करके योजनाबद्ध दौरे करें, क्योंकि आकस्मिक दौरों में प्रदेश में सबकुछ गड़बड़ मिलेगा. अत: मुख्यमंत्री ने सभी ज़िलों के लिए तारीख़ और दिन निश्चित कर दिए. हर ज़िले में यह भी सूचना भिजवा दी कि वे अपने दौरे में किन-किन विभागों और योजनाओं का निरीक्षण करेंगी. उन्होंने ज़िला प्रशासन को यह संदेश भी भिजवा दिया कि इस दौरान विकास कार्यों के निरीक्षण में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर स्थानीय अधिकारियों के साथ शासन के संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को भी ज़िम्मेदार मानते हुए उन पर कार्रवाई की जाएगी. किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी.

मुख्यमंत्री मायावती को अपने दौरे के दौरान लगभग सभी ज़िलों में भारी अनियमितताएं देखने को मिलीं. हालांकि वे पहले ही निरीक्षण की तारीख़ तक तय कर चुकी थीं. इसके बावजूद अधिकारियों ने गंभीरता नहीं दिखाई. मायावती को लगा कि अधिकारियों ने उनके वोटों के समीकरण को बिगाड़ने का पूरा इंतज़ाम कर रखा है.

पूरे प्रदेश के दौरे में मायावती को मात्र बलरामपुर की नगर कोतवाली के सीओ तथा थानाध्यक्ष, छत्रपति शाहूजीमहाराज नगर के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, बिजनौर के जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के मंडलायुक्त व जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी व ग़ाज़ियाबाद के जिलाधिकारी व फ़ैज़ाबाद सदर तहसील के तहसीलदार, जिलाधिकारी बदायूं तथा जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर के ही कार्य संतोषजनक मिले. प्रदेश के बाक़ी ज़िलों के अफ़सरों ने उन्हें बहुत निराश किया. हर जगह अनियमितता और घोर लापरवाही पाई गई. मायावती को लगा कि अधिकारियों ने उनके वोटों के समीकरण को गड़बड़ा देने के पूरे इंतज़ाम कर रखे हैं. मुख्यमंत्री ने जनवरी में ही शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित रूप से स्पष्ट कर दिया था कि 28 फ़रवरी के बाद किसी भी विभाग को अतिरिक्त धनराशि किसी भी दशा में रिलीज़ न की जाए. इसके साथ ही उन्होंने ये निर्देश भी जारी किए थे कि शासन के वरिष्ठ अधिकारी ज़िलों में जाकर महामाया ग़रीब आर्थिक मदद योजना के लाभार्थियों का सत्यापन, राज्य के 1126 अपर प्राइमरी स्कूलों का निर्माण, प्रदेश के 90 नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए चिकित्सकों तथा अन्य स्टाफ़ की व्यवस्था, दक्षता विकास कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन, तहसील एवं जनपद स्तर पर विभागों के ख़ाली पदों अतिशीघ्र पूर्ति, मिड-डे मील योजना का गुणवत्तापूर्वक संचालन, महामाया सचल अस्पताल योजना का पूरी ईमानदारी से संचालन सुनिश्चित कराएं. मुख्यमंत्री मायावती ने अपने दौरों में पाया कि शासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने ही उनके आदेशों को गंभीरता से नहीं लिया था. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी, अनेक अधिकारियों को निलंबित किया और कई का स्थानांतरण किया गया. 2 फ़रवरी को आगरा ज़िला अस्पताल की व्यवस्था में सुधार के लिए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को उन्होंने चेतावनी देकर कहा कि यदि दो माह के अंदर व्यवस्था में सुधार नहीं आया तो उनके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 5 फ़रवरी को महामाया नगर जनपद में डॉ. अंबेडकर पार्क पर भू-माफ़िया द्वारा क़ब्ज़ा किए जाने के मामले में प्रभावी कार्रवाई न करने पर उन्होंने एसडीएम और तहसीलदार सिकंदराराऊ को निलंबित और महामायानगर के मुख्य विकास अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा थानाध्यक्ष सिकंदराराऊ को स्थानांतरित करने के निर्देश दिए. मथुरा में ज़िला अस्पताल में गंदगी और बिस्तर ख़ाली पाए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को कड़ी चेतावनी दी. 6 फ़रवरी को मैनपुरी के ज़िला अस्पताल में सफ़ाई व्यवस्था में कमी एवं कम मरीज़ों की संख्या पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई. मैनपुरी सदर तहसील के उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा तहसील दिवस में आए प्रार्थना-पत्रों के उचित रखरखाव एवं ठोस कार्रवाई न करने पर एक माह में सुधारने की चेतावनी दी. मैनपुरी के जिलाधिकारी का पर्यवेक्षण में ढील बरतने पर तत्काल स्थानांतरण कर दिया. मैनपुरी ज़िला अस्पताल के अस्थि रोग विशेषज्ञ को रोगियों से धनवसूली करने के आरोप में तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए. बीएड. कॉलेजों में अवैध वसूली की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उच्च

(शेष पृष्ठ 18 पर)

आईएएस अफ़सरों के तबादले

क्र.सं.	अधिकारी का नाम/पदनाम	नवीन तैनाती
1.	संजीव कुमार, आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी योजना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, स्थानांतरणाधीन, मंडलायुक्त, बरेली	मंडलायुक्त, बरेली के पद पर तैनाती संबंधी आदेश को निरस्त करते हुए, आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पद पर यथावत बनाए रखना
2.	सुधीर महादेव बोबड़े, मंडलायुक्त, आगरा	मंडलायुक्त, बरेली
3.	अमृत अभिजात, जिलाधिकारी, आगरा	मंडलायुक्त, आगरा
4.	ज्ञान सिंह, विशेष सचिव, गृह विभाग	जिलाधिकारी, कुशीनगर
5.	प्रांजल यादव, मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ	विशेष सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग
6.	प्रभु नारायण सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, बांदा	मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ
7.	सारिका मोहन, मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर	विशेष सचिव, नियुक्ति विभाग
8.	शीतल वर्मा, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, आगरा	मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर
9.	सेल्वा कुमारी जे., मुख्य विकास अधिकारी, झांसी	विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग
10.	मुथुकुमारस्वामी बी., ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, कानपुरनगर	मुख्य विकास अधिकारी, झांसी
11.	सुहास एल.वाई., ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, आजमगढ़	मुख्य विकास अधिकारी, मथुरा
12.	नवीन कुमार जी.एस., ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, गोरखपुर	मुख्य विकास अधिकारी, इलाहाबाद
13.	चैत्रा वी., ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़	मुख्य विकास अधिकारी, हरदोई
14.	संजीव कुमार मित्तल, प्रतीक्षारत	मंडलायुक्त, मिर्ज़ापुर
15.	अनिल कुमार-II, मंडलायुक्त, बस्ती	सदस्य (न्यायिक), राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
16.	राकेश कुमार गोयल, सचिव एवं प्रमुख स्टाफ ऑफ़िसर मुख्य सचिव	मंडलायुक्त, बस्ती
17.	अजय चौहान, जिलाधिकारी, शाहजहांपुर	जिलाधिकारी, आगरा
18.	नवदीप रिनवा, विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं अपर निदेशक, एस.जी.पी.जी.आई., उ.प्र., लखनऊ	जिलाधिकारी, शाहजहांपुर
19.	प्रदीप शुक्ला, प्रमुख सचिव, परिवार कल्याण विभाग	वर्तमान पद के साथ प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद का अतिरिक्त प्रभार
20.	बी.एस. भुल्लर, सचिव, वित्त विभाग	प्रमुख सचिव-II, वित्त विभाग
21.	उमेश सिन्हा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ.प्र. एवं सचिव, निर्वाचन विभाग	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश एवं प्रमुख सचिव, निर्वाचन विभाग
22.	प्रभात कुमार सारंगी, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं परियोजना निदेशक, यू.पी. हेल्थ सिस्टम डेवेलपमेंट परियोजना, लखनऊ	प्रमुख सचिव, अल्प संख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक़्फ़ विभाग
23.	डॉ. हरशरण दास, सचिव, पशुधन एवं मत्स्य विभाग	प्रमुख सचिव, पशुधन एवं मत्स्य विभाग
24.	सच्चिदानंद दुबे, जिलाधिकारी, मैनपुरी	विशेष सचिव, लघु उद्योग विभाग
25.	रणवीर प्रसाद, विशेष सचिव, लघु उद्योग विभाग	जिलाधिकारी, मैनपुरी
26.	अमित कुमार घोष, मंडलायुक्त, कानपुर	प्रतीक्षारत
27.	मनोज कुमार, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
28.	अवनीश कुमार अवस्थी, सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, महानिदेशक, पर्यटन एवं प्रबन्ध निदेशक, राज्य पर्यटन एवं प्रबंध निदेशक, राज्य पर्यटन विकास निगम, उ.प्र., लखनऊ	वर्तमान पद के साथ सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के पद का अतिरिक्त प्रभार
29.	पी. के. महांति, मंडलायुक्त, गोरखपुर	मंडलायुक्त, कानपुर
30.	के. रविन्द्र नायक, जिलाधिकारी, अलीगढ़	मंडलायुक्त, गोरखपुर
31.	अनिल कुमार-III, जिलाधिकारी, ज्योतिबाफुले नगर.	जिलाधिकारी, अलीगढ़
32.	एस. के. द्विवेदी, अपर आयुक्त, मनोरंजनकर, उ.प्र., लखनऊ	जिलाधिकारी, ज्योतिबाफुले नगर
33.	हिमांशु कुमार, महानिरीक्षक, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, उ.प्र., इलाहाबाद	सचिव, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग
34.	अमित कुमार घोष, प्रतीक्षारत	महानिरीक्षक, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, उ.प्र., इलाहाबाद
35.	पार्थ सारथीसेन शर्मा, प्रबंध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम, लखनऊ	आयुक्त, चकबंदी, उ. प्र., लखनऊ
36.	प्रांजल यादव, स्थानांतरणाधीन, विशेष सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग	प्रबंध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम, लखनऊ
37.	डॉ. गुरदीप सिंह, मंडलायुक्त, देवीपाटन	प्रतीक्षारत
38.	आर. रमेश कुमार, निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ. प्र., लखनऊ	मंडलायुक्त, देवीपाटन
39.	मधुकर द्विवेदी, जिलाधिकारी, गोंडा	प्रतीक्षारत
40.	नवतेज सिंह, प्रमुख सचिव, राष्ट्रीय एकीकरण एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	प्रमुख सचिव, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के पद के प्रभार से अवमुक्त किया गया एवं प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार के पद पर यथावत बनाए रखा गया
41.	डॉ. गुरदीप सिंह (प्रतीक्षारत)	प्रमुख सचिव राष्ट्रीय एकीकरण विभाग
42.	मधुकर द्विवेदी (प्रतीक्षारत)	विशेष सचिव बेसिक शिक्षा विभाग
43.	संतोष कुमार द्विवेदी, अपर आयुक्त, मनोरंजनकर, उ.प्र., स्थानांतरणाधीन, जिलाधिकारी, ज्योतिबाफुले नगर	जिलाधिकारी, ज्योतिबाफुले नगर के पद का स्थानांतरण निरस्त करते हुए अपर आयुक्त, मनोरंजनकर, उ.प्र., लखनऊ के पद पर यथावत रखा गया
44.	एस. वी. एस. रंगाराव (प्रतीक्षारत)	विशेष सचिव खाद्य एवं रसद विभाग
45.	राम बहादुर, उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा	जिलाधिकारी, गोंडा
46.	प्रभात कुमार सारंगी, प्रमख सचिव, अल्प संख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक़्फ़ विभाग	वर्तमान पद के साथ प्रमुख सचिव-II, परिवार कल्याण विभाग के पद का अतिरिक्त प्रभार
47.	हिमांशु कुमार, सचिव, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	सचिव एवं प्रमुख स्टाफ ऑफ़िसर मुख्य सचिव, उ.प्र.
48.	राज शेखर, जिलाधिकारी, झांसी	विशेष सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग
49.	मनीष चौहान, विशेष सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	जिलाधिकारी, झांसी
50.	लोकेश एम., जिलाधिकारी, कौशाम्बी	जिलाधिकारी, ज्योतिबाफुले नगर
51.	अतुल कुमार, विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग	जिलाधिकारी, कौशाम्बी
52.	एस. वी. एस. रंगराव, प्रतीक्षारत, स्थानांतरणाधीन, विशेष सचिव, खाद्य एवं रसद	विशेष सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग के पद पर किया गया स्थानांतरण निरस्त कर विशेष सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पद पर तैनात गया.
53.	डॉ. पी. वी. जगनमोहन, मंडलायुक्त, इलाहाबाद	सचिव, नगर विकास विभाग
54.	मुकेश कुमार मेश्राम, जिलाधिकारी, कानपुर (नगर)	मंडलायुक्त, इलाहाबाद
55.	डॉ. हरिओम, निदेशक, खेलकूद, उ.प्र., लखनऊ	जिलाधिकारी, कानपुर (नगर)
56.	कुमार अरविंद सिंह देव, प्रमुख सचिव, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग	वर्तमान पद के साथ निदेशक, खेलकूद, उ.प्र., लखनऊ के पद का अतिरिक्त प्रभार
57.	देश दीपक वर्मा, प्रतीक्षारत	सदस्य, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
58.	रिज्जियान सैम्फिल, जिलाधिकारी, बहराइच	जिलाधिकारी, फ़र्रूख़ाबाद
59.	गोविन्द राजू एन. एस., जिलाधिकारी, कन्नौज	जिलाधिकारी, बइराइच
60.	सारिका मोहन, विशेष सचिव, नियुक्ति विभाग	जिलाधिकारी, कन्नौज
61.	एस. मिनिष्ठी, जिलाधिकारी, फ़र्रूख़ाबाद	विशेष सचिव, नियुक्ति विभाग
62.	संतोष कुमार यादव, जिलाधिकारी, मुज़फ़्फ़रनगर	प्रतीक्षारत
63.	पंकज कुमार, प्रबंध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि., वाराणसी	जिलाधिकारी, मुज़फ़्फ़रनगर
64.	राजीव अग्रवाल, मंडलायुक्त, अलीगढ़	प्रतीक्षारत
65.	अनुराग श्रीवास्तव, मंडलायुक्त, मेरठ	मंडलायुक्त, अलीगढ़
66.	भुवनेश कुमार, जिलाधिकारी, मेरठ	मंडलायुक्त, मेरठ
67.	सुभाष चन्द्र शर्मा, जिलाधिकारी, मुरादाबाद	जिलाधिकारी, मेरठ
68.	राजशेखर, विशेष सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग	जिलाधिकारी, मुरादाबाद
69.	सैंथिल पांडियन सी., जिलाधिकारी, बलिया	विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग
70.	मधुकर द्विवेदी, विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग	जिलाधिकारी, बलिया
71.	संतोष कुमार यादव, प्रतीक्षारत	निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ.प्र., लखनऊ
72.	मृत्युन्जय कुमार नारायण, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण	सचिव, लोक निर्माण विभाग
73.	राजीव अग्रवाल, प्रतीक्षारत	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण
74.	राधाकृष्ण सिंह, जिलाधिकारी, कांशीराम नगर	विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं अपर निदेशक, एस.जी.पी.जी.आई., लखनऊ
75.	सेल्वा कुमारी जे., विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग	जिलाधिकारी, कांशीराम नगर
76.	दिनेश चन्द्र शुक्ला, जिलाधिकारी, फ़िरोज़ाबाद	विशेष सचिव, ग्राम्य विकास विभाग
77.	सुरेन्द्र सिंह, जिलाधिकारी, बलरामपुर	जिलाधिकारी, फ़िरोज़ाबाद
78.	प्रज्ञान राम मिश्रा, विशेष सचिव, ग्राम्य विकास विभाग	जिलाधिकारी, बलरामपुर
79.	योगेंद्र कुमार बहल, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ताज एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर	जिलाधिकारी, महामायानगर

चौथी दुनिया

उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपराधियों पर अंकुश लगाए या मायावती सरकार में शामिल लोगों को आरोपों से बचाए.

टंकी से आसपास के गांवों को तो पानी पहुंचने लगा, लेकिन दूर-दराज के गांवों में साफ़ पानी की समस्या बनी रही.

चौथी दुनिया

प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त बनाने की कवायद

पृष्ठ 1 का शेष

शिक्षा विभाग को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए. 10 फ़रवरी को चंदौली के मुख्य विकास अधिकारी को विकास भवन में गंदगी और अंधेरा होने के कारण जल्दी ही स्थिति सुधारने की चेतावनी दी. 11 फ़रवरी को आयुक्त देवीपाटन मंडल एवं जिलाधिकारी गोंडा को जन समस्याओं के निस्तारण में शिथिलता बरतने पर तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करने के निर्देश दिए. महिलाओं के विरुद्ध हो रही आपराधिक घटनाओं को रोकने में असफल तथा अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण न रखने पर थानाध्यक्ष मनकापुर को निलंबित किया तथा सीओ को स्थानांतरित किया गया. श्रावस्ती जनपद के तहसील परिसर में गंदगी पाए जाने पर परगनाधिकारी को चेतावनी दी गई तथा तहसीलदार व अपर जिलाधिकारी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच जिलाधिकारी को सौंपी. श्रावस्ती जनपद के तहसील भिनगा में जन समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही के लिए एसडीएम को चेतावनी दी गई. 13 फ़रवरी को इलाहाबाद में मेजा के पुलिस क्षेत्राधिकारी का स्थानांतरण किया गया. फ़तेहपुर नगर परिषद के अधिशासी अधिकारी को कार्य में शिथिलता के लिए निलंबित किया. अपराध नियंत्रण में कमी पाए जाने पर थाना कोतवाली के थानाध्यक्ष को निलंबित किया. 15 फ़रवरी को ललितपुर में डॉ. अंबेडकर गांव में सी.सी रोड की जर्जर हालत के कारण लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता तथा अवर अभियंता को निलंबित किया. जिलाधिकारी झांसी को व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लापरवाही और पर्यवेक्षण में शिथिलता बरतने के कारण स्थानांतरित करने के निर्देश दिए. तहसील मऊरानीपुर के सीओ व थानाध्यक्ष को निलंबित किया. 18 फ़रवरी को पर्यवेक्षण के अभाव एवं अधीनस्थों पर प्रभावी नियंत्रण न रख पाने के कारण इलाहाबाद के मंडलायुक्त के स्थानांतरण के निर्देश दिए. जनपद रायबरेली की ऊंचाहार तहसील के उपजिलाधिकारी तथा तहसीलदार को प्रतिकूल प्रविष्टि देने तथा स्थानांतरित करने के निर्देश दिए. प्रतापगढ़ नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी को चेतावनी दी. 19 फ़रवरी को मुज़फ्फ़रनगर के कैराना क्षेत्र के चार थानों में शिथिल अपराध नियंत्रण पर पुलिस उपाधीक्षक तथा थानाध्यक्षों को चेतावनी दी गई. 21 फ़रवरी को गौतमबुद्ध नगर की क़ानून व्यवस्था संतोषजनक न पाए जाने पर एसएसपी, एएसपी, सीओ तथा सेक्टर 29 के एसओ को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए गए. 22 फ़रवरी को उरई के पुलिस उपाधीक्षक तथा थानाध्यक्ष को लापरवाही एवं शिथिल पर्यवेक्षण के लिए निलंबित करने के निर्देश दिए. जालौन की मलिन बस्ती के विकास कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर अधिशासी अधिकारी को चेतावनी दी गई. 23 फ़रवरी को विकास कार्यों में लापरवाही तथा शिथिल प्रशासनिक नियंत्रण के कारण जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फ़र्रुख़ाबाद तथा कन्नौज के पुलिस अधीक्षक हटाए गए. घटिया निर्माण के लिए फ़र्रुख़ाबाद लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता एवं लापरवाही के लिए अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद निलंबित किए गए. ज़िला अस्पताल फ़र्रुख़ाबाद के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को कार्यों में रुचि न लेने के लिए प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए तत्काल स्थानांतरण के निर्देश दिए. 24 फ़रवरी को विकास कार्यों में लापरवाही तथा शिथिल प्रशासनिक नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी बलिया के स्थानांतरण के निर्देश दिए. जनपद मऊ के डॉ. अंबेडकर ग्राम में सीसी रोड की गुणवत्ता ख़राब पाए जाने पर अधिशासी अभियंता आरईएस के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए. जनपद मऊ में कांशीराम शहरी ग़रीब आवास योजना के तहत निर्मित भवनों की गुणवत्ता अधोमानक पाए जाने पर आवास विभाग के अधिशासी अभियंता के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए. मऊ ज़िला अस्पताल में गंदगी पाए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निलंबित करने के निर्देश दिए. बलिया ज़िला अस्पताल परिसर में गंदगी तथा लापरवाही के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी हटाए गए. 25 फ़रवरी को कर्तव्य में लापरवाही एवं शिथिल पर्यवेक्षण पाए जाने पर अधिशासी अधिकारी जौनपुर का स्थानांतरण. संत रविदास नगर के अधिशासी अधिकारी को कार्य में लापरवाही बरतने पर चेतावनी दी.26 फ़रवरी को फ़ैज़ाबाद ज़िला चिकित्सालय की असंतोषजनक व्यवस्था के चलते चिकित्सा अधीक्षक निलंबित तथा जिलाधिकारी को चेतावनी. अंबेडकर नगर ज़िला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक निलंबित किए. अकबरपुर तहसील की असंतोषजनक स्थिति के कारण उप जिलाधिकारी व तहसीलदार का स्थानांतरण. अकबरपुर कोतवाली के एक भाग का निर्माण निम्न स्तर का होने पर कार्यदायी संस्था पैक्सफेड का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने के निर्देश दिए. 27 फ़रवरी को बुलंदशहर की सफ़ाई व्यवस्था की सोचनीय स्थिति के लिए अध्यक्ष बुलंदशहर नगरपालिका परिषद के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए. 28 फ़रवरी को लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का स्थानांतरण करने के निर्देश दिए गए. जिलाधिकारी फ़िरोज़ाबाद को शिथिल प्रशासनिक नियंत्रण के लिए तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करने के निर्देश गए. कांशीराम नगर ज़िले की राजस्व एवं अन्य कार्यों की स्थिति संतोषजनक न पाए जाने पर जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी तथा परगनाधिकारी सहावरपुर को हटा दिया गया. फ़िरोज़ाबाद शहर में व्याप्त गंदगी के लिए अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को चेतावनी दी गई. फ़िरोज़ाबाद ज़िला अस्पताल में गंदगी पाए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को लापरवाही के लिए चेतावनी के सख्त निर्देश दिए गए. फ़िरोज़ाबाद के आपूर्ति निरीक्षक के विरुद्ध गंभीर शिकायतें मिलने पर उन्हें स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए. 1 मार्च को हरदोई के थाना अतरौली में अनुसूचित जाति/जनजाति महिलाओं के अत्याचार की बढ़ती घटनाओं के लिए सीओ तथा थानाध्यक्ष को चेतावनी दी. 2 मार्च को उन्होंने बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर,जनपदों का अंतिम दौरा कर अपने अभियान की समाप्ति की. यहां उन्होंने जिलाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों को ज़रूरी निर्देश ही दिए. बहरहाल, मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर अधिकारियों की लापरवाही यही साबित करती है कि प्रशासन पर उनकी पकड़ कमज़ोर हो गई है.

feedback@chauthiduniya.com

आगरा

बसपा में घमासान तय

प्रियंका सिंह

बहुजन समाज पार्टी ने आगरा ज़िले के सभी नौ विधानसभा सीटों के लिए अपने संभावित प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं. अब पार्टी हाईकमान इन नामों को तय करने के बाद उनकी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है. लिहाज़ा स्थानीय निकायों के चुनाव के नतीजों के बाद प्रत्याशियों की इमेज का नए सिरे से आंकलन किया जाएगा. पार्टी के इस फ़रमान के बाद संभावित प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ गई हैं. आगरा ज़िले के सात विधानसभा क्षेत्रों में बसपा के विधायक हैं.

बसपा के तत्कालीन ज़ोनल कोर्डिनेटर बीरसिंह जाते-जाते जो संभावित प्रत्याशी घोषित कर गए, उनमें आगरा दक्षिण से जुल्फ़िक़ार अहमद भुट्टो, आगरा छावनी सुरक्षित सीट से गुटियारी लाल दुबेश, आगरा देहात सुरक्षित सीट से नारायणसिंह, बाह सीट से मधुसूदन शर्मा, खेरागढ़ सीट से भगवानसिंह कुशवाह, फ़तेहपुर सीकरी सीट से सूरजपाल सिंह, एत्मादपुर सीट से डॉ. धर्मपाल सिंह के नाम हैं. ये सभी मौजूदा विधायक हैं. आगरा उत्तर में डॉ. डीबी शर्मा व फ़तेहाबाद से छोटेलाल वर्मा को भी संभावित प्रत्याशी बना दिया गया है. ज़िले की चार सीटों के स्वरूप बदले हैं. आगरा छावनी और दयालबाग़ अब तक सामान्य सीटें रही हैं. नए परिसीमन में सुरक्षित हो गई हैं और दयालबाग़ सीट का नाम आगरा देहात कर दिया गया है. आगरा पश्चिमी पहले सुरक्षित सीट थी, अब आगरा दक्षिण के रूप में सामान्य हो गई है, वहीं आगरा पूर्वी सीट का नाम बदलकर आगरा उत्तर कर दिया गया है. बसपा के संभावित प्रत्याशियों के नाम आनन-फ़ानन में घोषित होने के बाद कार्यकर्ताओं ने नए प्रत्याशियों के नाम तय होने पर आपत्ति जताई और पार्टी हाईकमान से जोनल कोर्डिनेटर पर प्रत्याशी चयन के लिए ग़लत नाम ऊपर भेजने की शिकायत की. आरोप यह भी लगा कि ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय व तत्कालीन ज़ोनल कोर्डिनेटर बीरसिंह ने आगरा उत्तर क्षेत्र में ग़लत आंकड़े पेश कर ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनवा दिया जो कभी भी बसपा में नहीं रहा. इस बाबत यह भी कहा गया कि डॉ. डीबी. शर्मा सैफ़ई महोत्सव में हेल्थ कैंप लगाते रहे हैं. वे बसपा में शामिल होने से ठीक पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से भी दिल्ली में मिले थे.

आगरा उत्तर सीट पर सर्वप्रकाश कपूर, कुलदीप मिश्र, गंगाधर कुशवाह के नामों पर ग़ौर नहीं किया गया. बसपा में इस बार रुपये के बदले टिकट न देने का फ़ैसला हाईकमान ने सुना दिया है. पार्टी को जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश है. कार्यकर्ताओं को यह बात ठीक लगी. उम्मीद यह थी कि पार्टी के निष्ठावान कार्यकताओं को इस बार टिकट मिलेगा, पर ऐसा हुआ नहीं. बीरसिंह ने हाईकमान को सफ़ाई दी कि उन्हें डॉ. डी. बी. शर्मा का नाम जिलाध्यक्ष शिवचरन लाल मानव ने दिया था और उन्होंने यह भी आंकड़े मुहैया कराए थे कि आगरा उत्तर क्षेत्र में वैश्य बिरादरी के बाद सबसे ज्यादा ब्राह्मण हैं, जबकि इस सीट पर ब्राह्मणों की संख्या चौथे नंबर पर है. बसपा हाईकमान ने फ़िलहाल ज़ोनल कोर्डिनेटर पद से बीरसिंह और जिलाध्यक्ष पद से शिवचरनलाल मानव को हटा दिया है. बसपा के तेज़तर्रार ज़ोनल कोर्डिनेटर के.के गौतम को कानपुर के साथ आगरा का भी चार्ज सौंप दिया गया है.

गौतम संभावित प्रत्याशियों के चयन पर नए सिरे से आंकलन कर रहे हैं. बसपा के कई मौजूदा विधायकों की अपने क्षेत्रों में ही हालत ख़राब है. बाह के विधायक मधुसूदन शर्मा के लिए इस बार राजा महेन्द्र रिपुदमनसिंह भदावर से मुक़ाबला करना कठिन होगा. भदावर भाजपा से पाला बदलकर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं. वहीं खेरागढ़ में मौजूदा विधायक भगवानसिंह कुशवाह का अपने ही समाज में विरोध हो रहा है. वैसे यह क्षेत्र ठाकुर व ब्राह्मण बाहुल्य है. जाट बाहुल्य फ़तेहपुर सीकरी क्षेत्र में बसपा के मौजूदा विधायक सूरजपाल सिंह, ठाकुर बिरादरी के हैं. सूरजपाल की तमाम शिकायतें हैं. उनको एक बार किरावली तहसील में जनविरोध होने पर भागना पड़ा था. दूसरी बार आगरा शहर के बल्केश्वर कॉलोनी में लेनदेन के विवाद में पहुंच जाने पर भीड़ ने उनकी पिटाई कर दी थी. इन दोनों घटनाओं से पार्टी आलाकमान ख़फ़ा है. बसपा के आगरा छावनी के मौजूदा विधायक जुल्फ़िक़ार अहमद भुट्टो को आगरा दक्षिण सीट से संभावित प्रत्याशी तो बना दिया गया है, पर एलआईयू ने उनका रिपोर्ट कार्ड ख़राब कर दिया है. उन पर चर्बी कांड का आरोप चस्पां है. कहा गया है कि यदि जुल्फ़िक़ार अहमद भुट्टो चुनाव लड़े तो चर्बी कांड उछलेगा और उसका असर दूसरे क्षेत्रों पर भी पड़ेगा. वहीं आगरा पश्चिमी सीट ख़त्म होने पर यहां के मौजूदा विधायक गुटियारीलाल दुबेश को आगरा छावनी सुरक्षित क्षेत्र का संभावित प्रत्याशी तो तय कर दिया गया है, किंतु छावनी क्षेत्र में जाटव बिरादरी के लोग गुटियारीलाल दुबेश को प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं. इस बाबत पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज़ोनल कोर्डिनेटर को जानकारी दे दी है. बसपा में प्रत्याशी बनने की पहली परीक्षा पास कर चुके विधायकों व नेताओं के लिए असली अग्नि परीक्षा अब शुरू हो रही है. कार्यकर्ता प्रत्याशी चयन से कितने खुश हैं, इसका अंदाज़ा इस बानगी से लगाया जा सकता है कि आगरा उत्तर में कैडर की दो बैठकें जाटव बिरादरी के मुहल्लों में बुलाई गईं और दोनों बैठकें कोरम पूरा न होने के कारण रद्द कर दी गईं. बसपा हाईकमान तक संदेश पहुंच गया है कि प्रत्याशी चयन में कार्यकर्ताओं की भावना को नज़रंदाज़ किया गया है. पार्टी के ज़ोनल कोर्डिनेटर ने सभी संभावित प्रत्याशियों को पहला निर्देश टास्क कैडर मीटिंग कराने का दिया है. इसके बाद स्थानीय निकाय के चुनावों में अपने-अपने क्षेत्र में बसपा के सभासद जिताने की ज़िम्मेदारी सौंपी है. जिन क्षेत्रों में पचास फ़ीसदी से कम प्रत्याशी जीते उस प्रत्याशी का नाम संभावित प्रत्याशियों में रहेगा या नहीं, यह मायावती तय करेंगी. फ़िलहाल बसपा अपने कैडर कैंपों में कार्यकर्ताओं के न आने को लेकर परेशान हैं. कार्यकर्ताओं की शिकायतों को पहली बार सुना जा रहा है. तमाम कार्यकर्ता विधायकों पर सिर्फ़ अपनी जाति के लोगों के ही काम कराने के आरोप लगा रहे हैं. संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को भरोसा दे रहे हैं कि नगर निगम व नगर पालिका के चुनाव के बाद प्रत्यशी चयन का काम नए सिरे से होगा.

> आगरा उत्तर सीट पर सर्वप्रकाश कपूर, कुलदीप मिश्र, गंगाधर कुशवाह के नामों पर ग़ौर नहीं किया गया. बसपा में इस बार रुपये के बदले टिकट न देने का फ़ैसला हाईकमान ने सुना दिया है. पार्टी को जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश है. कार्यकर्ताओं को यह बात ठीक लगी. उम्मीद यह थी कि पार्टी के निष्ठावान कार्यकताओं को इस बार टिकट मिलेगा, पर ऐसा हुआ नहीं.

पहले जैसी बात नहीं रही

बहुजन समाज पार्टी में चार साल पहले जैसी बात नहीं रही. इसका अंदाज़ा ज़िला पंचायत के चुनाव में हो गया है. तब बसपा विपक्ष में थी और ज़िले के 52 पंचायत सदस्यों में से बसपा के 18 सदस्य जीते थे. इस बार सूबे में बसपा सरकार है. इसके बावजूद सिर्फ़ 8 पंचायत सदस्यों की सीटें ही बसपा को मिलीं हैं. बसपा के ज़िम्मेदार नेता मान रहे हैं कि अब पहले जैसी बात नहीं है. इसका सबसे बड़ा कारण वे विधायकों की कार्यप्रणाली को मानते हैं. उनका कहना है कि विधायक सिर्फ़ अपनी जाति के लोगों के ही काम करते हैं. जब से गोरेलाल आगरा के ज़ोनल कोर्डिनेटर पद से हटे हैं, तब से पार्टी के बेस वोट बैंक ङ्गजाटवफ बिरादरी के लोगों की पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है. आगरा में उद्यानमंत्री नारायणसिंह, विधायक गुटियारीलाल दुबेश, विधान परिषद सदस्य बीरू सुमन शहर में ही रहते हैं. देहात के दलित समाज के लोगों की पीड़ा कोई नहीं सुनता. बसपा नेता इस बात से भी परेशान हैं कि जो जाटव विधायक हैं वे भी जाटव के अलावा अन्य किसी दलित बिरादरी के लोगों का काम नहीं करते. पार्टी के पास वोट बैंक के नाम पर सिर्फ़ जाटव ही हैं. हालांकि पिछड़ी जातियों में कुशवाह, बघेल व निषाद बिरादरी बसपा से जुड़ी है. बसपा नेता जाटव के साथ पिछड़ा वर्ग के जुड़ने से राहत की सांस ले रहे हैं.

नगर निगम के चुनाव असली परीक्षा

बहुजन समाज पार्टी के लिए नगर निगम के चुनाव विधानसभा के चुनाव से पहले का सेमीफ़ाइनल है. पार्टी के नेता इस चुनाव में अपनी पूरी ताक़त लगाने की तैयारी कर रहे हैं. बसपा पिछले नगर निगम चुनाव में 100 में से 32 पार्षद जिताने में कामयाब रही थी. इस बार बसपा कई ख़ेमों में बटी है. ऐसे में जिलाध्यक्ष डॉ. रामबाबू हरित के लिए सभी को एकसाथ मिलाकर प्रत्याशियों का चयन करना टेढ़ी खीर होगी. हालांकि बसपा ने इस बार जाटव के साथ कुशवाह, बघेल जैसी पिछड़ी जातियों को जोड़ लिया है, पर पार्टी में जाटव के अलावा अन्य किसी दलित बिरादरी को अपने साथ नहीं जोड़ पाई. पार्टी के नेताओं के लिए यह चिंता का प्रश्न है. आगरा में दलितों में कोरी, वाल्मीकि व खटीक समाज बहुतायत में है. बसपा से कटे ये दलित भाजपा से जुड़े हैं. आगरा में ग़ैर जाटव दलितों को बसपा से जोड़ने के लिए कभी गंभीरता से पहल नहीं की गई.

भाईचारा कमेटियां गुम हो गईं

बहुजन समाज पार्टी सर्वसमाज का नारा देकर पिछले विधानसभा चुनाव में सत्ता तक पहुंची थी. पार्टी ने 17 जातियों की भाईचारा कमेटियां बनाई थीं, पर अब एक भी भाईचारा कमेटी काम नहीं कर रही. बसपा इस बात को लेकर भी चिंतित है. बसपा अपनी प्रत्येक भाईचारा कमेटी के एक विधानसभा क्षेत्र में 1700 पदाधिकारी बनाती थी. इस तरह बसपा की 20 से 30 हज़ार तक उन मतदाताओं तक पकड़ बना रही थी जो बसपा से सीधे नहीं जुड़ते. इन कमटियों के न होने से भी संभावित प्रत्याशी परेशान हैं.

feedback@chauthiduniya.com

पार्टी गुटबाज़ी की शिकार

आगरा बहुजन समाज पार्टी गुटबाज़ी की शिकार है. पार्टी के कार्यकर्ता कई ख़ेमों में बटे हैं. हाईकमान इन ख़ेमों को ख़ुश करने के लिए पार्टी के जिलाध्यक्ष और ज़ोनल-कोर्डिनेटर बदलती रहती हैं. बहुजन समाज पार्टी में माना जाता है कि यहां कोई गुट नहीं होगा, पर ज़िला स्तर पर पार्टी में कई गुट हैं. इनके आक़ा सूबे की सरकार में काबीना मंत्री हैं. सबसे ताक़तवर गुट ऊर्जा मंत्री रामवीरसिंह उपाध्याय का है. ऊर्जा मंत्री की पत्नी सीमा उपाध्याय फ़तेहपुर सीकरी सीट से सांसद हैं. इनके गुट में राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त छोटेलाल वर्मा भी हैं. श्री वर्मा को पार्टी फ़तेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से संभावित पत्याशी घोषित कर चुकी है. विधान परिषद सदस्य सुनील कुमार चित्तौड़ बरेली के ज़ोनल कोर्डिनेटर हैं. चित्तौड़ का आगरा गृह जनपद है. लिहाज़ा वे आगरा में अपना दबदबा बनाए रखने की पुरज़ोर कोशिश करते रहते है. निवर्तमान जिलाध्यक्ष शिवचरनलाल मानव इसी गुट के थे. विधायक गुटियारीलाल दुबेश व डॉ. धर्मपाल सिंह भी इसी गुट के हैं. सांसद रामवीरसिंह को इसी गुट के दबाव में आने के कारण अपनी ज़ोनल कोर्डिनेटर की कुर्सी छोड़नी पड़ी. बसपा में दूसरा शक्तिशाली गुट सरकार के सबसे प्रभावशाली मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीक़ी का है. इस गुट में विधायक जुल्फ़िक़ार अहमद भुट्टो व गोरेलाल हैं. गोरेलाल मेरठ मंडल के कोर्डिनेटर हैं. बसपा में आज भी ज्यादातर पार्षद गोरेलाल के साथ हैं. मौजूदा जिलाध्यक्ष डॉ. रामबाबू हरित व विधायक सूरजपालसिंह इसी ख़ेमे से ताल्लुक़ रखते हैं. बसपा में तीसरा गुट कुशवाह बिरादरी का है. इसकी कमान मायावती के सबसे नज़दीकी भगवानसिंह कुशवाह, ज़िला सहकारी बैंक के अध्यक्ष गंगाधर कुशवाह, ज़िला पंचायत अध्यक्ष दौलतराम कुशवाह शामिल हैं. चौथा गुट बसपा के राष्ट्रीय महामंत्री व विधायक धर्मपाल भारतीय का है. वे आगरा से बाहर रहते है. फिर भी विधायक मधुसूदन शर्मा व विधान परिषद सदस्य प्रताप बघेल इसी गुट में हैं. पांचवां गुट सांसद व राष्ट्रीय महासचिव एस.पी. सिंह बघेल का है. इस गुट में कोई नामचीन नेता नहीं है, पर बघेल के समर्थक किसी अन्य गुट से जुड़ने की कोशिश नहीं करते हैं. सांसद बघेल की पत्नी मधु बघेल पिछले विधानसभा चुनाव में हाथरस ज़िले के सिकंदराराऊ से चुनाव लड़ी थीं. इस सीट पर इस बार ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय को बसपा ने संभावित प्रत्याशी घोषित कर दिया है. हालांकि एस.पी. सिंह बघेल ने मुख्यमंत्री मायावती से कह दिया है कि उनके परिवार का कोई सदस्य विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगा, पर पर्दे के पीछे से बघेल का ख़ेमा रामवीर उपाध्याय पर एत्मादपुर सीट पर बघेल बिरादरी को टिकट देने के लिए दबाव बना रहा है. इसी कारण डॉ. धर्मपालसिंह ने ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय का ख़ेमा छोड़कर नसीमुद्दीन सिद्दीक़ी का दामन थाम लिया है. बसपा में छठा गुट उद्यानमंत्री नारायणसिंह का है. इस गुट में विधान परिषद सदस्य डॉ. स्वदेश कुमार उर्फ़ वीरू सुमन हैं. उद्यानमंत्री का ख़ेमा कमज़ोर है, पर मुख्यमंत्री के मुख्य सुरक्षा अधिकारी पदमसिंह व नारायणसिंह के बीच की नज़दी की सबको मालूम है.

दूषित पानी ने विकलांग बनाया

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के लगभग 50 गांवों के लोग ज़हरीले भू-जल के कारण विकलांगता का शिकार हो रहे हैं. विषैले पानी के कारण कई लोग अपनी आंखें गंवा चुके हैं तो कई के हाथ-पैर टेढ़े हो गए हैं. अफ़सोस की बात तो यह है कि यह समस्या शासन के अभिलेखों तक में दर्ज है, लेकिन अभी तक इस समस्या के समाधान के लिए कोई क़दम नहीं उठाया गया. बीते दिनों सीडीओ जब इन गांवों का निरीक्षण करने पहुंचे तो उन्होंने भी समस्या की जानकारी होने की बात मानी और जल्द ही ठोस कार्यवाही का आश्वासन दिया. जाजमऊ टेनरी का कचरा पिछले कई वर्षों से गांव लखापुर, पोनी, कर्मी, निहालखेड़ा, धोंधी, हैबतपुर, पहाड़पुर, महादिनवा, भिटवा, धनइया, महेशखेड़ा, दलनारायणपुर, कटहा, फत्तेपुर, पिपरिया, गजियाखेड़ा, नयाखेड़ा समेत क़रीब 50 गांवों से होकर गुज़र रहा है. इससे यहां का भूमिगत जल विषैला हो गया है. वर्ष 1974 में तत्कालीन राज्यपाल एम. चेन्नारेड्डी ने गांव हैबतपुर में पानी की टंकी का निर्माण कराया था. इस टंकी का नाम लुलपुंज पानी की टंकी रखा गया. इससे दूषित पानी की समस्या झेल रहे पचास गांवों को पानी मुहैया कराया जाना था. टंकी से आसपास के गांवों को तो पानी पहुंचने लगा, लेकिन दूर-दराज के गांवों में साफ़ पानी की समस्या बनी रही. विकलांग का शिकार गांव घोंघी के निवासी राजकिशोर व सोने लाल ने बताया कि दूषित पानी के कारण कई लोग विकलांग हो गए. कई अपनी आंखों की रौशनी गंवा चुके हैं. पूर्व प्रधान अनिल त्रिवेदी व विश्नाथ ने बताया कि ज़हरीला पानी पीकर इन गांवों में रहने वाले किसी व्यक्ति का हाथ तो किसी की गर्दन तक टेढ़ी हो गई. इस इलाक़े की लगभग एक लाख की आबादी आज भी स्वच्छ पेयजल के इंतज़ार में अपंग होती जा रही है. हालांकि मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार द्विवेदी ने जल्द ही गांवों को साफ़ पानी मुहैया कराने का वादा किया है. बीते दिनों पंयायत चुनाव से पूर्व इन गांवों के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार तक कर दिया था. इसके बाद सीडीओ आनंद कुमार द्विवेदी लाव-लश्कर के साथ गांव पहुंचे और उन्होंने समस्या को जल्द दूर करने का आश्वासन देकर मतदान करने के लिए ग्रामीणों को मना लिया. मगर ग्रामीणों की पानी की समस्या के समाधान के लिए कुछ नहीं किया गया.

अवनीश कुमार
feedback@chauthiduniya.com

अधिकारी की ग़लतबयानी

अमन कौशिक

जनपद फ़िरोज़ाबाद के अर्थ एवं संख्याधिकारी ए श्रीकृष्ण अपनी निरंकुशता के कारण ज़िले के अधिकारियों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं. यह अधिकारी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गए कार्यों को समय से पूरा न करने के कारण हमेशा चर्चा में रहता है. पिछले दिनों जनप्रतिनिधियों के शिकायती पत्र के आधार पर संयुक्त निदेशक प्रशासनद्ध आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक के पत्रांक 566जी14/2009 टी.सी. दिनांक 20 जनवरी 2011 द्वारा जिलाधिकारी फ़िरोज़ाबाद से उक्त अधिकारी श्रीकृष्ण के गृह जनपद की पुष्टि के संबंध में जानकारी मांगी गई थी, क्योंकि जनप्रतिनिधियों की शिकायत के अनुसार इस अधिकारी ने अपने अभिलेखों में गृह जनपद इटावा दर्ज करा रखा था, जबकि इसका गृह जनपद फ़िरोज़ाबाद ही है. जिलाधिकारी फ़िरोज़ाबाद ने इसकी जांच एसडीएम सदर फ़िरोज़ाबाद से कराई, जिसमें एसडीएम सदर ने पत्रांक 296/एसटी सदर-डीएम द्वारा जिलाधिकारी फ़िरोज़ाबाद को सौंपते हुए स्पष्ट किया कि यह अधिकारी तहसील व जनपद फ़िरोज़ाबाद के गांव फुलाइची थाना मटसैना का मूल निवासी है. वर्तमान में ये अधिकारी अर्थ एवं संख्याधिकारी-ए के पद पर फ़िरोज़ाबाद में तैनात है. जिलाधिकारी फ़िरोज़ाबाद ने अपने पत्रांक 74/शिका. सहा. 31 जनवरी 2011 द्वारा आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक उत्तर प्रदेश को जांच रिपोर्ट प्रेषित कर दी. यहां यह भी उल्लेख करना ज़रूरी है कि जनप्रतिनिधियों ने अपनी शिकायत में श्रीकृष्ण के ख़िलाफ़ स्थानीय स्तर पर नेतागीरी करने के भी आरोप लगाए थे. क़ानूनन राजपत्रित अधिकारी की उसके गृह जनपद में नियुक्ति हो ही नहीं सकती. इसका मतलब उक्त अधिकारी श्रीकृष्ण ने सोची समझी रणनीति के तहत अपने अभिलेखों में अपना जनपद इटावा लिखाया था और अपनी उसी रणनीति के आधार पर वह अपनी पोस्टिंग फ़िरोज़ाबाद में कराकर लाया था. यह स्पष्ट रूप से ग़लतबयानी का मामला बनता है. अपने गृह जनपद में पोस्टिंग पाकर अब उक्त अधिकारी निरंकुश हो गए हैं और सोचने लगे हैं कि अब उनकी पौबारह होगी, लेकिन उनकी कारगुज़ारियों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों में असंतोष भर दिया. उक्त अधिकारी के निरंकुश होने का एक उदाहरण आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक 3273/जी/18/88टीसी दिनांक 5 अक्टूबर 2010 के अनुपालन न करने से भी मिलता है. निदेशक ने अपने पत्र में श्रीकृष्ण को आगरा के अर्थ एवं संख्याधिकारी के पद से सेवानिवृत्त होने वाले राजेन्द्रपाल सचदेव के स्थान पर आगरा जाकर उनका अतिरिक्त चार्ज संभालने का आदेश दिया था. आदेश में स्पष्ट लिखा था कि आप अग्रिम आदेशों तक सेवानिवृत्त होने वाले राजेन्द्रपाल सचदेव के कार्यों को भी संपादित करेंगे, किंतु अधिकारी श्रीकृष्ण को इस पत्र के माध्यम से अपने ऊपर गाज गिरती नज़र आई. उन्हें लगा कि यदि उन्होंने आगरा जाकर अतिरिक्त चार्ज ले लिया तो निदेशक फ़िरोज़ाबाद में कोई दूसरा अधिकारी भेजकर कुछ दिन बाद ही उन्हें आगरा में ही स्थाई रूप से रहने का आदेश भेज देंगे. प्रमुख सचिव नियोजन मंजीतसिंह ने इस संबंध कहा कि उनके संज्ञान में इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी. अब वे इस संबंध में जांच कराएंगे. यदि आरोप के अनुसार ही अभिलेखों में गड़बड़ी पाई गई तो उक्त अधिकारी के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

feedback@chauthiduniya.com

महिला यौन उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश सबसे आगे

राजीव अग्निहोत्री

इन दिनों उत्तर प्रदेश रेप प्रदेश बना हुआ है. आए दिन प्रदेश में हो रही बलात्कार की घटनाओं ने प्रदेशवासियों में दहशत पैदा कर दी है. यहां विदेशी महिला मेहमानों को भी नहीं बख्शा जा रहा है. प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं. अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र के महुआखेड़ा गांव में बलात्कार पीड़ित 19 वर्षीय युवती ने ख़ुद को ज़िंदा जलाया, एटा के कोतवाली क्षेत्र स्थित कांशीराम आवास कॉलोनी में 11 वर्षीय लड़की के साथ गैंगरेप, आगरा के थाना हरीपर्वत क्षेत्र में 3 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार, जिसमें उस बच्ची की मौत हो गई, झांसी के मऊरानीपुर इलाक़े में बलात्कार के बाद युवती ने आत्मदाह करके अपनी जान दे दी, बांदा जनपद में नसैनी गांव की 15 वर्षीय लड़की के साथ तमंचे के बल पर बलात्कार, रायबरेली जनपद के डलमऊ इलाक़े में 15 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार, आगरा जनपद के थाना हरीपर्वत के किदवई पार्क इलाक़े में 13 वर्षीय किशोरी के साथ गैंगरेप के बाद हत्या, फ़र्रुख़ाबाद जनपद के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के नगला स्वामी गांव की 8 वर्षीय लड़की की बलात्कार के बाद हत्या, कन्नौज जनपद में 14 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार, उन्नाव जनपद के सफ़ीपुर थाने के पुरवा गांव में 17 वर्षीय किशोरी से बलात्कार के प्रयास में विफल होने पर मारने का प्रयास, फ़तेहपुर जनपद में 16 वर्षीय छात्रा के साथ गैंगरेप के प्रयास में विफल होने पर कुल्हाड़ी से हाथ-पैर काट डाले, ग़ाज़ियाबाद के कमला नेहरू नगर में छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार कानपुर जनपद के कोतवाली पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एयरफ़ोर्स स्कूल की कक्षा 8 की छात्रा से शिक्षक द्वारा बलात्कार, कानपुर जनपद के चकेरी इलाक़े में महिला के साथ 10 दिन तक लगातार सामूहिक बलात्कार किया गया. बलात्कार के ये सिर्फ़ वे मामले हैं जो फ़रवरी माह में मीडिया में सुर्ख़ियां बने रहे. बलात्कार या बलात्कार के प्रयास अन्य मामलों का हम ज़िक्र नहीं कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश सरकार को कई मामलों में तो अपने विधायकों व मंत्रियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी पड़ी. बांदा रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया. याची ने सरकार पर आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी, क्योंकि इस मामले में सत्तारूढ़ पार्टी बसपा का विधायक पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी आरोपी था. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आफ़ताब आलम और आर. एस. लोढा की दो सदस्यीय खंडपीठ के सामने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क रखा कि किशोर अधिनियम के तहत किशोर को हिरासत में नहीं रखा जा सकता. अधिवक्ता ए. एन. राजारमण ने अपनी जनहित याचिका में अदालत से कहा कि केवल यह इस मामले तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य मामलों में भी मजिस्ट्रेट किशोर को पुलिस हिरासत में भेज देते हैं. उन्होंने अदालत से इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर संज्ञान में लेने का आग्रह किया. यहां उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश ने देश को कई प्रधानमंत्री दिए है और इसमें भी दो राय नहीं कि भारत की राजनीति का केन्द्र बिंदु उत्तर प्रदेश ही रहता है. वर्तमान में इस प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला है, वह भी दलित वर्ग की. इसलिए अपेक्षा की जाती है कि प्रदेश में महिला यौन उत्पीड़न के मामलों में कमी आनी चाहिए, साथ ही ऐसे मामलों की सुनवाई भी तेज़ी से होनी चाहिए. इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में महिला यौन उत्पीड़न के मामले सबसे अधिक हो रहे हैं. ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता, जिस दिन बलात्कार की कोई घटना न होती हो. दलित महिलाओं की स्थिति तो और भी बदतर है. मुख्यमंत्री मायावती इन सब घटनाओं से बेख़बर हों, ऐसा भी नहीं हो सकता. हालत यह है कि कहीं मंत्रियों के उत्पीड़न की शिकार महिलाएं उनकी कार के आगे लेट रही हैं तो कहीं सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों को मुख्यमंत्री के सामने पहुंचने नहीं दिया जाता. जिन लोगों ने मायावती शासन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की कोशिश की, उन्हें सरकारी काम में बाधा डालने के नाम पर जेल भेज दिया जाता है, ताकि लोगों में सरकार के प्रति डर बना रहे.

उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपराधियों पर अंकुश लगाए या मायावती सरकार में शामिल लोगों को आरोपों से बचाए. बांदा रेप केस इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार स्थानीय पुलिस ने सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी को बचाने के लिए क़ानून की बलि चढ़ा दी और यौन उत्पीड़न की शिकार महिला पर चोरी का केस बनाकर उसे जेल भिजवा दिया. वह तो इस मामले में मीडिया कूद पड़ा. मीडिया का दबाव बनने के बाद ही विधायक को गिरफ्तार किया गया था. पिछले दिनों मात्र दो दिनों के भीतर राज्य के अलग-अलग हिस्सों में घटी गैंगरेप की 6 घटनाओं ने लोगों को चौंका दिया था. एक घटना नोएडा की एक मल्टीनेशनल कंपनी की सेल्सगर्ल के साथ घटी. इस सेल्सगर्ल के साथ चार युवकों ने ग़ाज़ियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में रईसपुर गांव के पास गैंगरेप किया, वह भी युवती के ब्वायफ्रेंड कृष्णा के सामने. युवकों ने कृष्णा को बंधक बना लिया था. इसके बाद युवकों ने कृष्णा के बैग से लैपटाप, मोबाइल और जेब से 450 रुपये निकाल लिए. जाते-जाते चारों युवक कृष्णा को मुंह न खोलने की धमकी भी दे गए. बदहवास युवती किसी तरह अपने घर चली गई, लेकिन कृष्णा ने रात के नौ बजे घटना की सूचना कविनगर पुलिस को दी. पुलिस ने चारों आरोपियों को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया. इसी तरह रायबरेली में एक नाबालिग दलित किशोरी के साथ गांव के ही दो युवकों ने गैंगरेप किया. पहले तो पुलिस ने इस मामले की एफ़आईआर ही दर्ज नहीं की. कई दिन बाद दबाव बनने पर पुलिस को आरोपियों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करना पड़ा. फ़तेहपुर ज़िले में तो अपराधियों ने हैवानियत की हदों को ही पार कर दिया. गैंगरेप की कोशिश में नाकाम होने के बाद हैवानों ने 16 वर्षीय दलित किशोरी सारिका की हाथ-पैर की अंगुलियां ही काट डालीं. इस मामले में मुख्य आरोपी श्रीओम बहुजन समाज पार्टी का स्थानीय कार्यकर्ता है. कांग्रेस के महासचिव व सांसद राहुल गांधी इस दलित किशोरी को देखने कानपुर के अस्पताल में गए अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र के महुआखेड़ा गांव निवासी 19 वर्षीय युवती की पिछले दिनों अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में मृत्यु हो गई. युवती ने एक दिन पहले शाम को ख़ुद को आग लगा ली थी. वह साठ फ़ीसदी से ज्यादा जली थी. उसके आत्मदाह करने का कारण गांव के ही 20 वर्षीय आमिर द्वारा उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करना था, जिससे वह बहुत ही क्षुब्ध हो गई थी. युवक फ़रार है. इसी प्रकार झांसी के मऊरानीपुर थाने के अंतर्गत भी 18 साल की युवती ने बलात्कार के बाद आत्मदाह कर जान दे दी. एस.एस.पी. झांसी के अनुसार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. हम यहां हरदोई ज़िले के अतरौली की निवासी दलित महिला शालिनी का ज़िक्र ज़रूर करना चाहेंगे. इस युवती के साथ 19 फ़रवरी 2009 को पति के सामने ही गैंगरेप हुआ था और उन तीनों बदमाशों ने नगदी-ज़ेवर भी लूट लिए थे. बदमाश जाते-जाते इन दोनों के मुंह पर पेशाब भी कर गए थे. शालिनी अपने पति के साथ अपने मायके काकोरी जा रही थी कि अंधे की चौकी नवीपनाह मार्ग पर तीन लोगों ने उन्हें रोक लिया और इस घटना को अंजाम दिया. महिला पांच माह की गर्भवती थी और हादसे के बाद उसका गर्भ भी गिर गया था. उसी दिन दोनों ने घटना की रिपोर्ट थाना काकोरी में लिखानी चाही तो पुलिस ने आनाकानी की. बाद में पुलिस महानिदेश के आदेश के बाद ही इस घटना की रिपोर्ट लिखी गई थी. घटनास्थल पर दो युवकों के पर्स गिर गए थे उन्हें पीड़ितों ने थाने में जमा करा दिया था. उन पर्सों के आधार पर बलात्कारियों की पहचान तो पुलिस ने कर ली, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं रही है. बताया जा रहा है कि पीड़ित दंपत्ति पर समझौते का दबाव डाला जा रहा है. आज तक शालिनी को इंसाफ़ नहीं मिला है, बल्कि दोषियों को बचाने में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री बाबूसिंह और राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त रामचन्द्र प्रधान लगे हुए हैं. न्याय के लिए महिला लखनऊ के झूलेलाल पार्क में धरने पर बैठी है. मुख्यमंत्री को चाहिए कि वे प्रदेश को जोनों में बांटकर कुछ फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाएं, जिनमें प्रदेश के सभी बलात्कार के मामलों की निरंतर सुनवाई हो और सीमित समय में उनका फ़ैसला हो.

feedback@chauthiduniya.com

विपक्षी दलों ने आलोचना की

विपक्षी पार्टियां राज्य में बिगड़ रही क़ानून व्यवस्था की मुख्य वजह मायावती सरकार में शामिल अपराधियों को बता रही हैं. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामआसरे कुशवाहा का कहना है कि राज्य में प्रतिदिन गैंगरेप हो रहे हैं. अपराधी बेख़ौफ़ हो गए हैं. मायावती ने प्रभावशाली लोगों को टिकट देकर विधायक बना दिया है. पुलिस बसपा के उन प्रभावशाली लोगों को बचाने की संस्था बनकर रह गई है.भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सूर्यप्रताप शाही का कहना है कि राज्य में जंगलराज चल रहा है. अपराधी सत्ता में शामिल हो गए हैं. सत्ता के दबाव में पुलिस बेबस हो गई है और अपराधियों पर कार्रवाई करने से बच रही है. हालात यह हैं कि बिना लखनऊ से आदेश के किसी भी ज़िले में ज़िला स्तर का अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता. उत्तर प्रदेश में बढ़ते की मुख्य वजह समाजवादी पार्टी से निकाले गए लोगों का बसपा में भर्ती होकर सत्ता में आ जाना है. उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी का कहना है कि थाना स्तर के पुलिस अधिकारियों का मनोबल गिर गया है. राज्य सरकार ने थानों में रेप और ऐसे अन्य मामलों को रफ़ा-दफ़ा करने की स्पष्ट हिदायत दे रखी है. जो मामले दर्ज हो जाते हैं उनमें भी पुलिस मंत्रियों और विधायकों के दबाव में अपराधियों को संरक्षण दे रही है. मायावती ने अपराधियों और दबंगों को पार्टी में शामिल कर सत्ता तो हथिया ली है, लेकिन प्रदेश में जंगलराज क़ायम हो गया है.

महिला अफ़सरों को बलात्कारियों से निपटने का मौक़ा मिले

विदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी रही किरन बेदी का कहना है कि बलात्कार और महिला उत्पीड़न के मामले महिला पुलिस अधिकारी बेहतर तरीक़े से संभाल सकती हैं. लेकिन उन्हें वह पोस्टिंग ही नहीं दी जाती, जहां उन्हें काम करने की स्वतंत्रता हो. ऐसी घटनाओं के लिए कमज़ोर और भ्रष्ट सरकार प्रमुख रूप से जवाबदेह ह है. पुलिस ज्यादा प्रभावी हो, इसके लिए कई सालों से पुलिस रिफार्म्स की बात की जा रही है, लेकिन कोई सरकार इस पर गंभीर नहीं है. बलात्कार की घटनाओं पर देश में केवल राजनीति की जाती है. हम आज भी 1861 में बने बने ब्रिटिश क़ानून का पालन कर रहे हैं. क़रीब 30 साल से पुलिस रिफार्म्स पर कई कमीशन अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं, लेकिन किसी भी सिफ़ारिश को लागू नहीं किया गया. देश में पुलिस के 4 लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किसी भी देश में एक लाख जनता पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए, लेकिन भारत में यह आंकड़ा 120-130 है. उस पर भी देश में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वीआईपी सुरक्षा में लगे रहते हैं. आम जनता के लिए प्रशासन के पास वक्त नहीं है. पुलिस अधिकारी स्वतंत्रतापूर्वक काम नहीं कर पा रहे. कमज़ोर प्रशासन के कारण पुलिस व्यवस्था भी कमज़ोर है. भ्रष्टाचार ने पूरी व्यवस्था को ख़राब दिया है. अच्छी बात यह है कि आम जनता अब अन्याय और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ खड़ी हो रही है.

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

भारतीय डाक सेवा अपने को मज़बूत करने के प्रयास में है. समय के साथ क़दम से क़दम मिलाने को तैयार है, ऐसे समय में जब अमेरिकी डाक सेवा जो अपनी स्थापना के समय से देश में संचार का सशक्त माध्यम रही, अब ख़त्म होने की कगार पर है.

चंद्रवार की ऐतिहासिक धरोहरों का वजूद ख़तरे में

शिवम तिवारी

फ़िरोज़ाबाद जनपद के चंद्रवार का ऐतिहासिक महत्व है. इसे चंद्रवाड़ भी कहते हैं. यह क्षेत्र कभी जैन धर्म का गढ़ रहा था, लेकिन आज इसके अवशेष धूल–धूसरित होकर अपना अस्तित्व खो रहे हैं. अपने स्थापना काल से लेकर आज तक के सफ़र में इस राज्य ने बहुत से उतार–चढ़ाव देखे हैं. कहते हैं कि भगवान नेमिनाथ व कई अन्य जैन मुनियों की साधना व क्रीड़ा स्थल रहे चंद्रवार को वासुदेव ने बसाया था. बाद में विक्रमी संवत 1052 में राजा चंद्रपाल ने इसे अपने अधिकार में लेकर यहां का राजकाज शुरू किया था. राजा चंद्रपाल ने चंद्रवार नगरी में यमुना के किनारे विशाल क्षेत्र में एक बहुत ही सुंदर क़िले का निर्माण कराया था.

यहां का विपुल वैभव आसपास के राजाओं की आंख में हमेशा ही खटकता रहा था. इसलिए यह राज्य और ख़ासकर चंद्रवार नगरी उनकी लूटमार का शिकार होकर कई–बई बार उजड़ी और बसी. चंद्रवार नगरी के ध्वस्त होने और उजड़ने की घटना भी बहुत ही मर्मस्पर्शी है. महाराजा चंद्रसेन के शासनकाल में विक्रमी संवत 1253 में कन्नौज से लौटते समय मोहम्मद शाहबुद्दीन गौरी ने क्रोधित होकर इस नगर पर अचानक आक्रमण कर दिया था. शांतप्रिय और धार्मिक आस्थाओं वाली यह नगरी यकायक किए गए इस आक्रमण के लिए तैयार नहीं थी. परिणामस्वरूप मोहम्मद शाहबुद्दीन गौरी ने इस नगरी पर विजय पाई और जाते हुए वह 1400 सौ ऊंटों पर यहां से लूटी हुई संपत्ति को लादकर ले गया. क़िस्सा यहीं ख़त्म नहीं हो जाता. इसके बाद भी अन्य मुग़ल शासकों ने चंद्रवार नगरी पर आक्रमण कर इसको लूटा. अपनी अनोखी शान में इठलाते चंद्रवार नगरी के क़िले को बार–बार के आक्रमणों ने जर्जर करके रख दिया. अंतिम आक्रमण में इस क़िले की प्राचीरें ध्वस्त हो गई थीं. तत्कालीन राजा ने इस नगरी को छोड़ते समय अपने आराध्य देवों की प्राचीन प्रतिमाओं को क़िले के किनारे यमुना और बावड़ी में छिपाकर उन्हें सुरक्षित कर दिया था. इसी में से एक बेशक़ीमती और विश्व में एकमात्र भगवान चंद्रप्रभु की स्फटिक की प्रतिमा थी, जो इन दिनों फ़िरोज़ाबाद नगर के चंद्रप्रभु मंदिर में विराजमान है और जो भारत के जैन धर्मावलंबियों के लिए श्रद्धा का केन्द्र बनी हुई है. पिछले दिनों 27 दिसंबर 2010 को प्रसिद्ध मुनि अमित सागरजी महाराज ने यहां खुदाई कराई थी, उस खुदाई में तब यहां से पदमप्रभु भगवान की मूर्ति मिली थी. जैन तीर्थ के नाम से विख्यात प्राचीन चंद्रवार नगरी साहित्य मनीषियों का भी गढ़ रही है. ऐसा उल्लेख श्वेतांबर प्राचीन तीर्थ यात्रा संग्रह संवत 1661 तथा जयविजय रचित सम्मेद शिखर तीर्थ यात्रा माला 1604 एवं सौभाग्य विजय कृत तीर्थमाला में मिलता है. साहित्य सृजन के क्षेत्र में भी चंद्रवार नगरी विख्यात थी. साहित्य मनीषियों ने कई धर्म ग्रंथों की रचना की है, जिनमें नागकुमार चरित्र, भगवान बाहुबलि आदि कई ग्रंथों का नाम उल्लेखनीय है. इसी क्षेत्र में जन्मे जैन मुनि ब्रह्म गुलाल ने भी जैन धर्म से संबंधित कई ग्रंथों की रचना की. 15वीं शताब्दी के कवि नारायणदास ने काव्य ग्रंथ छिताई चरित्र एवं कवियत्री चम्पा ने 1530 व 1540 के आसपास विरह शतक काव्य ग्रंथ लिखा. महाकवि रईधू ने भी कई ग्रंथों की यहां रहकर रचना की थी. कवियों की इस नगरी में कवि श्रीधर, लाखू लक्ष्मण, पदनंदी व धर्मवीर ने अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की. अतिशय क्षेत्र चंद्रवार धार्मिक नगरी के रूप में प्रख्यात रहा है. इस क्षेत्र में प्राचीन मारुति नंदन हनुमान मंदिर, भगवान श्रीकृष्ण, जैन तीर्थंकर, चक्रेश्वरी देवी, ज्वाल मालिनी, कूष्मांडनी देवी, पद्मावती देवी, श्रीजी सुव्रतनाथचरण मंदिर के अलावा कई शिव मंदिर भी यहां थे जो चन्द्रवार पर किए गए मुग़ल शासकों के आक्रमण के दौरान नष्ट हो गए. यहां के टीले बौद्ध टीले के नाम से जाने जाते हैं. इसी प्रकार शाह सूफ़ी की मज़ार भी मुस्लिम समाज के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है. चंद्रवार क्षेत्र को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायमसिंह यादव ने पर्यटन क्षेत्र घोषित किया था, लेकिन इसके विकास की गति कछुआ चाल से कम नहीं है.

किवदंती है कि मोहम्मद गौरी द्वारा चंद्रवार पर किए गए आक्रमण के दौरान गौरी की सेना ने मारुति नंदन हनुमान मंदिर को ध्वस्त करने का प्रयास किया था, किंतु बंदरों ने आकर गौरी की सेना पर हमला बोलकर उसे भागने पर मजबूर कर दिया था. चंद्रवार नगरी में निरंतर होने वाले आक्रमणों के कारण यहां के लोग भागकर फ़िरोज़ाबाद में आकर बस गए. सम्राट अकबर के शासनकाल में फ़िरोज़ाबाद नगर अस्तित्व में आया था. फ़िरोज़शाह ने इसे अपने नाम से 1568 में बसाया था. आज भी नगर पालिका भवन के पास फ़िरोज़शाह का मक़बरा मौजूद है. यह मक़बरा मुग़लकाल शैली में निर्मित कला का एक जीवंत उदाहरण है. फ़िरोज़ाबाद साहित्य सृजन व कला संस्कृति की राजधानी रहा है. साहित्य लेखकों, सांस्कृतिक कर्मियों, बुद्धिजीवियों और शिल्पियों ने यहां रहकर अपनी–अपनी कलाओं को परिमार्जित और संवर्द्धित किया. आज चंद्रवार क्षेत्र के लोग आदिवासियों–सा जीवन जी रहे हैं. ऐसा लगता है कि विकास की छाया इस क्षेत्र पर कभी पड़ी ही नहीं. इसके पिछड़ेपन की इससे बड़ी बात क्या होगी कि इस क्षेत्र की आबादी में मकान बेतरतीब और बेढंगे बने हुए हैं. यहां की बस्ती में नालियां तक नहीं हैं. कहने को इसे पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, जबकि यहां न यात्रियों के लिए गेस्ट हाउस हैं और न वाहन खड़ा करने का कोई उचित स्थान. पर्यटन विभाग ने मात्र महाराजा चंद्रसेन पार्क बनाकर ही अपने दायित्व की इतिश्री कर ली है. भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यहां की आबादी को समग्र गांव योजना में शामिल किया गया था और आज यहां की आबादी को अंबेडकर गांव योजना में शामिल कर लिया गया है. यहां के लोग बेरोज़गारी के शिकार हैं. यहां के स्थानीय निवासियों की आय का मुख्य ज़रिया इस क्षेत्र में खड़े विदेशी प्रजाति के बबूल के पेड़ हैं जिनकी लकड़ी बेचकर ये लोग अपना गुज़ारा कर रहे हैं. सांसद राजबब्बर इस क्षेत्र में नागार्जुन फ़र्टिलाइज़र के एक प्रोजेक्ट को लगवाने की कई बार घोषणा कर चुके हैं, लेकिन इस पर अभी तक अमल नहीं हो पाया है. कभी अख़बारों में इस प्रोजेक्ट के निरस्त हो जाने की ख़बर छपती है तो कभी विचाराधीन होने की बात. आज ज़रूरत इस बात की है कि चंद्रवार नगरी की ऐतिहासिक धरोहरों को मिटने से बचाया जाए. चंद्रवार की ऐतिहासिक धरोहरें हमारे गौरवशाली अतीत की निशानी हैं. पुरातत्व विभाग को इन धरोहरों को संरक्षित करना चाहिए. हमारे जनप्रतिनिधियों को भी चाहिए कि वे चंद्रवार राज्य के अवशेषों को बचाने के लिए जनता की आवाज़ शासन तक पहुंचाएं और क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दें.

feedback@chauthiduniya.com

कवियों की इस नगरी में कवि श्रीधर, लाखू लक्ष्मण, पदनंदी व धर्मवीर ने अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की. चंद्रवार धार्मिक नगरी के रूप में प्रख्यात रहा है. इस क्षेत्र में प्राचीन मारुति नंदन हनुमान मंदिर, भगवान श्रीकृष्ण, जैन तीर्थंकर, चक्रेश्वरी देवी, ज्वाल मालिनी, कूष्मांडनी देवी, पद्मावती देवी, श्रीजी सुव्रतनाथचरण मंदिर के अलावा कई शिव मंदिर भी यहां थे, जो चंद्रवार पर किए गए मुग़ल शासकों के आक्रमण के दौरान नष्ट हो गए.

दुनिया की पहली हवाई डाक सेवा इलाहाबाद से शुरू हुई

आशीष कुमार अंशु

इलाहाबाद में उस दिन डाक की उड़ान देखने के लिए लगभग एक लाख लोग इकट्ठे हुए थे. जब 6500 पत्रों के साथ इलाहाबाद से नैनी जंक्शन तक का हवाई सफ़र आज से 100 साल पहले 18 फ़रवरी को 13 मिनट में पूरा हुआ था.

बहुत दिन हो गए किसी गीत में डाकिया या ख़त का नाम नहीं सुना. अब कोई गीत नहीं लिखता, डाकिया डाक लायाफ न ही किसी गीत के बोल होते हैं, फूल तुझे भेजा है ख़त मेंफ डाकिया की जगह कूरियर वाला और प्रेम पत्र की जगह एसएमएस लेता जा रहा है. अब यह याद करना इंटरनेट, मोबाइल के इस युग में जी रहे किसी भी व्यक्ति के लिए आसान नहीं होगा कि उसने अंतिम पोस्टकार्ड, या अंतरदेशीय कब लिखा था? या फिर कब डाकिया उसके घर में अंतिम पत्र छोड़ गया था. इस बात में कोई आश्चर्य नहीं कि पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बहुत से बच्चों ने पोस्ट कार्ड का नाम तक न सुना हो. वैसे सच्चाई यह है कि आज भारतीय डाक सेवा के सामने चुनौतियां बिल्कुल बदल गई हैं. इस बात को एक प्रबंधन संस्थान में अपने अध्ययन में माना है. अध्ययन के अनुसार आज डाक विभाग सिर्फ़ चिट्ठी मात्र पहुंचाने का माध्यम नहीं है. उसके ज़िम्मे ई–पोस्ट, ई–बिलिंग, रिटेल पोस्ट, लॉजिस्टिक पोस्ट, मीडिया पोस्ट, म्यूचुअल फंड, वेस्टर्न मनी ट्रांसफ़र जैसे बहुत से काम आ गए हैं. साथ में इस समय उसके सामने प्रतिस्पर्धा भी पहले से काफ़ी अधिक बढ़ गई है. इंटरनेट सेवाएं, कूरियर कंपनियां, निजी क्षेत्र के बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, शेयर बाज़ार जैसे उसके प्रतिस्पर्धी हैं.

भारतीय डाक सेवा अपने को मज़बूत करने के प्रयास में है. समय के साथ क़दम से क़दम मिलाने को तैयार है, ऐसे समय में जब अमेरिकी डाक सेवा जो अपनी स्थापना के समय से देश में संचार का सशक्त माध्यम रही, अब ख़त्म होने की कगार पर है. अमेरिका में चल रहे 16000 डाक घर अभी घाटे में चल रहे हैं. वर्ष 2020 तक इनमें से आधे डाक घरों को बंद कर देने की सरकारी घोषणा है. वहीं भारत में डाक विभाग नए–नए प्रयोग कर रहा है. चूंकि वह समय के साथ चलना चाहता है. विभाग ने अजमेर में पत्र वितरित करने वालों को सौर ऊर्जा से चलने वाली साइकिल उपलब्ध कराई, अब गांव के लोगों को डाकिये के माध्यम से जीवन बीमा, बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. सौर ऊर्जा से चलने वाली साइकिल के माध्यम से डाकिया के काम करने की गति बढ़ी है. योजना आयोग के तत्वावधान में माइक्रो फ़ाइनेंस और ग़रीबी उन्मूलन विषय पर काम कर रही एक समिति ने भारतीय डाक सेवा की मदद की बात ग़रीबी उन्मूलन के लिए की. समिति के अनुसार ऑटोमेटिक टेलर मशीन (एटीएम) को यदि डाक घरों के नेटवर्क के साथ जोड़ दिया जाए तो इसके माध्यम से गांव–गांव तक सरकारी योजनाओं का लाभ प्रभावकारी तरीक़े से पहुंचाना आसान होगा. यहां ग़ौरतलब है कि आज भी देश की पैंसठ फ़ीसदी आबादी बुनियादी बैंकिंग सुविधा से वंचित है. सरकार चाहती है कि मार्च 2012 तक देश के दो हज़ार तक की आबादी वाले 73,000 गांवो में पांच करोड़ नए खाते खुल जाएं. इसमें डाक घरों की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है.

डाक सेवा और उसके प्रयोग को वर्ष 2011 में याद करने का एक विशेष कारण है. इस साल भारतीय हवाई डाक सेवा ने अपने सौ साल पूरे कर लिए हैं. भले ही डाक सेवा को प्रारंभ करने का श्रेय ब्रिटेन के पास हो, लेकिन डाक की पहली हवाई यात्रा भारत में हुई. वह समय भारतीय डाक सेवा के इतिहास में एक ख़ास दिन के तौर पर दर्ज हुआ. संयोगवश उस वर्ष इलाहाबाद में कुंभ का मेला भी था. इस विमान को फ्रांसिसी पायलट मोनसियर हेनरी पिक्वेट ने उड़ाया.

अब चलते–चलते यह भी बता दें कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार बारह संख्या वाले इस ख़ास नंबर को भी आप तक भारत के डेढ़ लाख से भी अधिक संख्या में मौजूद डाक घरों के माध्यम से ही पहुंचाया जाएगा.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 14 मार्च -20 मार्च 2011

www.chauthiduniya.com

"संजीवनी का है ऐलान,
झारखण्ड-बिहार में हो सबका मकान"

Website : sanjeevanibuildcon.in

PLOT

BUNGALOW

DUPLEX

AISHWARIYA RESIDENCY
Argora-Kathalmore Road, Ranchi
PLOT 6 LAC | DUPLEX 18 LAC

SANJEEVANI HIGHWAY
Ranchi Patna Highway Road
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

THE DYNASTY
Sidhu Kanhu Park, Kanke Road
PLOT 13 LAC | DUPLEX 25 LAC

SANJEEVANI TOWNSHIP
4 Lane, Kanke Road, Ranchi
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

9973959681
9471356199
9431190351
9472727767
9471527830

फोटो– प्रभात पाण्डेय

राजद के नए रणनीतिकार

छोटे इंतज़ार के बाद राजद का रुख़ काफ़ी आक्रामक हो गया है. इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि जिस चारा घोटाले को लालू प्रसाद के राजनीतिक ध्वंस का कारण माना जाता है, उस मसले पर अब्दुल बारी सिद्दीक़ी ने सदन में राज्य सरकार को चुनौती दे डाली. उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो राज्य सरकार चारा घोटाले के अभियुक्त श्याम बिहारी सिन्हा द्वारा 164 के तहत दिए गए बयान को सार्वजनिक करे.

सरोज सिंह

बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की करारी हार के बाद क़यास लगाए जा रहे थे कि इसका खेल ख़त्म हो गया है. इसी बीच पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद तीर्थाटन में नगरी नगरी द्वारे द्वारे ख़ाक छानते दिखाई पड़ने लगे. तब माना गया था कि राजनीति हार के संताप से मुक्ति के लिए धर्मस्थलों एवं धर्मगुरुओं के चरण में वह शीश नवा रहे हैं. इसी बीच राजद विधायक दल के नेता पद पर तत्कालीन पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल बारी सिद्दीक़ी को मनोनीत किया गया. वहीं उनकी जगह परिहार विधानसभा क्षेत्र में हार चुके पूर्व मंत्री रामचंद्र पूर्वे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया. अब्दुल बारी सिद्दीक़ी और रामचंद्र पूर्वे दोंनो लो-प्रोफ़ाईल नेता माने जाते हैं. लिहाज़ा, आम राय यह बन गई थी कि विधानसभा चुनाव में भारी पराजय से पार्टी का मनोबल चकनाचूर हो गया है. वहीं पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने राज्य सरकार के ख़िलाफ़ छह माह तक मुंह न खोलने का दावा किया. दूसरी ओर राज्य सरकार की कृपा से मात्र बाईस विधायकों वाली पार्टी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीक़ी बिहार विधानसभा में नेता विरोधी दल बन गए. राजनीतिक हलके में अनुमान लगाया जा रहा था कि शराफ़त के लिए प्रसिद्ध अब्दुल बारी सिद्दीक़ी राज्य सरकार के अहसान तले दबकर मुंह नहीं खोल पाएंगे. वैसे भी वह मितभाषी राजनेता हैं, लेकिन सारे पूर्वानुमानों पर पानी फेरते हुए बतौर नेता विपक्ष सिद्दीक़ी भाजपा-जदयू सरकार पर भारी पड़ रहे हैं. बजट सत्र में उनके धारदार संबोधन से सत्तापक्ष बगले झांकते हुए नज़र आया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार विपक्ष के तार्किक हमले से आहत दिखे. इसी उत्तेजना में उन्होंने इसका जवाब दिया था. अब्दुल बारी सिद्दीक़ी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की अंतर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण एवं पदस्थापन में जातिवाद के मुद्दे पर रॉयल ब्लड का सवाल उठाया. विधानसभा में राजद के मुख्य सचेतक सम्राट चौधरी कहते हैं कि पटना के डीएम और एसएसपी एक ख़ास जाति के होंगे. इसके लिए दूसरे कैडर से भी अधिकारियों को लाया जाता है. इसी रॉयल ब्लड पर सवाल खड़ा किया था. जदयू-भाजपा के लोग राजद पर यादव समाज का पक्ष लेने का आरोप मढ़ते रहते हैं, लेकिन राजद शासनकाल में दूसरे राज्य से किसी यादव समुदाय के अधिकारी को नहीं लाया गया. सुधीर कुमार राकेश को अवश्य प्रतिनियुक्ति पर लाया गया था. उन्हें समस्तीपुर का ज़िलाधिकारी बनाया गया था. पर, वह वैश्य समुदाय से आते थे. इसी आरोप का जवाब देने के बजाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तिलमिला उठे. उन्होंने रॉयल ब्लड को ब्लू ब्लड में उलझा दिया.

राजद का रुख़ काफ़ी आक्रामक हो गया है. इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि जिस चारा घोटाले को लालू प्रसाद के राजनीतिक ध्वंस का कारण माना जाता है, उस मसले पर अब्दुल बारी सिद्दीक़ी ने सदन में राज्य सरकार को चुनौती दे डाली. उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो राज्य सरकार चारा घोटाले के अभियुक्त श्याम बिहारी सिन्हा के 164 के तहत दिए गए बयान को सार्वजनिक करना चाहिए. सम्राट चौधरी कहते हैं कि उस बयान में श्यामबिहारी सिन्हा ने बिहार के सत्ताशीर्ष पर विराजमान एक शख्स का नाम लिया था. इसी बीच अब्दुल बारी सिद्दीक़ी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक और तीर छोड़ा. उन्होंने उनकी स्कूली छात्राओं को साइकिल देने की महात्वाकांक्षी योजना का श्रेय लेने की कोशिशों की हवा निकाल दी. उन्होंने दावा किया कि बिहार में इस योजना पर अमल होने के तक़रीबन एक दशक पूर्व तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयाललिता ने इसे ईजाद किया था.

राजद आख़िर इतना हमलावर रुख़ क्यों अपना रही है? राजनीतिक प्रेक्षकों की राय इससे जुदा है. इनका मानना है कि राजद की रणनीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है. बल्कि, पिछली विधानसभा में राबड़ी देवी विधायक दल की नेता थीं. वह बतौर नेता विपक्ष तार्किक तरीक़े से सत्ताधारी जमात को परेशान करने में सक्षम नहीं थी, जबकि संसदीय राजनीति के लंबे अनुभव के कारण अब्दुल बारी सिद्दीक़ी इसमें सिद्धहस्त हैं. हालांकि इसमें एक झोल यह है कि गत विधानसभा में एक से बढ़कर एक दिग्गज विपक्ष दल की बेंच को सुशोभित कर रहे थे. जगदानंद सिंह, रामचंद्र पूर्वे, श्याम रजक, रमई राम, शकुनी चौधरी आदि दिग्गजों के अलावा स्वयं अब्दुल बारी सिद्दीक़ी तब सदन के सदस्य थे. उस समय 56 सदस्यीय राजद विधायक दल अपने शब्दवाणों से कभी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार विपक्ष के तार्किक हमले से आहत दिखे. इसी उत्तेजना में उन्होंने इसका जवाब दिया था. अब्दुल बारी सिद्दीक़ी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की अंतर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण एवं पदस्थापन में जातिवाद के मुद्दे पर रॉयल ब्लड का सवाल उठाया. विधानसभा में राजद के मुख्य सचेतक सम्राट चौधरी कहते हैं कि पटना के डीएम और एसएसपी एक ख़ास जाति के होंगे. इसके लिए दूसरे कैडर से भी अधिकारियों को लाया जाता है. इसी रॉयल ब्लड पर सवाल खड़ा किया था. जदयू-भाजपा के लोग राजद पर यादव समाज का पक्ष लेने का आरोप मढ़ते रहते हैं.

प्रभावशाली नहीं दिखे. युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक मेहता कहते हैं कि राजद अक्रामक नहीं हुई है. वह मुख्य विपक्षी दल के कर्तव्य का निर्वाह कर रही है. पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद ने अवश्य जनादेश का सम्मान करते हुए छह माह तक चुप रहने का मन बनाया था, लेकिन जनसमस्याओं एवं जनसरोकार के मुद्दे से मुंह नहीं चुराया जा सकता है. इस सरकार में चारा घोटाले से दस गुना बड़ा घोटाला हुआ है, जिसे दबाया जा रहा है. लिहाज़ा, राजद को सामने आना पड़ रहा है. पार्टी विधायक दल के मुख्य सचेतक सम्राट चौधरी भी इसकी तस्दीक करते हुए कहते हैं कि विधायक दल में भी तय हुआ था कि छह माह तक राज्य सरकार के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोला जाएगा, लेकिन राज्य में मची अंधेरगर्दी के कारण उन्हें मुंह खोलने पर मजबूर होना पड़ा. बाढ़ की एनटीपीसी को जदयू के विधायक ने लूट लिया, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है.

बिहार की सियासत पर गहरी नज़र रखने वालों का मानना है कि राजद अपनी सूरत और सीरत बदलने को आमादा है. लालू प्रसाद को भी बख़ूबी पता है कि जिस तरह वह भाजपा का भूत दिखाकर लंबी अवधि तक बिहार में शासन करत रहे, उसी तरह नीतीश कुमार उनके भूत का इस्तेमाल कर रहे हैं. माना जा रहा है कि इससे निजात पाने के लिए चेहरा बदला गया है. हाल में राजद में तीन प्रमुख नियुक्तियां हुईं, जिसमें किसी यादव समुदाय के नेता को जगह नहीं मिली. प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे, विधायक दल के नेता अब्दुल बारी सिद्दीक़ी एवं मुख्य सचेतक सम्राट चौधरी का मनोनयन हुआ था. हालांकि, विधायक ललित यादव को लोक लेखा समिति का सभापति बनाया गया है. राजद से जुड़े सूत्रों की मानें तो पार्टी में आम सहमति बनी है कि बेदाग़ चेहरों को आगे लाया जाए, जिससे पार्टी की सकारात्मक छवि उभर सके. इसी के तहत पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीक़ी एवं पूर्व सांसद आलोक मेहता को विशेष ज़िम्मेदारी देने की संभावना बनी थी. चर्चा है कि आलोक मेहता का नाम प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे था. बताया जाता है कि कुशवाहा समाज के स्वयंभू सिरमौर शकुनी चौधरी को यह नागवार गुज़रा. उन्होंने दबाव की राजनीति के तहत लालू प्रसाद के नेतृत्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया. कहा कि लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी दोनों जगह से हार गईं. अब वह नेता नहीं रहीं. कहा जाता है कि इसके दबाव में राजद सुप्रीमो ने रामचंद्र पूर्वे को सूबेदार नियुक्त कर दिया था. सम्राट चौधरी इससे इतर कहते हैं कि जिस व्यक्ति के नाम पर छिहत्तर लाख वोट मिले हैं, उसके नेतृत्व पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता. ग़ौरतलब है कि नाबालिग़ मंत्री के तौर पर कभी पार्टी के गले की हड्डी बन गए थे सम्राट. वहीं लोक लेखा समिति के अध्यक्ष ललित यादव हरिजन वाहन चालक की नाख़ून उखाड़ प्रताड़ना देने के मामले में काफ़ी चर्चा में रहे थे. लेकिन ये खोटे सिक्के भी आड़े वक्त में काम आ रहे हैं.

हालांकि, विधायक दल जितने धारदार तेवर दिखा रहा है, उसके अनुरूप प्रदेश संगठन सुस्त नज़र आता है. सही तरीक़े से प्रेस ब्रीफिंग तक नहीं हो पाती. रामधारी सिंह दिनकर के आवास पर क़ब्ज़े के मामले में प्रदेश इकाई के बजाए विधायक दल के नेता ही विधानसभा से बाहर भी अधिक सक्रिय दिखे. वैसे, प्रतिद्वंद्वी विपक्षी दल कांग्रेस के संगठन की दुर्दशा उनके लिए सुकूनदायक है.

feedback@chauthiduniya.com

ज़िले के सभी 20 प्रखंडों में पंचायत चुनाव की सरगर्मी बढ़ने लगी है. नामांकन के पहले ही संभावित प्रत्याशी मतदाताओं की नब्ज़ टटोलने में जुट गए हैं.

एक नज़र

ढिबरी के उजाले में जीने को विवश

मांझी प्रखंड क्षेत्र के जैतपुर पंचायत का एक गांव पिपरहियां के ग्रामीण आज भी ढिबरी के उजाले में ही जीने को विवश हैं. [illegible] -विक्की पांडेय

मशीनों की ख़राबी से परेशानी बढ़ी

[illegible] के दौरान इसकी वैकल्पिक व्यवस्था कराने का का आदेश सिविल सर्जन डॉ. नरेश प्रसाद को दिया था, लेकिन अभी तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो सकी है. ज़िला मुख्यालय में क़रीब एक महीने से एंटीरीबीज़ सुई उपलब्ध नहीं है. इसके अलावा पिछले एक सप्ताह से सदर अस्पताल में दंत चिकित्सक के न रहने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि जितने भी दंत चिकित्सक संविदा पर कार्यरत थे सिविल सर्जन ने सभी को हटा दिया है. -मनोज प्रसाद

पांच वर्षों से पुल निर्माण अधूरा

दरभंगा के गरौल गांव के नज़दीक विगत पांच वर्षों से पुल निर्माण का कार्य अधूरा पड़ा है. लगभग दो दर्जन से अधिक गांवों के लोग इस पुल के नज़दीक जमा पानी से होकर गुज़रते हैं. बताया जाता है कि उक्त पुल का निर्माण कार्य विगत पांच वर्ष पहले पथ निर्माण विभाग ने शुरू करवाया था. तब से निर्माण अधूरा है. लोगों की मानें तो गरौल गांव के नज़दीक 2004 की भीषण बाढ़ में मुख्य पथ पर ही मोईन फूट गया था. इसके बाद स्थानीय विधायक अब्दुल बारी सिद्दीक़ी के प्रयास से इस मोईन पर पथ निर्माण विभाग ने पुल निर्माण कार्य की स्वीकृति की थी, लेकिन कुछ भभ नहीं हुआ. पंचायत के मुखिया हुसैन ने बताया कि अब भी अगर पथ निर्माण उक्त पुल का निर्माण नहीं करेगी तो इस क्षेत्र की जनता पथ निर्माण विभाग के ख़िलाफ़ आंदोलन करेगी. -चौथी दुनिया ब्यूरो

सेविका बहाली के मामले ने तूल पकड़ा

जमुई के सिकंदरा प्रखंड अंतर्गत मंजोश के खैरा टोला में आंगनवाड़ी सेविका की बहाली के मामले ने तूल पकड़ लिया है. पोषक क्षेत्र के आधा दर्जन आवेदकों ने मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजकर सीडीपीओ के कारनामों का पर्दाफ़ाश किया है. पत्र की प्रतिलिपि ज़िलाधिकारी, समाज कल्याण मंत्री, निगरानी विभाग एवं क्षेत्रीय विधायक को भेजी गई हैं. अंजनी सुमन ने कहा कि खैरा टोले में मिनी आंगनवाड़ी का प्रस्ताव आया था, जिसके तहत सेविका बहाली के लिए आवेदन करने की तिथि की सूचना पोषक क्षेत्र में नहीं दी गई और न ही किसी अख़बार में विज्ञापन दिया गया. भारती के मुताबिक़ सीडीपीओ द्वारा पोषक क्षेत्र से बाहर रहने वाले लोगों को सूचना दी गई. इन्होंने सरकार से मांग की कि हम लोगों के आवेदन को भी स्वीकार किया जाए या जांच कर कार्रवाई की जाए. संबंधित पंचायत के मुखिया प्रमिला देवी एवं वॉर्ड सदस्यों ने भी इस मामले को सही बताया.

वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भूमि पूजन

जमुई में लक्ष्मीनारायण महायज्ञ का भूमि पूजन वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच प्रारंभ किया गया. यह पूजा पुरानी दुर्गा स्थान के प्रांगण में किया गया. इस भूमि पूजन महायज्ञ में यजमान के रूप में चन्द्रशेखर सिंह एवं आचार्य की भूमिका में ललन पांडेय थे. भूमि पूजन के आचार्य ललन जी ने बताया कि भूमि पूजा का अर्थ वस्तु पूजा होता है, इसलिए इनकी पूजा करने के बाद ही यज्ञ का फल मिलता है. यज्ञ आयोजक समिति के अध्यक्ष उमेश चंद्र पांडेय कोषाध्यक्ष उमेश वर्णवाल, सचिव आनंदी सिंह, महामंत्री देवेन्द्र मिश्रा ने बताया कि यज्ञ की सफलता के लिए 23 मार्च को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी. -इमरान ख़ान

तपेश्वर बाबू को याद किया गया

स्व. तपेश्वर सिंह सहकारिता आंदोलन के जनकों में से एक थे और इसके पुरोधा-पुरुष भी थे. बिहार प्रदेश में सहकारिता को आसमान तक पहुंचाने में उनकी बड़ी भूमिका थी. प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मज़बूत करने में भी उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है. यह विचार स्व. सिंह की 20 वीं पुण्यतिथि पर बोरिंग रोड स्थित उनके आवास पर आयोजित एक समारोह में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ. अनिल सुलभ ने व्यक्त किए. डॉ. सुलभ ने कहा कि तपेश्वर बाबू अपने उदार मन और मृदुल स्वभाव के कारण आमजन में, विशेष रूप से ग्रामीणों के बीच बहुत लोकप्रिय थे. इस अवसर पर पूर्व आईएएस अधिकारी और कांग्रेस नेता रामउपदेश सिंह, पूर्व विधायक हरखु, डॉ. विनोद शर्मा, आजमी बारी, जावेद इक़बाल, जनार्दन पाठक तथा माधुरी सिंह समेत कांग्रेसजन एवं प्रबुद्ध व्यक्तियों ने स्व. सिंह की तस्वीर पर श्रद्धा के पुष्प अर्पित किये. सभा का संचालन स्व. सिंह के पुत्र एवं पूर्व विधायक डॉ. अजय कुमार सिंह ने किया. -चौथी दुनिया ब्यूरो

PATALIPUTRA SCHOOL OF FIRE & SAFETY MANAGEMENT
Only one Institute of Bihar & Jharkhand, which is Govt. of India registered, Regd. No. 03-09284 of 2000-2001.
ISO 9001:2000 certified, Regd. No. CCPL/QMS/C1487
Only one Institute of Bihar & Jharkhand, where the full Practicals are conducted.
Only one Institute of Bihar & Jharkhand, where one full paper of 100 marks on petroleum is taught.
Only one Institute of Bihar & Jharkhand, where students of Industrial Safety Management Course of Patna University & Magadh University get Practical Training.
FREE Demo-Classes in the Morning & Evening from Monday to Friday
Excellent Placement with Handsome Salary
Website: www.psfsm.com
410, Ashiana Galaxy, Exhibition Road, Patna-800 001
Ph: 0612-6455019, Mob.: 9334107607, 9835042835, 9234729075

हेल्थ स्मार्ट कार्ड
पंचायत चुनाव में मुद्दा बनेगा

● पांच लाख लोग वंचित रह गए

मनोज कुमार राव

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीपीएल परिवार को मिले हेल्थ स्मार्ट कार्ड का लाभ पूर्वी चंपारण में बहुत कम लोगों को ही मिल रहा है. ग़रीब लोग इस कार्ड के धारक तो बन गए हैं, लेकिन उनके लिए यह कार्ड महज़ सहेज कर रखने वाली एक वस्तु बनकर रह गया है. इस कार्ड में बहुत ही गड़बड़ियां हैं. इस कार्ड के आधार पर जब कोई ग़रीब अपने इलाज के लिए संबंधित अस्पताल में पहुंचता है तो उसे परेशानी के सिवाए कुछ भी हासिल नहीं होता. इस कारण वह सुविधा लेने से वंचित रह जाते हैं. उम्मीद की जा रही है कि आगामी पंचायत चुनाव के दौरान यह योजना संबंधित जनप्रतिनिधियों के लिए सिरदर्द साबित होगी, क्योंकि कार्ड बनने के बाद भी सुविधा का न मिलना अपने आप में आगामी पंचायत चुनाव के लिए एक मुद्दा साबित हो रहा है.

हाल तो यह है कि विगत 31 जनवरी तक ही ज़िले के सभी प्रखंडों में हेल्थ स्मार्ट कार्ड वितरित करना था, लेकिन कार्य धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है. रॉयल सुंदरम इंश्योरेंस द्वारा बनाए गए स्मार्ट कार्ड में बड़े पैमाने पर गड़बडियां सामने आ रही है. इसमें कार्ड का लाभ अधिकांश कार्ड धारकों को नहीं मिल रहा है.

मोतिहारी

आकड़ों के अनुसार पूर्वी चंपारण ज़िले में 8 लाख बीपीएल परिवारों का चयन किया गया था. इनमें 7 लाख 23 हज़ार लोगों का स्मार्ट कार्ड बनाना है, जबकि मात्र 2 लाख 22 हज़ार ही हेल्थ कार्ड अभी तक ज़िले में बनाए जा सके हैं. रोचक तथ्य तो यह है कि पूर्वी चंपारण के 4 प्रखंडों में अभी तक यह योजना प्रारंभ भी नहीं हुई है. ऐसे में यह योजना कितनी कारगर साबित होगी और ग़रीबों को कितना कल्याण करेगी यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा.

पूर्वी चंपारण में स्मार्ट कार्ड बनाने व नर्सिंग होम चयन करने का ज़िम्मा केंद्र सरकार ने रायल सुंदरम इंश्योरेंस को दिया है. पिछले साल से ही यह एजेंसी इस काम में जुटी है, लेकिन जिस परिवार का स्मार्ट कार्ड बनाया गया, उसमें कई ख़ामियां पाई गईं हैं. मसलन नाम का ग़लत होना या फिर अंगूठे का निशान कार्ड धारक से न मिलना. अधिकांश मामलों में गड़बड़ी के कारण चयनित नर्सिंग होम के चिकित्सक मरीज़ों को वापस लौटा देते हैं. इस मामले में डॉ. अमरेंद्र कुमार, डॉ. आर के झा और डॉ. वी के पांडे ने बताया कि मामले की जानकारी संबंधित विभाग तक पहुंचा दी गई है. चिकित्सकों ने यह भी बताया कि फ़रवरी माह में सौ से भी अधिक स्मार्ट कार्ड धारक मरीज़ आए, जिनमें से मात्र 20 से 25 कार्ड धारकों का कार्ड सही पाया गया. इस प्रकरण को लेकर जब रॉयल सुंदरम इंश्योरेंस के अधिकारी मंथन व अमित घोष कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं. इनका बस इतना कहना है कि इन कार्डों का सुधार सामाजिक सुरक्षा विभाग मोतिहारी द्वारा आगामी 7 फ़रवरी से होगा. स्मार्ट कार्ड के ज़रिये इलाज के लिए मां नर्सिंग होम, सर्जरी केयर, राजपाली नर्सिंग होम, सुचित्रा शल्य चिकित्सा, जीवन दीप नर्सिंग होम, समीर सिन्हा नर्सिंग होम, मात छाया नर्सिंग होम का चयन किया गया है, जबकि शरण नर्सिंग होम चंद्रलता नर्सिंग होम व माधुरी नर्सिंग होम के चयन की प्रक्रिया अभी चल रही है. पूर्वी चंपारण के कुछ प्रखंडों में तो यह योजना अभी प्रारंभ भी नहीं हो सकी है. इस सुविधा को उपलब्ध कराने वाले अस्पतालों की सूची में महज 9 अस्पतालों का ही नाम दर्ज किया जा सका है और शेष अस्पतालों के चयन की प्रक्रिया अभी जारी है. वरीय उपसमाहर्ता रजिक ने बताया कि इस योजना को लेकर जितनी भी शिकायतें मिल रही हैं. इस पर सरकार अपनी नजर रख रही है और सभी गड़बड़ियों के निदान के लिए कार्रवाई तेज़ कर दी गई है. सरकार ने इस योजना का शुभारंभ करते हुए इन ग़रीबों के स्वास्थ्य के लिए एक हैजेल फ्री अर्थात बिना झंझट वाले स्वास्थ्र्य कार्ड का नाम दिया था, लेकिन दुभार्ग्य ही है कि इस हैजेल फ्री कार्ड में अभी तक मुश्किलें ही मुशिकलें हैं.

feedback@chauthiduniya.com

● कई कमियां उजागर हुईं

गठबंधन की गांठें ढीली पड़ रही हैं

झाविमो कांग्रेस के साथ इस शर्त पर समझौता कर सकती है कि हटिया विधानसभा के उप चुनाव में उसे उम्मीदवारी की गारंटी मिले. कांग्रेस इस सीट पर केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय के अनुज सुनील सहाय को खड़ा करना चाहती है.

नवल किशोर सिंह

झारखंड में यूपीए और एनडीए में शामिल राजनीतिक दलों के बीच रस्साकशी का खेल शुरू हो गया है. खरसावां उपचुनाव में अर्जुन मुंडा की जीत के बाद ख़ाली होने वाले जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र में एनडीए और यूपीए के घटक दलों के बीच ज़ोर-आज़माइश तेज़ होती जा रही है. खरसावां में भाजपा को समर्थन देने के एवज में जहां झामुमो जमशेदपुर सीट पर अपना दावा ठोक रहा है, वहीं आजसू की अपना उम्मीदवार उतारने की मंशा ज़ाहिर कर गठबंधन धर्म की दुहाई दे रहा है. अर्जुन मुंडा के साथ समस्या यह है कि खरसावां सीट ख़ाली करने के एवज में वहां के तत्कालीन विधायक मंगल सिंह सोय को जमशेदपुर सीट से चुनाव लड़ाने का वचन दे चुके हैं. उधर, झाविमो उम्मीदवार को खरसावां में समर्थन प्रदान करने के एवज में कांग्रेस जमशेदपुर सीट पर अपनी दावेदारी जताकर गठबंधन धर्म के तहत झाविमो से समर्थन की मांग कर रही है. झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की मन:स्थिति में नहीं दिखते. उनका मानना है कि झाविमो का उम्मीदवार कांग्रेस की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन करेगा और उस सीट को निकाल ले जाएगा. उन्हें झारखंड में अपनी पार्टी के बढ़ते जनाधार को देखते हुए जीत का पूरा भरोसा है. कांग्रेस इसे गठबंधन के संतुलन को बनाए रखने में बाधक मान रही है. कांग्रेस का मानना है कि बारी-बारी से सभी को मौक़ा दिया जाना चाहिए अन्यथा गठबंधन का मतलब ही क्या रह जाएगा. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बलमुचु, विपक्ष के नेता राजेंद्र प्रसाद सिंह जमशेदपुर सीट पर उम्मीदवार उतारने की अपनी मंशा ज़ाहिर कर चुके हैं. सूत्रों को कहना है कि झाविमो कांग्रेस के साथ इस शर्त पर समझौता कर सकती है कि हटिया विधानसभा के उप चुनाव में झाविमो की उम्मीदवारी की गारंटी मिले. कांग्रेस इस सीट पर केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय के अनुज सुनील सहाय को खड़ा करना चाहती है. उधर झाविमो ने अजयनाथ शाहदेव को हटिया से उम्मीदवार बनाने की शर्त पर ही पार्टी में शामिल किया है.

-झारखंड-

इधर, भाजपा धर्म संकट में फंसी हुई है. हालांकि यह मुश्किल है लेकिन यदि भाजपा मंगल सिंह सोय को कोई मलाईदार बोर्ड या निगम देने का आश्वासन देकर मना भी लेती है तो उसके समक्ष समस्या यह होगी कि झाममो और आजसू में किसे उतारे. शिबू सोरेन जमशेदपुर संसदीय सीट को अपनी परंपरागत सीट मानते हैं, क्योंकि इस सीट पर लंबे समय तक उनका क़ब्ज़ा रहा है. पिछले चुनाव में अर्जुन मुंडा जैसे क़द्दावर नेता के मैदान में उतरने के कारण उसे यह सीट गवांनी पड़ी थी. उस वक़्त झामुमो एनडीए में नहीं था. अब इसे पूरा भरोसा है कि विपक्ष चाहे जो भी उम्मीदवार उतारे, सीट उसकी झोली में ही जाएगी. आजसू ने जमशेदपुर सीट पर कभी जीत हासिल नहीं की, लेकिन उसका दावा गठबंधन में बराबरी के अधिकार को लेकर है. उसका मानना है कि खरसावां में भाजपा को समर्थन देने के एवज में उसे कुछ तो मिलना चाहिए. उधर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी कहते हैं कि जमशेदपुर संसदीय सीट पर भाजपा की स्वाभाविक दावेदारी बनती है. इस सीट पर भाजपा अकेले दम पर एक लाख से भी अधिक वोटों के अंतर से जीती है. भाजपा अपना उम्मीदवार देने का निर्णय ले चुकी है. वह पीछे नहीं हट सकती. जमशेदपुर लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने के सवाल को झामुमो ने भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है. पूर्व सांसद सुमन महतो सहित पार्टी के अन्य विधायकों का मानना है कि अर्जुन मुंडा को विकट परिस्थिति में झामुमो ने समर्थन दिया. लिहाज़ा गठबंधन धर्म का ध्यान रखते हुए भाजपा को स्वत: यह सीट झामुमो के लिये छोड़ देनी चाहिए. कुल मिलाकर अभी राज्य की राजनीति पूरी तरह जमशेदपुर सीट पर केंद्रित हो गई है.

हालांकि यह रस्साकशी समय के काफ़ी पहले शुरू हो गई है. अभी अर्जुन मुंडा के इस्तीफ़ा देने के बाद उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी. चुनाव आयोग इसकी तिथि तय करेगा. नोटिफिकेशन होगा. इसके बाद उम्मीदवारी की बात आएगी, लेकिन अभी से जो राजनीतिक फ़िज़ा बन रही है वह दोनों ही गठबंधनों के अंदर दरार पड़ने का संकेत दे रही है. चुनाव तक यह कोई भी रूप धारण कर सकती है. बहरहाल, गठबंधन धर्म का निर्वाह करना यूपीए और एनडीए दोनों के लिए कठिन होता जा रहा है.

feedback@chauthiduniya.com

निबंधन कार्यालय में भ्रष्टाचार

राजेश सिन्हा

खगड़िया ज़िला के निबंधन कार्यालय लूट का अड्डा बनकर रह गया है. हालत यह है कि दिन के उजाले में सरकारी कर्मी भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहा रहे हैं. रात के अंधेरे में कार्यालय परिसर में आसपास के होटल संचालकों द्वारा जिस्म का व्यापार कराया जाता है. हालांकि कोई खुले तौर पर स्वीकार नहीं करता. अगर मामले की उच्चस्तरीय जांच हो तो यह प्रमाणित हो जाएगा कि सरकारी कर्मियों तथा अन्य की मिलीभगत से सरकार को न केवल प्रतिदिन लाखों रुपये के राजस्व का चूना लगाया जा रहा है, बल्कि ज़मीन क्रेताओं को विभिन्न ख़र्च के नाम पर अवैध तरीक़े से लूटा भी जा रहा है. एक तरफ़ राज्य सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार तथा भूमि विवाद पर नियंत्रण पाने के लिए कई तरह की नीतियां बनाई जा रही हैं, वहीं निबंधन कार्यालय में कार्यरत सरकारी और ग़ैरसरकारी कर्मियों द्वारा भूमि विवाद की पृष्ठभूमि तैयार करते हुए भ्रष्टाचार को चरम पर पहुंचाया जा रहा है. इसी मामले में पहले तत्कालीन ज़िला निबंधन पदाधिकारी अशोक कुमार मौर्य को इसी वर्ष राजस्व को क्षति पहुंचाने तथा पब्लिक से राशि वसूलने के आरोप में निलंबित किया जा चुका है. ज़िला निबंधन कार्यालय में चल रहे अवैध कारोबार की जानकारी मिलने के बाद चौथी दुनिया के द्वारा लगभग एक सप्ताह से स्थिति पर नज़र रखी जा रही थी. तभी यह तथ्य सामने आया कि तत्कालीन ज़िला निबंधन पदाधिकारियों के ज़माने में बाबुओं की बनाई गई लूट नीति के कारण ज़मीन को औने-पौने दामों में ख़रीदा बेचा जा रहा है. जयप्रकाश नगर की एक महिला ने बताया कि वह बीते दिनों मारड़ मौजे के तीन कट्ठे साढ़े चार धुर ज़मीन का निबंधन कराने निबंधन कार्यालय गई थी. मुंशी के द्वारा निबंधन के एवज में दस हज़ार रुपये की मांग की गई. स्टांप पेपर पर निबंधननामा तैयार होने के बाद उससे कहा गया कि साहब आज नहीं आ सकेंगे. दूसरे दिन कहा गया कि आज भी साहब नहीं आ सकेंगे, लेकिन अगर आज ही ज़मीन का निबंधन कराना है तो अर्जेंट के नाम पर पांच सौ रुपये देने होंगे. इसके बाद फ़ोटो और हस्ताक्षर के नाम पर भी उससे रुपये लिए गए. इसके एवज में रसीद मांगी गई तो सरकारी कर्मियों का कहना था कि घूस के एवज में रसीद दी जाती है क्या!

अब ज़रा एक ही ज़मीन मालिक द्वारा एक ही ज़मीन को तीन-तीन लोगों के हाथों बेचकर भूमि विवाद की पृष्ठभूमि तैयार किए जाने की स्थिति पर नज़र डालते हैं. प्रभारी ज़िला निबंधन पदाधिकारी की कार्यव्यस्तता का फ़ायदा उठाकर निबंधन कार्यालय के कर्मियों द्वारा काग़ज़ात चेकिंग के नाम पर मोटी रक़म उठाने के बाद काग़ज़ात को सही क़रार देते हुए प्रभारी निबंधन पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं. बाद में ज़मीन ख़रीदने वालों के बीच विवाद छिड़ जाता है और पुलिस को नाहक़ परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

बताया जाता है कि उपसमाहर्ता सह वर्तमान प्रभारी ज़िला निबंधन पदाधिकारी ने कार्यव्यस्तता के कारण फ़िलवक्त मो. अनवर को निबंधन कार्यालय का इंचार्ज बना रखा है. तथाकथित कार्यालय इंचार्ज, वरीय लिपिक तथा कंप्यूटर ऑपरेटर की मिलीभगत से कई ग़ैरक़ानूनी कार्यों को अंजाम देना चर्चा का विषय बना हुआ है. एक मुंशी ने बताया कि अगर ज़िला निबंधन कार्यालय में किसी जांच टीम के द्वारा नज़र रखी जाए तो कई गोलमाल के मामले सामने आएंगे. विभिन्न होटल संचालकों और सक्रिय दलालों के द्वारा ज़मीन के ख़रीददार को लूटने के लिए अलग नीति तय कर दी गई है. इसके लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल कर ज़मीन ख़रीदने वालों को जमकर चूना लगाया जाता है. बहरहाल, इस तरह के गोरखधंधे पर सख्ती के साथ अंकुश लगाया जा सकेगा या प्रशासन के द्वारा गोरखधंधे में शामिल लोगों पर हाथ डाला जाएगा, यह कहना तो शायद अभी लाज़िमी नहीं है, लेकिन सदर आरक्षी उपाधीक्षक मनोज कुमार तिवारी यह ज़रूर कहते हैं कि इस तरह के मामलों से पुलिस अवगत नहीं है. अगर शिकायत मिली तो दोषी लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

feedback@chauthiduniya.com

विधायक राजकिशोर केसरी हत्याकांड की जांच को लेकर सीबीआई काफी सतर्क दिख रही है. जांच में रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं, देखना होगा कि सीबीआई कब इसकी तह तक पहुंचेगी.

केसरी हत्याकांड
सीबीआई की डगर आसान नहीं

नीरज कुमार सिंह

विधायक राजकिशोर केसरी हत्याकांड की जांच के लिए सीबीआई की टीम पूर्णिया में पसीना बहा रही है. नित्य हो रहे नए ख़ुलासों से इस कांड की जांच सीबीआई के लिए कड़ी चुनौती बनती जा रही है. बिहार का पूर्णिया एकमात्र प्रमंडलीय शहर है, जहां सीबीआई की टीम तीसरी बार पहुंची है. इससे पहले पूर्व विधायक अजीत सरकार हत्याकांड व बूटन सिंह हत्याकांड में सीबीआई पूर्णिया पहुंच चुकी है. अजित सरकार हत्याकांड में सीबीआई की उपलब्धि कुछ ख़ास नहीं रही. वहीं बूटन सिंह हत्याकांड में डिंपल मेहता की हत्या हो जाने के कारण इस अध्याय को सीबीआई को बंद कर देना पड़ा था. मालूम हो कि विधायक राजकिशोर केसरी हत्याकांड की जांच व हत्या के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए डीएसपी स्तर के अधिकारी बीबी भट्अ के नेतृत्व में छह सदस्यीय सीबीआई की टीम 25 फ़रवरी को पूर्णिया पहुंची है. मिली जानकारी के अनुसार जांच से संबंधित रणनीति, मेपिंग बनाने के उपरांत 27 फ़रवरी को सुबह लगभग साढ़े दस बजे सीबीआई की टीम सबसे पहले पूर्णिया के चूनापुर रोड स्थित विधायक राजकिशोर केसरी के आवास पर पहुंची. हत्या स्थल पर सीबीआई की टीम ने उस जगह का मुआयना किया, जहां ख़ून से सनी मिट्टी को ढककर रखा गया था व जहां विधायक गिरे थे. विधायक के भतीजे सुदीप केसरी का बयान भी टीम के सदस्यों ने लिया. आवास में विधायक की पत्नी किरण केसरी, पुत्र एवं सरकारी अंगरक्षक दिनेश साह से भी जानकारी मिली. ये सब घटना के वक़्त घटना स्थल पर मौजूद थे. 28 फ़रवरी को सीबीआई टीम ने सदर अस्पताल के उन चिकित्सकों से जानकारी हासिल की जो केसरी के पोस्टमार्टम एवं इलाज में लगे थे. सीबीआई को इस बात की जानकारी हाथ लगने की उम्मीद है कि विधायक ने रास्ते में दम तोड़ा था या इलाज के दौरान. वहीं रूपम पाठक की मनोस्थिति की भी जानकारी मिल सकती है, क्योंकि रूपम का इलाज भी सदर अस्पताल के चिकित्सकों की टीम कर रही थी. जेल में बंद नवलेश पाठक की पत्नी रमा पाठक का बयान भी सीबीआई ने लिया. पूर्व में रमा पाठक रूपम के विद्यालय राजहंस पब्लिक स्कूल की शिक्षिका थी और रामा पाठक ने मीडिया को दिए बयान में नवलेश की हत्या होने की आशंका ज़ाहिर की थी. उसने इस घटना से जुड़ी कई जानकारियां अपने पति के पास होने की जानकारी दी थी और सीडी कैसेट का ज़िक्र किया था. लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आख़िर नवलेश के पास कौन-सी अहम जानकारी है और उस घटना में इनका क्या रोल रहा है. राजहंस पब्लिक स्कूल स्थल, स्कूल वैन से जहां सीबीआई हत्या की कड़ी को तलाश करेगी, वहीं पुलिस रूपम पाठक की निजी मारूति वैन चालक की गिरफ्तारी अब तक नहीं कर पाई है. वह भी इस घटना की महत्वपूर्ण कड़ी है. जैसा कि स्थानीय लोगों का कहना था कि रूपम विद्यालय की वैन में सवार होकर 4 जनवरी को विधायक आवास पहुंचा थी. घटना के समय रूपम के पर्स से मिले समान आदि से भी सीबीआई अहम सुराग की तलाश करेगी, वहीं यौन शोषण का मुक़दमा दर्ज कराना एवं उसे पुन: वापस लेने के कारणों की जांच सीबीआई ज़रूर करेगी.

अब तक की जानकारी के अनुसार यौन शोषण केस के एक अन्य आरोपी विधायक के निजी सचिव विपिन राय से भी पूछताछ होगी, हालांकि, यह मामला स्थानीय पुलिस की जांच में निराधार साबित हो चुका है. रूपम पाठक द्वारा बार-बार बयान बदलने से सीबीआई जांच में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं. ग़ौरतलब है कि रूपम ने हाल ही में बयान दिया था कि किसी के बहकावे में आकर उसने इस घटना को अंजाम दिया था. वह इस घटना को अंजाम देने में सक्षम नहीं थी. अत: सीबीआई की मुख्य चुनौती साजिशकर्ता के चेहरे को बेनक़ाब बरने की होगी. सारे घटनाक्रमों और पेचीदगियों को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि इस कांड में सीबीआई की राह आसान नहीं होगी.

रूपम पाठक | रमा पाठक

feedback@chauthiduniya.com

पंचायत चुनाव की सरगर्मी दिखने लगी

विकास कुमार

लोकतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत आम जनता पर शासन करने की सबसे छोटी एवं निचली इकाई पंचायती राज व्यवस्था चुनाव का बिगुल बज गया है. ज़िले के बीस प्रखंडों के 381 पंचायत एवं 51 जिला परिषद क्षेत्रों में चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई है. ज़िला परिषद की पूर्व अध्यक्ष एवं रोसड़ा की भाजपा विधायक मंजू हज़ारी की भरपाई आगामी ज़िला परिषद के गठन में हो, इसके लिए मंजू हज़ारी के देवर सह जदयू सांसद महेश्वर हज़ारी एवं उनके विधायक पिता रामसेवक हज़ारी के समर्थकों ने वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र के ज़िला परिषद क्षेत्रों में चहलक़दमी शुरू कर दी है. चर्चा गर्म है कि आगामी ज़िला परिषद के बोर्ड गठन में अध्यक्ष पद पर पारिवारिक पकड़ एवं प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए सांसद अपने किसी परिजन को चुनाव मैदान में ला सकते हैं. यदि ऐसा हुआ तो वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व लोजपा विधायक विश्वनाथ पासवान की पत्नी भी उसी क्षेत्र से खड़ी होंगी, जहां से उनके प्रतिद्वंद्वी रहे महेश्वर हज़ारी के परिजन चुनाव लड़ेंगे. विदित हो कि गत लोकसभा चुनाव में जदयू सांसद महेश्वर हज़ारी ने लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान के अनुज एवं दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र पासवान को क़रारी शिकस्त दी थी. उसकी कसक आज भी पासवान बंधुओं एवं लोजपा समर्थकों के दिल में है.

ज़िले के सभी 20 प्रखंडो में पंचायत चुनाव की सरगर्मी बढ़ने लगी है. नामांकन के पहले ही संभावित प्रत्याशी मतदाताओं की नब्ज़ टटोलने में जुट गए हैं. फ़िलहाल पांच प्रखंडों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें अबतक 1346 प्रत्याशी चुनावी दंगल में कूद पड़े हैं. शाहपुर पटोरी अनुमंडल के तीन प्रखंडों में 1148 अभ्यर्थियों ने नामजदगी के परचे भरे. पटोरी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के लिए 425 उम्मीदवारों ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन दाख़िल किया. मुखिया पद के लिए 83, पंचायत समिति सदस्य, पंसस के लिए 66, सरपंच के लिए 29, पंच के लिए 71, वार्ड सदस्य के लिए 176 लोगों ने नामजदगी के परचे भरे. मोहनपुर प्रखंड में 231 उम्मीदवारों ने परचे दाख़िल किए. मोहिउद्दीननगर प्रखंड मुख्यालय पर मुखिया पद के लिए 71, पंसस के लिए 60, सरपंच के लिए 33, पंच के लिए 86 एवं वार्ड सदस्य के लिए 208 लोगों ने नामांकन किया. यहां से नामांकन करने वाले प्रमुख एवं चर्चित लोगों में ज़िला परिषद उपाध्यक्ष सुनीता सिंह, पटोरी की पूर्व प्रखंड प्रमुख आरती सिंह एवं निवर्तमान मुखिया प्रियंका सुमन एवं राजकुमार अकेला के नाम शामिल हैं. हसनपुर प्रखंड में मुखिया पद के लिए 17 पुरुष एवं 12 महिलाओं ने नामज़दगी के परचे भरे. पंसस के लिए 11 महिला एवं 25 पुरुष, सरपंच पद के लिए 7 पुरुष, वार्ड सदस्य पद के लिए 19 महिला एवं 19 पुरुष तथा पंच पद के लिए 2 पुरुष एवं 1 महिला ने नामांकन का परचा दाख़िल किया. बिथान प्रखंड में मुखिया पद के लिए 16, पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 16, सरपंच के लिए 4, पंच के लिए 5 एवं वार्ड सदस्य के लिए 37 लोगों ने नामांकन पत्र दाख़िल किया. बिथान की निवर्तमान प्रखंड प्रमुख विभा देवी के पति एवं आपराधिक सरगना अशोक यादव ने दो-दो पंचायत समिति क्षेत्र से नामांकन दाख़िल किया. साथ ही उनके भाई वीरेन्द्र यादव ने भी नरपा पंचायत से नामज़गदी के परचे भरे. हसनपुर के जदयू विधायक राजकुमार राय की पत्नी एवं बेलसंडी पंचायत की निवर्तमान मुखिया पुष्पलता देवी ने एक बार फिर से मुखिया पद के लिए नामांकन दाख़िल किया है.

अनीता देवी | सुनीता सिंह | विभा देवी | विश्वनाथ पासवान | पवन कुमार यादव

feedback@chauthiduniya.com

हम मकान नहीं घर बनाते हैं...
Yash Raj Enterprises Pvt. Ltd.
excellence in Real Estate...
An ISO 9001:2008 Certified Company
● PROMOTER ● DEVELOPER
● MARKETER ● SERVICE PROVIDER
9234601786, 9234602786, 9234603786
E-mail: yashraj221@gmail.com
Website : www.yashrajenterprises.com

एक नज़र

हिंदू परिवार मस्जिद की देखरेख कर रहा है

इक़बाल ने ठीक ही कहा है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना..... आप यह सोच कर हैरान होंगे की राजधानी पटना से सटे बेउर जेल से पूरब नथूपुर गांव में एक मस्जिद की देखरेख हिंदू परिवार कर रहा है. यहां एक भी मुस्लिम जाति के लोगों का बसेरा नहीं है, बावजूद इसके यहां मस्जिद व मंदिर दोनों हैं. इस मस्जिद को आप अगर देखेंगे तो लगेगा की यह मस्जिद अभी साल दो साल पहले ही बनी है. ग्रामीण किताब राय बताते हैं कि आज से लगभग सौ साल पहले यहां मुस्लिमों का निवास था, लेकिन देश की आज़ादी के साथ ही यहां के मुस्लिम पाकिस्तान, बांग्लादेश व देश के अन्य हिस्सों में चले गए. तब से लेकर आज तक फिर कोई उनका वंशज यहां नहीं आया. वे लोग जाते-जाते अपनी ज़मीन हमारे पूर्वजों को बेच गए. गांव के ही विनय राय नेताओं पर चुटकी लेते हुए कहते हैं कि मेरे गांव में कुर्सी या सत्ता का लालच नहीं है न ही जातिवाद के झूठे वादे करके आम जनता को गुमराह किया जाता है. -देवेंद्र कुमार दुबे

राशि मिलने के बावजूद विकास नहीं

मधुबनी के उच्च विद्यालय को प्लस टू का दर्जा मिलने के दो वर्ष बीत जाने एवं पर्याप्त राशि होने के बावजूद सीता मुरलीधर उच्च विधालय बदहाली के दौर से गुज़र रहा है. बेनीपट्टी प्रखंड के बसैठ गांव में वर्ष 1951 में सीता मुरलीधर उच्च विद्यालय की स्थापना हुई थी. इस विद्यालय में 650 छात्र-छात्राएं और सात शिक्षक हैं. यहां के चार कमरों में पढ़ाई होती है. 13 कमरे पूरी तरह जर्जर और क्षतिग्रस्त हो चुके हैं. इस स्कूल के लिए चार एकड़ ज़मीन है, लेकिन फिर भी भवन का भारी अभाव है. स्कूल के भवन निर्माण के लिए 39 लाख 50 हज़ार रूपए की राशि उपलब्ध कराई गई है, लेकिन फिर भी यह हालत है. प्रभारी प्रधानाध्यापिका गजाला आसमी ने बताया कि बैंक में जमा राशि के खाता स्थानांतरण के लिए डीईओ को लिखा गया है.

मंदिर के पास कूड़े का अंबार

मधुबनी के महंथीलाल चौक स्थित प्राचीन राम मंदिर के चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है. मंदिर के मुख्य द्वार के समीप नाले में गंदगी भरी पड़ी है. इस संदर्भ में व्यापारी गोपाल प्रसाद, शंभू कारक आदि लोगों ने बताया कि नगर परिषद के सफ़ाईकर्मियों को मंदिर के समीप नाले की नियमित रूप से सफ़ाई करनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है.

राजेंद्र बाल उद्यान सुंदर होगा : डीएम

मोतिहारी ज़िलाधिकारी अभिजीत सिन्हा ने कहा है कि रमणीक मोतीझील के किनारे अवस्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद बाल उद्यान को और अधिक सुंदर बनाया जाएगा. फ़िलहाल वह ज़िले के बारे में जानकारी ले रहे हैं ताकि विकास की संभावनाओं को तलाशा जा सके. वह डॉ. राजेंद्र प्रसाद सेवा संस्थान द्वारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की 48वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. कार्यक्रम का संचालन संस्था के संस्थापक ई. रमेश प्रसाद वर्मा ने किया. मौके पर विजय सिन्हा,रंजन शर्मा,आलोक कुमार, रंजन वर्मा, जावेद अंसारी आदि उपस्थित थे.

नगर परिषद में 24 करोड़ 15 लाख का बजट पास

मोतिहारी के नगर परिषद के सभागार में विशेष बैठक सभापति प्रकाश अस्थान की अध्यक्षता में संपन्न हुई. 2011-12 का बजट मौजूद सदस्यों के विचार-विमर्श के बाद 24 करोड़ 14 लाख 91 हज़ार रुपये का पेश किया गया. यह बजट 30 लाख 97 हज़ार रुपये के घाटे का बजट रहा है. बैठक के दौरान सदन में नगर परिषद के सभी संसाधनों से प्राप्त राशि के रूप में कुल 23 करोड़ 83 लाख 93 हज़ार 9 सौ 33 रुपये दिखाए गए. बजट पास होने के बाद 13वें वित्त आयोग के तहत शहर को सुंदर बनाने के लिए जगह-जगह स्ट्रीट लाइट लगाने का सुझाव सदन में मौजूद वॉर्ड आयुक्तों ने दिया. वहीं ज़िले व राज्य में अवार्ड व मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को नप प्रशासन द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा. बैठक में इप सभापति राजकुमारी गुप्ता, कार्यपालक पदाधिकारी राजेन्द्र मंडल, कुमुद कुमारी श्रीवास्तव, भोला ठाकुर, शैल देवी, पूनम देवी आदि मौजूद थे.

पीएम व सीएम से मिलकर रणनीति तय होगी

मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर स्थानीय एलएनडी कॉलेज में मीडिया ग्रुप के तत्वावधान में सदस्यों की एक बैठक हुई. इस बैठक में निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का आग्रह किया जाएगा. अगर इसमें कोई अवरोध दिखाई दिया तो आंदोलनात्मक कार्रवाई की जाएगी. बैठक की अध्यक्षता पूर्व विधायक रामाश्रय प्रसाद सिंह ने की. इस मौक़े पर पूर्व विधायक सुरेश कुमार मिश्रा, चंद्रभूषण पांडेय, जदयू नेता राय सुंदरदेव शर्मा, राकेश कुमार, विनोद कुमार, मंकेश्वर सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे.

वाहन चालकों को ट्रैफ़िक नियम बताए

मुजफ़्फ़रपुर शहर को जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन ने ज़ोरदार पहल की है. सिटी एएसपी विकास बर्मन ने स्वयं उस समय हाथ में डंडा उठा लिया जब वह ट्रेफिक पोस्टों का जायज़ा लेने निकल पड़े थे. उस दौरान सरैयागंज टावर समेत कई जगहों पर वाहन चालकों को बेतरतीब होते देखा तो उनके पास पहुंच गए और उन्हें ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाया. बर्मन ने इन पोस्टों पर तैनात कर्मियों को भी कई दिशा-निर्देश दिए. उनके साथ क़ाज़ी मुहम्मदपुर व इंस्पेक्टर बालेश्वर प्रसाद भी थे. -चौथी दुनिया ब्यूरो

छात्रों को बेहतर शिक्षा देना ही मक़सद है

आग से होने वाली तबाही को रोकने के लिए पटना स्थित फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट स्कूल छात्रों को बेहतर तरीक़े से तैयार कर रहा है. फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के निदेशक ललन कुमार प्रसाद ने बताया कि बिहार व झारखंड का यह पहला संस्थान है. इस संस्थान में कम ख़र्च पर छात्रों को अच्छी शिक्षा दी जाती है. यह कोर्स करने के बाद छात्रों को आसानी से नौकरी मिलती है. -अनुमेहा झा

A. KUMAR WISHES YOU A HAPPY HOLI
Join EXPERT BANK COACHING
For BANK, RLY, SSC, AIR FORCE, NAVY, ARMY
Join MODERN STUDY CENTRE
For English Classes (XI, XII, Spoken & Competitive)
VENUE-KASHIPUR, SAMASTIPUR
A.KUMAR CHAIRMAN CUM FACULTY: ENGLISH